

प्रापिकार ने प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

d. 491

नई विस्ती, सनिवार विसम्बर 4, 1982//अग्रहायण 13, 1804

No. 49)

NEW DELHI, SATURDAN DECEMBER 4, 1982/AGRAHAYANA 13, 1904

इस क्रांग में भिन्न पृष्ठ संस्था दी जाती है जिससें कि यह अलग संकलन के कप में एका जा सकें Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—**क्षत्र** 3—श्रप-क्षत्र (ii)

PART II-Section 3-Sub-section (il)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सार्विधक आवेश और आधसूचनाइ Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

गह मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 1982

का॰ आ॰ 3975.—केन्डीय सरकार, विल्ली विशेष पुलिस स्थापन सिक्षिनयम, 1946 (1946 का 25) की घारा 3 हारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए निस्तिलिखन अपराधों की, ऐसे अपराध पंचित करती है, जिनका अन्येषण विल्ली विशेष पुलिस स्थापन द्वारा किया जाएगा, सर्थात् :---

- (क) भारतीय दंड संहिता, 1860 (1960 वा 45) की धारा 367 के अर्धान देवनीय धपराध
- (ख) खड़ (क) में विणित प्रपराधों में से एक या एक से श्रविक प्रपराधों के सबंध में या उनसे संबंधित प्रयत्न, दृष्प्रेरणाएं और पश्यंत भौर इन्हीं तथ्यों से उद्भूत उमी संव्यवहार के दौरान किया गया श्रन्थ कोई भगराध।

[संख्या | 128/6/82/ए०विं(०४(०-11) एच० कं० वर्मा, उप मचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel and Administrative Reforms)
New Delhi, the 17th November, 1982

S.O. 3975.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25

of 1946), the Central Government hereby specifies the following offences as the offences which are to be investigated by the Delhi Special Police Establishment, namely:—

- (a) Offences punishable under section 367 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860); and
- (b) attempts, abetments and conspiracies in relation to, or in connection with, one or more of the offences mentioned in clause (4) and any other offence committed in the course of the same transection arising out of the same facts

[No. 228/6/82-AVD-II] H. K. VERMA, Under Secy.

नुदास जांच आयोग

गोधी णानि प्रतिष्ठान ग्वं ग्रम्य संगठनों के बारे से संगोबन

नई विरुली, 25 नवम्बर, 1982

कारुआर 3976.—इस धार्यांग की कार्यविधि को विनियमित करने वासे आदेश के पैरा 3 की, जिसे तारीख 26 जुलाई, 1982 की मिश्रमूचना सं 1/1/82-के क्रीं उपाई० के नहन जारी किया गया था, इस प्रकार पढ़ा जाये :—

'कार्यालय का पता 3 22-11-1982 में, सनले मादेशों तक, इस भायोग का मुख्यालय कमरा नं ● 13, "सी" विंग, दूसरी मजिल, लांक नायक भवन, नजदीक स्वान मार्कीट, नई विल्ली-110003 में होगा भीर जब सक पते में कोई परिवर्तन अधिम् जिल न किया जाए तब सक सभी पत्रावि सिचन, कुवास जोन आयोग — गांधी गांति प्रतिष्ठान एवं श्रुव्य संगठमों के बारे में — कमरा नं 21, "सी" विंग, दूसरी मंजिल, लोक नायक भवन, नजबीक खान मार्कीट, नई विल्ली-110003 के पते पर भेजे जांरें।"

भागोग के भादेश स।

[सं॰ 1/1/82-के॰सी॰माई॰] को॰ एम०के॰ मदद, सचिव

Kudal Commission of Inquiry on Gandhi Peace Foundation and other Organisations

AMENDMENT

New Delhi, the 25th November, 1982

S.O. 3976.—Para 3 of the Order regulating the procedure of this Commission issued vide Notification No. 1/1/82-KCI dated the 26th July, 1982 may be read as under:—

"Official Address.—3 Until further orders, the Head-quarters of the Commission will be at Room No. 13, 'C' Wing, IInd Floor, Lok Nayak Bhavan, Near Khan Market, New Delhi-110003, with effect from 22-11-1982 and all communications should be addressed to the Secretary to the Kudal Commission of Inquiry on Gandhi Peace Foundation and other Organisations, Room No. 21, 'C' Wing, IInd Floor, Lok Nayak Bhavan, Near Khan Market, New Delhi-110003, till a change in address is notified."

[No. 1/1/82-KCI] B. M. K. MATTO, Secy.

विस संत्रालय

(राजस्य विमाग्)

नई दिल्ली, 23 मप्रैल, 1982

म्राय-कर

का॰ आ॰ 3977.— सर्वसाधारण की जानकारी के लिए मिं मूर्वित्ति किया जाता है कि विहित प्राधिकार, अर्थात विज्ञान भीर प्रौद्योगिक विभाग नई दिल्ला से निम्नलिखित संस्था को प्रायकर नियम, 1962 के नियम 6 के संध्य पठिंत ग्रायकर प्रधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए मन्य प्राकृतिक भीर भनुप्रयुक्त थिज्ञान के क्षेत्र में "संगम" प्रयमं के मर्छन निम्नलिखित शतौं पर मनु-मोदित किया है अर्थात् :—

- (i) यह कि जैन वैज्ञानिक अनुसंघान धीर विकास प्रतिष्टान, नई विरूपः कृषि/पशुपालन/मात्स्यकी और भौषिध से भिन्न प्राकृतिक और अनुप्रयुक्त विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंघान के लिए प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।
- (ii) उक्त संगम अपने वैज्ञानिक अनुमंद्रान संबंधी कियाकलागें। की वार्षिक विवरणी विहिन प्राधिकारी की प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररूपों में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किए जाएं और उसे सुचित किए जाएं।
- (iii) उक्त प्रतिष्ठान वार्षिक विवरणी ग्रीर लेखाओं का वार्षिक विवरण प्रतिवर्ष ग्रायकर ग्रायुक्त को ग्रेजेगा।

संस्था

जैन वैक्रानिक अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान, नई विल्ली यह अधि-सूचना 26-12-1981 से 25-12-1983 तक वो वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है।

> [सं॰ 4582/का॰ सं॰ 203/193/80-माई टी ए(II)] भवन गोयल, प्रवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)
New Delhi, the 23rd April, 1982
INCOME TAX

- S.O. 3977.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Department of Science and Technology, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of subsection (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Inome-tax Rules, 1962 under the category of "Association" in the area of other natural and applied sciences subject to the following conditions:—
 - (1) That the Jain Foundation for Scientific Research and Development, New Delhi will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research in the field of natural and applied sciences other than Agricultural/Animal husbandry/Fisheries and medicines.
 - (ii) That the said Association will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimate to them for this purpose by 30th April each year.
 - (iii) That the said Foundation will submit the Armual returns and statement of Accounts to the Commissioner of Income-tax for every year.

INSTITUTION

Jain Foundation for Scientific Research and Development, New Delhi.

This notification i_8 effective for a period of two years from 26-12-1981 to 25-12-1983.

[No. 4582/F. No. 203/193/80-ITA (ii)]
M. G. C. GOYAL, Under Secy.

नई दिल्ली, 1 जून, 1982

क्ष विकर

का० आ० 3978.—मायक्तर मधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (44) के उपखंड (iii) के अमुसरण में और मारत सरकार केराजस्व विभाग की विनांक 3-5-80 की मधिसूचना सं 3280 का अधिलंबन करते हुए, केम्ब्रीय सरकार एनद्दार। श्री एस० सी० गुप्त-II को, जो केन्द्रीय सरकार एनद्दार। श्री एस० सी० गुप्त-II को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपवित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अधीन कर वसूली अधिकारी की गवितयों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है।

यह भिधिसूचना श्री एस॰ सी गुग्त-II द्वारा कर वसूली अधिकारी
 के रूप में कार्नभार ग्रहण करने की सार्रक्ष से लागू होगी।

[सं॰ 4650 (फा॰ सं॰ 398/14/81-मा॰ क॰ द॰ (खंड 1)]

New Delhi, the 1st June, 1982 INCOME TAX

S.O. 3978.—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and in supersession of Notification of the Government of India in the Department of Revenue No. 3280 (F. No. 398/3/80-ITB) dated 3-5-80, the Central Government hereby authorises Shri S. C. Gupta-II being a gazetted Officer of the Central Government, to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

2. This Notification shall come into force with effect from the date Shri S. C. Gupta-II takes over charge as Tax Recovery Officer.

[No. 4650/F. No. 398/14/81-ITB (Pt. I)]

नई दिस्ली, 3 जून, 1982

माय-कर

का० आ० 3979.—मायकर घिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (44) के उपखंड (iii) के धानुसरण में धौर भारत सरकार के राजस्व विभाग की दिनाक 30-6-80 की घिसूचना सं० 3498 (फा० सं० 398/15/80-आ० क० स० क०) का घिष्ठंचन करते हुए केन्द्रीय सरकार एतनुदारा, श्री ए० ग्रार० पिपलबार को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपन्नित मिकारी है, उक्त अधिनियम के ग्रंतर्गत कर वसूली मिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करनी है।

 यह मिश्रियना, श्री ए० घार० पिम्पलवार द्वारा कर बसूली मिश्र-कारी के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से लागू होगी।

[संव 4658/ फा० संव 398/5/82-मा० क० सव]

New Delhi, the 3rd June, 1982

INCOME TAX

- S.O. 3979.—In pursuance of sub-clause (ili) of clause (44) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and in pursuance of Notification of the Government of India in the Department of Revenue No. 3498 (F. No. 398/15/80-ITCC) dated 30-6-80, the Central Government hereby authorises Shrl A. R. Pimpalwar, being a gazetted Officer of the Central Government, to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.
- 2. This Notification shall come into force with effect from the date Shri A. R. Pimpalwar takes over charge as Tax Recovery Officer.

[No. 4658/F. No. 398/5/82-ITB]

ग्राय-कर

कांश्वां 3980 --- मायकर मधिनियम, 1961 (1961 का 13) की धारा 2 के खंड (44) के उप-खंड (iii) के अनुसरण में और भारत सरकार के राजस्व विभाग की दिनांक 30-6-81 की धिस्चना सं० 4066 (फा० सं० 398/20/81-मा० कंस० क०) का घिलंघन करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतंबुहारा भी डी० घार० मन्दा को जो केन्द्रीय सरकार के राजपित प्रधिक री हैं, उक्त घिनियम के धन्तर्गत कर वसूनी घिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है।

यह प्रधिसूचना श्री डी॰ ग्रार० नग्दा द्वारा कर बसूनी प्रधिकारी
 के पद का कार्यभार ग्रहण करने की तल्दीख से लागू होगी।

[सं० 4660/फा॰ सं० 398/25/82-मा० क० व०]

INCOME TAX

- S.O. 3980.—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and in supersession of Notification of the Government of India in the Department of Revenue No. 4066 (F. No. 398/20/81-ITCC) dated 30-6-81, the Central Government hereby authorises Shri D. R. Nanda, being a gazetted Officer of the Central Government, to exercise the powers of a Tax Recovery officer under the sald Act.
- 2. This Notification shall come into force with effect from the date Shri D. R. Nanda takes over charge as Tax Recovery Officer.

[No. 4660/F. No. 398/25/82-ITB]

ग्राय-कर

की बार 2 के सांव (44) के उपखंब (iii) के धनुसरण में तथा मारत

सरकार के राजस्व विधाग की दिनांक 30-6-79 की कि सूचना मंड्या 2918 (फा० सं० 404/134/का० व० घ० उड़ सा/79-प्र०क० स० क०) को मिलकारत करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री एन० पी० रामाराज को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपित मिलकारी है, उसते भीवनियम के अन्तर्गत कर वसूसी मिलकारी की शिवनयों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकत करती है।

 यह ग्रधिसूचना श्री एन० पी० रामाराव द्वारा कर वसूर्व श्रधि-कारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किए जाने की तारंख से लागू होता.

[सं० 4662/ फा॰ सं० 398/21/82-ग्रा० क॰ व॰]

INCOME TAX

- S.O. 3981.—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in supersession of Notification of the Government of India in the Department of Revenue No. 2918 (F. No. 404/134/TRO-Orissa/79-ITCC) dated 30-6-79, the Central Government hereby authorises Shri N. P. Rama Rao, being a gazetted Officer of the Central Government, to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.
- 2. This Notification shall come into force with effect from the date Shri N. P. Rama Rao takes over charge as Tax Recovery Officer.

[No. 4662/F. No. 398/21/82-ITB]

नई विल्पा, 18 जून, 1982

ग्राय-कर

का० औ० 3982.— प्रायकर प्रधित्यम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (44) के उप खंड (iii) के प्रतुसरण में भीर भारत सरकार के राजस्व विभाग की विताल 16 1 80 की प्रधिसूचना सं० 3133 (का० सं० 40 4/22/क० व० भ्र०-प० बं०/79-प्रा० क० स० क०) का भिक्षंच करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतथ्डारा श्री बो०एस० बिस्वास की, जो केन्द्रीय सरकार के राजपवित भिध्वारी हैं, उनत भिध्तियम के ग्रन्सौत कर वसूनी मधिकारी की णक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती. है।

2- यह प्रशिस्चना, श्री बी० एस० विस्वास द्वारा कर वसूली प्रधिकारी के रूप में कार्यभार प्रहुण किए जाने की तारीख से लागू होगी।

[सं० 4702/फा० सं० 398/19/82-मा० क० व०]

New Delhi the 18th June, 1982 INCOME TAX

- 8.0, 3982.—In exercise of sub-clause (iii) of clause (44) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and in supersession of Notification of the Government of India in the Department of Revenue No. 3133 (F. No. 404/22/TRO-WB/79-ITCC) dated 16-1-80, the Central Government hereby authorises Shri B. S. Biswas, being a gazetted Officer of the Central Government, to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.
- 2. This Notification shall come into force with effect from the date Shri B. S. Biswas takes over charge as Tax Recovery Officer.

[No. 4702/F. No. 398/19/82-ITB]

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 1982

ग्राय-कर

का० आ० 3983.—- आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की आरा 2 के खंड (44) के उप खंड (iii) के अनुसरण में और भारत सरकार के राजस्व विभाग की दिनांक 3-5-80 की अधिसूचना सं० 3276 (फा० सं० 398/3/80-आ० क० स० क०) का अधिलंधन करते हुए, केन्नीय सरकार एतद्वारा श्री राजेंड प्रसाद को, जो केन्नीय सरकार के राजपतित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अंतर्गत कर वसूली अधिकारी की गरितयों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करती है।

 यह मिम्पूचना, श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा कर वसूली श्रिषकारी क क्य मे कार्यमार प्रहण किए जाने की तारीख से लागू होगी।

> [स॰ 4791 /फा॰ सं॰ 398/11/81-घा० म॰ ध॰] एन॰ घे॰ मनल धनर सन्तिव

New Delhi, the 12th July, 1982 INCOME TAX

- S.O. 3983—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and in supersession of Notification of the Government of India in the Department of Revenue No 3276 (F No. 398/3/80-ITCC) dated 3-5-80 the Central Government hereby authorises Shri Rajinder Prasad, being a gazetted Officer of the Central Government to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act
- 2. This Notification shall come into force with effect from the date Shri Rajindei Prasad takes over chaige as Tax Recovery Officer

[No 4791/F No 398/14/81-ITB] N K SHUKLA, Under Secy

नर्ष फिल्लो, ३१ अगस्त, 1982

ग्राय-कर

कां आ० 3984 — भायकर भिष्तियम 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (44) के उप खंड (11) के म्रुनुसरण में भीर भारत सरकार के राजस्व विभाग की दिनांक 1-6-82 की अधिसूचना स० 4650 (फा॰ सं॰ 398/14/81 भा॰ क॰ ब॰) का अधिलधन करते हुए, कंन्द्रीय सरकार एतव्हारा श्रीमतो सुमति के॰ मेहना को, जो केन्द्रीय सरकार की राजपतिन भिष्कारों हैं, उक्त अधिनयम के भत्नांत कर असूनी अधिकारों की कक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत मर्सा है।

2. यह प्रक्रिस्चना, श्रीमनी मुमति ने० मेहता द्वारः नर बस्कि प्रधि-कारी के कप में कार्यमार ग्रहण किए जाने की तारीख से लागू हांगी!

[स॰ 4.878/फा॰ स॰ 398/14/81-प्रा॰फ॰ब॰]

New Delhi, the 21st August, 1982 INCOME TAX

- 6.0. 3984—In pursuance of sub-clause (m) of clause (44) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and in supersession of Notification of the Government of India in the Department of Revenue No 4650 (F. No. 398/14/81-ITB) dated 1-6-82, the Central Government hereby authorisres 5mt. Sumati K. Mehta, being a gazetted Officer of the Central Government, to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.
- 2. This Notification shall come into force with effect from the date Smt Sumati K Mehta takes over charge as Tax Recovery Officer

[No. 4876/F. No 398/14/81-ITB]

नई दिन्हीं, 13 मितम्बर 1982

भाय-कर

कार कार 3985 -- आयकर प्रधितियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (44) के उपकार (111) के अनुसरण में और मारत सरकार के राजस्य विभाग की विनांक 23-1-79 की अधिसूचना सर 2678 (कार सर 404/22 कर बर्ज्य प्रत्यं प्रिंग के जी कि भीमिक को, जी के कीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधित्यम के असर्त कर कर कर कर की कीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के असर्त कर कर्मी की सिकारी की सिकारी की स्वीत्यों के प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करनी हैं।

2 यह प्रधिसूचना, श्री डी॰ भौमिक द्वारा कर वसूली प्रधिकारी के क्य में कार्यमार प्रहण किए जाने की तारीख से लागू होगी।

[मं॰ 4909 /फा॰ सं॰ 398 19 82-मा॰ **व**॰ ब॰]

New Delhi, the 13th September, 1982 INCOME TAX

- S O. 3985.—In pursuance of sub-clause (in) of clause (44) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and in supersession of Notification of the Government of India in the Department of Revenue No 2678 (F No 404/22/TRO-WB/79-ITCC dated 23 1-79, the Central Government hereby authorises Shri D Bhowmick, being a gazetted Officer of the Central Government, to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act
- 2 This Notification shall come into force with effect from the date Shri D Bhowmick takes over charge as Tax Recovery Officer.

[No 4909/F No 398/19/82-ITB]

नई दिल्ली, 12 श्रन्तवर, 1982

माय-कर

का० आ। 3986 -- मायकर अधितयम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खड़ (44) के उप खंड (111) के अनुसरण में और भारत सरकार के राजस्य विभाग की विनाद 10-8-1982 की प्रधिसूचना स० 4863 (का० स० 398/8/81-अ००० का प्रक्षिलयन करते हुए, केन्द्रीय सरक र एतद्द्रारा श्री बी० एन० के वर्मी को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपीत प्रधिनारी हैं, उपन अधितयम के अंतर्गत कर वसूसी प्रधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है।

्र यह मधिमूचना, थी। घी० एन० के० वर्मा द्वारा कर वसूकी प्रधि-कारों के रूप में नार्यभार ग्रहण किए जाने ती नार्रेख से लागू हार्ग।

> [स॰ 4945/फा॰ सं॰ 398/8/81-म्रा॰ क॰ब॰] मार॰ सी॰ होडा, उप सचिव

New Delhi, the 12th October, 1982 INCOME TAX

- 50. 3986.—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and in supersession of Notification of the Government of India in the Department of Revenue No 4863 (F No 398/8/81-ITB) dated 10-8 82 the Central Government hereby authorises Shri B N K Verma, being a gazetted Officer of the Central Government to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.
- 2 This Notification shall come into force with effect from the date Shri B N K Verma takes over charge as Tax Recovery Officer

[No 4945/F. No 398/8/81-ITB] R. C HANDA, Dy. Secy

नई विस्ती, 25 ग्रगस्त, 1982

भाग-कर

का० आ० 3987 — केन्द्रांय सरकार आय-वर प्रिधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खड़ (V) द्वारा प्रवत्त शिक्तियों का प्रयाग वरते हुए, "श्री पद्मान[म स्वामी मृदिर क्यास को निर्धारण वर्ष 1982-83 से 1984-85 के अतर्गत भाने वाली अविधि के लिए उनत धारा के प्रयोजनार्थ अधिसुनित करती है।

[सं॰ 4878/फा॰ स॰/197/66/8 এ-आ॰व॰ (ए॰ I)]

New Delhi, the 25th August, 1982 INCOME TAX

S.O. 3987—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Sice Padmanabhaswami Temple Trust" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1982-83 to 1984-85

[No 4878/F No 197/66 '82-IT(AJ)]

नई दिस्ली, 31 अगस्न, 1982

ग्राय-कर

का॰ आ॰ 3988 — केन्द्रीय सरकार, श्राय-कर श्रीविनियम, 1961 (1961 का 43) की धारों 10 की उपधारा (23-ग) के खंड (४) द्वारा प्रवक्त शक्तियों का श्रेगींग करने द्वुए, "श्री बाहुबन्ति ब्रह्मचर्यश्रम बाहुबल्ति" को निर्धारण वर्ष 1981-82 भीर 1982-83 के श्रेतर्गंत श्राने वाली श्रवधि के लिए उक्त धारा के श्रेयोजनार्थ श्रीधसूचित करती हैं।

[सं० 4894/फा० सं० 197/30/81-मा०क (ए I)]

New Delhi, the 31st August, 1982 INCOME TAX

S.O. 3988.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Shri Bahubali Brahmacharyashram Bahubali" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1981-82 and 1982-83.

[No. 4894/F. No. 197/30/81-IT(AI)]

म्राय-कर

का॰ आ॰ 3989 .--केलीय सरकार, प्राय-कर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की घारा 10 की उपघारा (23-ग) के खंड (V) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "दि कीप्रियेणन और दि ब्रदर्स और सेकेड हार्ट, पलायम कीटाइ" की निर्धारण वर्ष 1977-78 से 1981-82 के घन्नपंत माने वानी श्रविध के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ श्रीध-सूचित करती है।

[स॰ 4895/फा• सं॰ 197/106/79-धा॰ क (ए र्])]

INCOME TAX

S.O. 3989.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "The Congregation of the Brothers of Sacred Heart, Palayam-kottal" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1977-78 to 1981-82.

[No. 4895/F. No. 197/106/79-IT(AI)]

स्राय-कर

का॰ आ॰ 3990 --- केन्द्रीय सरकार, प्राय-कर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खंड (V) द्वारा प्रवत्त प्रावनियों का प्रयोग करते हुए, "दि सीसाइटी औक प्रावर तेंद्री आंक डोलर्स, वि सर्वेन्ट्स घाँफ मेरी" को निर्धारण वर्ष 1979-80 से 1982-83 के प्रंतर्गत प्राने वाली प्रवधि के लिए उनत धारा के प्रयोजनार्थ प्रविस्थित करती है।

[सं॰ 4897/फा॰ सं॰ 197/195/81/ग्रा॰ क (ए J)]

INCOME TAX

S.O. 3990.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "The Society of Our Lady of Dolours. The Servants of Mary" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1979-80 to 1982-83.

[No. 4897/F. No. 197/195/81-IT(A1)]

ग्राय-कर

का० आ० 3991 ...किन्द्रीय सरकार, प्राय-कर प्रधितियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधार। (23-ग) के खंड (V) द्वारा प्रवस गिवायों का प्रयोग करने हुए, "प्राविद्यायोसेस आफ निर्वेद्रम" की निर्धारण वर्ष 1982-83 के प्रवर्गत आने वाली प्रविधि के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ प्रधिस्चित करती है।

[सं० ४৪९६/फा० सं०/197/85/80-आविकाऽ(एक I)]

INCOME TAX

S.O. 3991.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Archidiocese of Trivandrum" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment year 1982-83.

[No. 4896/F. No. 197/85/80-IT(Al)]

नई दिल्ली, 2 सिलम्बर, 1982

आय-कर

का॰ आ॰ 3992,---केन्द्रीय सरकार, भाय-कर मधिनियम, 1961 (1961 का 43)की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खण्ड (V) द्वारा प्रदस्त शिक्तियों का प्रयोग करने तुए, "कुन्बा कोनम डायोंसेस सोमायटी, कुन्बा, कोनम" को निर्धारण वर्ष 1979-80 मे 1982-83 के भंगम त माने वाली भवधि के लिए उक्त धारा के प्रयोगनार्थ अधिस्थित करती है।

[#o 4900/फा॰सं॰ 197/93/80-प्रा॰कः (ए.I)]

New Delhi, the 2nd September, 1982

INCOME TAX

S.O. 3992.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Kumba Konam Diocese Society, Kumbakonam" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1979-80 to 1982-83.

[No. 4900/F. No. 197/93/80-IT(AI)]

नई विल्लो, 21 सिनम्बर, 1982

आय-कर

का॰ आ॰ 3993 मेर्न्द्राय सरकार, आय-कर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खण्ड (v) द्वारा प्रदत्त गावित्यों के प्रयोग करने हुए, "श्री बैदान्त देनिकर देवस्थानम मायलापुर को निधीरण वर्ष 1982-83 से 1984-85 के अन्तर्गत आने वाली सर्विष के लिए उक्त धारा के प्रगोजनार्थं स्रधिन्धित करती है।

[सं॰ 4918[फा॰सं॰ 197/56/82/प्रा॰क॰ (ए I)]

New Delhi, the 21st September, 1982

INCOME TAX

S.O. 3993.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Sri Vedantha Desikar Devasthanam, Mylapure" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1982-83 to 1984-85.

[No. 4918/F. No. 197/56/82-IT(AI)]

आय-५र

का०आ० 3994 केर्न्याय सरकार, श्राय-कर श्रीवित्यम, 1961 (1961 का 43) की बारा 10 की उपवारा (23-ग) के खण्ड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "श्री श्रानम्बपुर न्यास" की निर्धारण वर्ष 1981-82 श्रीर 1982-83 के श्रंतर्गत श्राने वाली श्रविध के लिए उक्त वारा के प्रयोजनार्थ श्रीवस्थित करती है।

[सं० 4919/फा०सं० 197/216/80-प्रा०क० (ए-1)]

INCOME TAX

S.O. 3994.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961); the Central Government hereby notifies

"Shri Anandpur Trust" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1981-82 and 1982-83.

INO. 4919/F. No. 197/216/80-IT(AI)?

नई दिल्मं ,30 सितम्बर 1982

ऑय-कर

का॰ अ१९५ - केन्द्रिय सरकार, माय-कर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खण्ड (V) द्वारा प्रदत्त मिन्याकः प्रयोग करते हुए, "श्री ठाकुरजी लक्ष्मीनाम जी न्यास भुतस्तुन" को निर्वारण वर्ष 1981-82 से 1983-84 तक के मन्तर्गत भाने वाली अवधि के लिए उक्त धारा के प्रयोजनाम प्रधिन् वित्त करती है।

[fo 4930/फा॰सं॰ 197/169/79 সা০ফ০(ए॰I)]

भिलाप जैन, भवर सचिव

New Defhi, the 30th September, 1982 INCOME TAX

S.O. 3995.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Shri Thakurji Laxmi Nath Ji Trust, Jhunjhunu" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1981-82 to 1983-84.

[No. 4930/F. No. 197/169/79-IT(AI)]

MILAP JAIN, Under Secy.

आधिक कार्य विभाग

(बेंकिंग प्रभाग)

नई विय्यो, 13 नवस्थर, 1982

कार 3996 - बैंककारी विनियमन प्रिमियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रवक्त णिक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिकारिण पर एतदद्वारा धोषणा करती है कि उक्त प्रधिनियम की धारा 10ख की उपधारा (1) और (2) के अवबंध बैंक प्रॉप्ट समिलनाडु लिमिटेड, िक्तेलबेकी पर 4 मनस्वर, 1982 से 3 फरवर्र, 1983 तक 3 महीने की प्रविध के लिए, प्रववा उक्त बैंक में भगले पूर्णकालिक भन्न्यका की नियुक्ति हाने तक, इनमें से जी पहले हो उस समय तक लागू नहीं हों।

[संख्या 15/21/82-बी०मो०-[[]]

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

(Banking Division)

New Delhi, the 13th November, 1982

S.O. 3996.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of subsections (1) and (2) of section 10B of the said Act, shall not apply to Bank of Tamilnad Ltd., Trunulveli, for a period of 3 months with effect from 4th November, 1982 upto 3rd February 1983, or till the appointment of the next whole-time Chairman of that bank whichever is earlier.

[No. 15/21/82-B.O. III]

कां आ 3997. — बैककारी विलियमन प्रधिनियम, 1949(1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त गक्तियों का प्रयाग करते हुए केस्तीय सरकार भारतीय रिजर्ज बैंक को सिकारिश पर एतदहारा घोषणा करती है कि उक्त भवितियम की धारा 10 ख की उपधार, (1) भीर (2) के उपबंध मिराज स्टेट बैंक लिसिटेड मिराज पर 3 नवस्थर, 1982 से

2 मार्च 1983 तक 40 महीने की घविद्य के लिए प्रधाव घगले घष्यक्ष के कार्यभार संभालने तक, इनमें से जो भी पहले हो उस समय तक लागू महीं होंगे।

> [म॰ 15/29/82-बी॰मो॰ [H] एन॰ डी॰ बहा, भनर सचिव

S.O. 3997.—In exercise of the powers conferred by Section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendations of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of subsections (1) and (2) of Section 10B of the said Act, shall not apply to Miraj State Bank Ltd., Miraj for a period of 4 months with effect from 3rd November, 1982 upto 2nd March, 1983 or till the new Chierman assumes charge, whichever is earlier.

[No. 15/29/82 B.O. III] N. D. BATRA, Under Secy.

विवेश संत्रालय

नई दिल्ली, 12 नदस्बर, 1982

का॰आ॰ 3998.—राजनियक एवं कोंमिली अधिकारी (गल्ब एवं शुल्क) अधिनियम, 1948 (1948 का 41वां) के खंड 2 की धारा (क) के अनुपालन में केन्द्र सरकार, इसके द्वारा, भारत का हाई कमीगन, सुमाका, जान्विया में सहायक श्री विमल कपूर को तत्काल से कोंननी एजेन्ड का कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

[ਜਂ∘ਣੀ 4330(2)823]

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 12th November, 1982

S.O. 3998.—In pursuance of the clause (a) of section 2 of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and Fees) Act, 1948 (41 of 1948) the Central Government hereby authorise Shri Bimal Kapoor, Assistant in the High Commission of India, Lusaka, Zambia to perform the duties of Consular Agent with immediate effect.

[No. T. 4330 (2)/82]

का०आ० 3999.—राजनियक एवं कोंसली मिश्रकारी (भाष एवं भुक्क) मिश्रिनियम, 1948 (1948 का 41वां) के खंड 2 की धारा (क) के मनुपालन में केन्द्र सरकार, इसके द्वारा, भारत का राजदूतावास, बहरीना में सहायक श्री जे०भार० मानकतला को तत्काल से कोंसली एजेंग्ट का कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

[सं•टी 4330/2/82] बी० एस० निडर, ग्रनर मनिज

S.O. 3999.—In pursuance of the clause (a) of Section 2 of the Diplomatic and Consular Officer (Oaths and fees) Act, 1948 (41 of 1948) the Central Government hereby authorise Shri J. R. Manaktala, Assistant in the Embassy of India, Bahrain to perform the duties of Consular Agent with Immediate effect.

[No. T. 4330/2/82] B. S. NIDDAR, Under Secy.

बाणिष्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 नवस्त्रर, 1982

का॰ प्रा॰ 4000.—केस्बीय सरकार, काफी प्रधिनियम, 1942 (1942 का 7) की घारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों काप्रयोग करते हुए, काफी बोर्ड साधारण भविष्य निधि नियम, 1965 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात, :---

1. (1) इन निथमों का संक्षिप्त नाम काफी बोर्ड साधारण पविषय भिति (संगोधन) नियम, 1982 है।

(2) ये राजपन्न में प्रकाशन की नारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. मुच्छे। बोर्ड माधारण भविष्य मिधि नियम, 1965 में, नियम 8 मे, उपनियम (३) के पश्चान निम्नलिखत उपनियम श्रंत स्वापित किया जाएगा, प्रभात -- (4) उपनियम (1) में किसी बात के हाते हुए भी कोई ममिवाता, निधि में उस मास के लिए जिसमे वह सेवा छोड़ता है सब सक प्रभिवाय नहीं करेगा, जब तक कि उसने उक्त मास के प्रारम्भ से पूर्व उक्त मास के लिए मिमवाय करने का मपना विकल्प लेखा मधिकारी को लिखित, क्प में संनुचित न कर दिशा हो।"

> [फाइल सं० 1/17/82-प्लांट (बी)] बी ॰ एम ॰ एस ॰ नेगी, भवर मचिव

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 18th November, 1982

S.O. 4000.—In exercise of the powers conferred by section 48 of the Coffee Act. 1942 (7 of 1942), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Coffee Board General Provident Fund Rules, 1965, namely:
1. (1) These rules may be called the Coffee Board General

- Provident Fund (Amendment) Rules, 1982
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Coffee Board General Provident Fund Rules, 1965. in rule 8, after sub-rule (3). the following sub-rule shall be inserted, namely:—
 - "(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), a subscriber shall not subscribe to the Fund for the month in which he quits service unless, before the commencement of the said month, he communicates to the Accounts Officer in writing his option to subscribe for the said month."

(File No. 1/17/82-Plant (B)) B. M. S. NEGI, Under Secv.

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय

रहकरने का आवेश

नई विल्ली, 11 मधम्बर, 1982

का० आ० 4001---सर्वधी बैंक प्राप्त बड़ोदा, 10/12, बस्बई समाधार मार्ग, फोर्ट, बस्बई को (1) वन मिनोल्टा प्लेन पेपर कापियर मांडल, ई-पी-310 (2) बिजली के टाइपराइटर मॉडल 'हर्मेस' 808 दोनों फालतू पूजों भीर उपभोग्य सामग्री के साथ भागत के लिए 38,500/ रुपए सागत-बीमा-भाषा महय का एक श्रायान लाइसेंस रां॰ बी/ए/1091356. दिनांक 16.3.82 प्रदान किया गया था जो कि जारी होने की सारीसा से 1 ? मास के लिए वैध या। प्रव पार्टी ने उपर्युक्त प्रायान लाइसेंस की धनुलिपि सीमा-गुल्क प्रयोजन भीर मुद्रा-विनिमय नियंत्रण प्रतियां प्रदान करने के लिए इस भाषार पर भावदेन किया है कि मूल प्रतियां उनसे खो गई/अस्थानस्थ हो गई हैं। पार्टी ने श्रायान व्यापार नियत्रण नियमो के अनुसार भावश्यक शपय-पत्न/घोषणा भी भेजी है जिसके भन्मार उपयुक्त आयान लाइसेंस किसी भी सीम-शुल्क कार्यालय के पास पर्जाकृत नहीं कराया गया था भीर उसका बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया या ग्रीर लाइसेंस मे भव 38,500 रुपए की राणि शेष है। शपय-पत्न घोषणा में यह भी कहा गया है कि यदि भाषान लाइसेम की उक्त सीमा-शुल्क प्रयोजन भीर भुद्रा-विनिमय नियंत्रण प्रतियां बाद में भिल गई या प्राप्त हूं। गई तो मे जारी करने वाले प्राधिकारी को लौटा दी जाएं_{गी}। मै संत्रूष्ट हुं कि भाषात लाइसेंस की मूल सीमा-सुरुक प्रयोजन और भूद्रा-विनिमय नियंत्रण प्रतियां खो गई/मस्थानस्य हो गई हैं भीर निदेश देता है कि बायेदक की मायाम लाइसेंस की मनुलिपि सीमा-गुरूक प्रयोजन ग्रीर मुद्रा-विनिधय

नियवण प्रतिया जारी की जानी चाहिए प्रायास लाइसेंस की मुल सीमा-गुल्क प्रयोजन चौर मद्रा विनिमय नियक्षण प्रतिया एतदद्वारा, रह की जाती है।

> [मिमिल स॰ 12/183/81-82/एम एल एस/574] शकर चन्द, उप-मुख्य नियंत्रक, भाषात-निर्मात कृते मुख्य नियन्नक, प्रायात-नियात

Office of the Chief Controller of Imports and Exports

New Delhi, the 11th November, 1982

CANCELLATION ORDER

S.O. 4001.-M/s. Bank of Baroda, 10/12, Bombay Samachar Marg, Bombay were granted an import licence No. G/A/1091356 dated 16-3-82 for a C.I.F. value of Rs. 38,500 for import of (i) One Minolta Plain Paper Copier Model CP-310; (ii) Electric Typewriter Model 'Hertnes' 808, both with spares and consumables valid for twelve months from the date of issue. Now the party have applied for grant of Duplicate Customs Purpose and Exchange Control copies for the aforesaid import licence on the ground that the original one have been lost/misplaced by them. The party have furnished necessary affidavit/declaration as per I.T.C. Rules according to which the aforesaid import licence was not registered with any Customs House and was not utilised at all and the balance against the licence is Rs. 38,500. It has also been incorporated in the affidavit/declaration that if the said Customs purpose and Exchange Control copies of the import licence are traced or found later on, it will be returned to the issuing authority. I am satisfied that the original Customs purpose and Exchange control copies of the import licence have been lost/misplaced and direct that Duplicate Customs Purpose and Fxchange control copies of the import licence should be issued to the applicant. The original Customs Purpose and Exchange Control copies of the import licence are hereby cancelled.

> [File No. 12/183/81-82|MLS[572] SHANKAR CHAND, Dy. Chief Controller of Imports and Exports for Chief Contfoller of Imports and Exports

रामीण विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, 12 नवस्बर, 1982

का॰आ(॰ 4002---केन्द्रीय सरकार, कृषि उपज श्रेणीकरण ग्रीर (चिन्हाकन) प्रधिनियम, 1937 (1937 क. 1) की घारा 3 द्वारा प्रदत्त मक्तियों का प्रयोग करने हुए धनिया श्रेणीकरण चौर चिन्हाकन नियम, 1964 का भीर संशोधन करना चाहती है। जैसा कि उक्त धारा में अपेक्षित है, प्रस्तावित संगोधनो का निम्नेनि खत प्रारूप उन मभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है। इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमो पर उस तारीख से जिसको उस राजपत्र की प्रतियो जिसमें प्रक्षिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता की उपलब्ध करा दी जाती है, 45 दिन के पश्चात विचार किया जीएगा ।

इस प्रकार विनिविष्ट भ्रयधि की समाप्ति के पूर्व निवसों के उक्त प्रारूप की बाबन जो भी प्राज्ञेप या मुझान किमी व्यक्ति से प्राप्त होगे, केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी।

प्रारुप सियम

 इन नियमों का संक्षिप्त नाम धनिया श्रेगीकरण ग्रौर जिल्हांकन (संशोधन) नियम, 1982 है।

2 घनिया श्रेणीकरण श्रीर जिल्हांकन नियम, 1964 की घनुसूची

- (क) सारणी के स्तम्भ 4 के शीर्षक में नुकसान शब्द का लीप किया जाएगा।
- (ख) स्पम्म 5 मे 1 0, 2.0, 3.0 प्रको के स्थाप पर कपश. 2.0, 4.0, 6 0 प्रौर 6 0 प्रक रखे जायों ।
- (ग) पाद टिप्पणी 3 के स्थान पर निम्निश्वत पाद टिप्पण रखा जाएगा, श्रवीत्—

3 काले किए हुए बीज के फल या विशवन फल होते हैं जो ता।स्वक रूप से क्वालिटी पर प्रभाव बालते हुए, काले किए जाते हैं।

- टिप्पण (1) सूल ियम भारत के राजपन्न में काल्झा 2391, नारीख 11-7-64 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।
 - (2) पहला संलोधन भारत के र.जपस में कं क्या 523, तारीख 10-2-68 द्वारा प्रकाशित किया गया था ।
 - (3) दूसरा संगोधन भारत के राजपत्न में काञ्मा॰ 2842 सारीख 24-7-71 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

सिं० एफ० 10-4/82-ए एम०] जी०मेहना, निवेशक (विषणन)

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 12th November, 1982

S.O. 4002.—The following draft rules, further to amend the Coriander Grading and Marking Rules, 1964, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937), are hereby published as required by the said section for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that said draft rules will be taken into consideration after forty five days from the date on which the copies of the Gazette of India in which this notification is published are made available to the public.

Any objections or suggestions received from any persons with respect to the said draft rules, before the expiry of the period so specified, will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

- 1. These rules may be called the Coriander Grading and Marking (Amendment) Rules, 1982.
- 2. In the Coridander Grading and Marking Rules, 1964 in Schedule II,
 - (a in the heading of column 4 of the table, the word "Damaged" shall be deleted;
 - (b) in column 5 for the figures '1.0", '2.0', '3.0' and '3.0' the figures '2.0', '4.0', '6.0' and '6.0' shall respectively be substituted;
 - (c) for the foot note 3 the following foot note shall be substituted, namely:—
 - "3. 'Elackened Seeds' are those fruits or split fruits which are blackened, materially affecting the quality."
- NOTE.—(1) Principle rules published vide S. O. 2391 of G.O.I. dated 11/7/64.
 - (2) 1st amendment published vide S. O. 523 of G.O.I. dated 10/2/68.

(3) 2nd amendment published vide S. O. 2842 dated 24/7/71.

[No. F 10-4/82-AM]
D. MEHTA, Director (M)
Dated.—11-11-82.

संचार मंत्रालय

(बाक सार बोर्ड)

नई दिल्ली, 17 नवस्बर, 1982

का ब्झार 4003. — स्थायी आदेश संख्या 627, विसांक 9 मार्थ, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार अक्ष-तार महानिवेशक वे पालसपुर हांडयाला गुरु टेलीफीन केन्द्र मे दिनांक 16-12-1982 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निरुच्य किया है।

[संख्यः 5-5/82-पी०एस०की०] ध्रार०सी० भटाग्या, सहायकानदेशक (पी०एच०की००)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(P & T Board)

New Delhi, the 17th November, 1982

SO. 4003.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S. O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director Generat, Posts and Telegraphs, hereby specifies 16-12-1982 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Palampur/Jandiaia Guru Telephone Exchanges N. W. Circle.

[No. 5.5/82-PHB]

R. C. KATARIA, Assistant Director General (PHB)

अनुभवण संघटन

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 1982

- का. था. 4004: --- केन्द्रीय सरकार, राज भाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण भे, अनुश्रवण संघटन, संबार मंत्रालय के निम्नलिखित अनुश्रवण केन्द्रों को, जिनके कर्मचारी-वृद्द ने हिन्दी का कार्यशाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को अधिमूचित करती है. ---
 - अनुश्रवण केन्द्र, त्रिवेन्द्रम,
 - 2. अनुश्रवण केन्द्र, मंगलौर,
 - अगुश्रवण केन्द्र, नागपर ।

[संख्या 9-मौन/(10)/82] र. ग. देजधर, निदेशक, (बेतार अनश्रवण)

(MONITORING ORGANISATION)

New Delhi, 6th November 1982

S.O. 4004.—In pursuance of sub-rule 4 of the Official Languages (Use for official purpose of the union) Rule 1976 the Central Government pereby notify following Stations of

[भाग 11-खण्ड ३	(ii)] भारत का राजनसः दिसम्बर 4,	1982 भग्रहायण 13,	1994		4171
	inisation of the Ministry of Communications,	गाव	वसरा नंग्जर हिस्सा	গ্রন্থ	<u></u> इस
1.Monitoring	g station Nagpur.	.,.	मस्बर	हेक्टर	ऐयर
2.Monitoring	g station, Trivendrum.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	616.	44.
3. Monitori	ng station, Manglore.	গাঁদুল	256 का भाग -	_	
	[No. 9-Mon (10)/82]	, K.	268 ,, } -	- 00	2:
	R. G. DEODHAR, Director		j		
	(Wireless Mon.)	7.)	252 ,,]		
	,	,,	253 ,,		
		F7	254 ,, }	0.0	1
	ऊर्जा मंत्रालय	17	255 ,,)	•	
		19	241 ,,]		
	(वैट्रोलियम विमान)	U	251 ,,]	0.0	2
	नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 1983	,,	261 ,,]		
₩15 ⁵ 8115-400	5⊶यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि	11	262 ,,	•	
	उत्तरक है कि महर प्युराज्य में बंबई से पूर्ण तक	11	274 ,,		
	त्रपरवार हाना सहराष्ट्र राज्य म बबाइ स पुण तना ते परिवहन के लिये पार्डप लगाईन हिल्युस्पान पैट्रोलियम	n	275 ,, }	0.0	23
	विद्यारिकामी चाहिये।	11	277 ,,		
Antenia Record	אוווו אוופאי	1)	291 ,,]		
ग्रीर यतः यह	प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को विद्याने के प्रयोजन	1.7	292 ,,		
के लिये एतपाबद्व	धनुसूची में वर्णित सूमि में उपयोग का अधिकार भजित	11	296 ,,		
करना भावश्यक है	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,,	298 ,, }	00	6.4
		,,	299 ,, }		
	लियम ग्रीर खनिज पाईप लाईन (भूमि में उपयोग के	,	- 300 ,,		
	r) मधिनियम, 1962 (1962 का 50) की भ्रारा 3	,,,	301 ,,		
की उपधारा (1)	द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार	"	302 ,,	' .	
ने उसमें उपयोग	का मधिकार मजिल करने का मपना माश्रम एतद्द्वारा	11	303 ,,)		
भोषित किया है।		11	293 ,,]		
7.0		n	294 ,, }	00	09
पाईप लाइन बिट	त भूमि में हिसबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे होने के लिये प्राक्षिप सक्षम प्राधिकारी, हिन्दुस्तान) i	295 ,, }	1	
	शन लिमिटेड, बम्बई पूर्ण पाईप लीइन्स प्रोजेक्ट फपुसेल	 D	297 ,,		
	ढार रोड बस्बई को इस अधिसूचना की तारीख से	1)	298 ,,)		
21 दिनों के भीत	र कर सकेगा।	"	299 ,, }	00	38
3 _ 3	A mark ware in the faction of the con-	7.3	304 ,,		
•	क्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविद्यातः यह भी कथन	71	307 ,,)		
	ह यह चाहना है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या सियी की मार्कत।	ħ	332 का भाग) (1 ए 1()		
	_	11	332 ,,(172) -	-	
	अ नुम् षि		332(1 7 3)	0.0	03
τ	राईप लॉईन जॉभूलमे कान्हे तक	"	334 ,,		
	er front ordination	11	335 ,,		
नालुकः सावः	ल, जिला पूर्ण, इहाराष्ट्र	n	336 ,,) →-		
गां व	कसरा नम्बर हिस्सा क्षेत्रकल	71	342 ,,]		
	HF47	"	351 ,, 352 ,,		
	हैक्टर ऐयर	"	353 ,, }	00	73
))))	354 ,,]		
जोभूल	239 का भाग → 00 60		361 ,,		
11	240',, 00 60	" कान्हे	224 ,, }		
1,	168 ,,	u d	228 ,	00	0.5
"	169 ,,	"	229 ,,]		
n	170 ,,	"	327 ,, \	00	02
1)	171 ,, 00 19	17	330 ,, }	00	29
11	172 ,,		334 ,,]		
77	173		326 ,,]	0.0	14

326 "

53 ...)

7, 1001 GI/82—2

172 ,, 173 ,, 174

175 ,,

		Guerr	क्षेत्रफल		
ing ,,	स्वसारा नम्बर	हिस्सा नम्बर	हेक्टर	<u>ऐ</u> यर	
4					
काण्ह	54 ,, 55 ,,		00	41	
p; 17	56 ,,		0.0		
n	257 "				
11	258 ,,				
<i>n</i>	259 ,,				
)7 1)	260 ,, > 261 ,,				
., 11	262 ,,				
11	263 ,,				
11	264 ,, 265 ,,				
n n	266 "				
	267 का भाग े				
11 11	268 ,, [
17	269 ,, {				
73	ر 270 ,,				
n	282 ,,)				
27	283 ,, }		00	13	
"	284/2 ,,]				
"	284 ,,		00	04	
11	288 "	_	0.0	29	
n	292 ,,	_	- 00	32	
n	293 ,,		0.0	22	
71	312 ,,]				
1)	314 "		0.0	27	
**	311 "		0.0	43	
	316 ,		00	08	
η			00	37	
"	315 ,,				
"	512/1,2 ,,		00	19	
"	521 ,, }				
7)	522 ,, { 523 ,, {		00	17	
11 17	523 ,, 524 ,,		00	.,	
	840 ,,		00	16	
"	5		0.0	•	
17	536 ,,) 537 ,, {				
n	538 "		00	17	
11	539 ,,	~~			
†7	ر ,, 541			4	
,,	532 का भाग		00	10	
	535 "		00	01	
"					
"	533 ,,	h	0.0	43	
7,	460 ,,		0.0	5	
	452 ,, }		0.0		
*))	453 ,,		•		
*1	454 ,,			_	
"	455 ,, >		00	0.4	
	456 ,, 457 ,,				
n 11	457 ,, } 458 ,, J				
			00	34	
J‡	449 ,,		ŲŪ	,1 4	

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Petroleum)

New Delhi, the 9th November, 1982

S.O. 4005.—Whereas it appears to Central Government that it is necessary to lay a pipeline for transporting Petroleum Products from Bombay to Pune in the State of Maharashtra though Pipe-line and that said Pipe-line is to be Iaid through the agency of Hindustan Petroleum Corporation Limited, Bombay.

And whereas it appears to Central Government that for laying pipe-line it is necessary to acquire the Right of User in respect of the lands appended to herewith in schedule.

Now therefore in exercise of the powers vested in them by virtue of Section 3 (i) of Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) AO 1962 (50 of 1962) Central Government notify intention to acquire the Right of user in the lands referred to above.

Any person having his interest in the lands referred to above having any objection for laying the Pipe-line through above mentioned lands may prefer an objection within 21 days of the publication of this notification before the competent authority Hindustan Petroleum Corporation Limited, Bombay Pune Pipeline Project, Puels Refinery, Corridor Road, Bombay-74.

All persons having any objection may also state whether they want to be heard in person either himself or through any lawyer appointed by him.

SCHUEDULE

PIPELINE FROM: VILLAGE JAMBHUL TO KANHE

Taluka : Mawal, District : Pune (Maharashtra)

		AREA		
Village	Gutt No.	Hissa No.	Н-	⊸R
Jambhul	239 PART	_	00	60
1,	240 ,,		00	60
,,	168 ,,	_		
	169] ,,	_		
"	170] ,,	_	00	19
9	171 [,,			
**	172 } ,,			
נל	173 [,,	_		
11	174] ,, 175] ,,			
1)	- ·			
79	256]	_	00	2
17	268) ,,	_		
"	252) ,,			
79	253 (,,		00	1
11	254 \ ., 255 \ .,			
"	-			_
,,	2417		00	2
19	251) ,,	_		
"	261) ,,			
1)	262 1		•	^
1,	274 } ;;		00	2
11	275 277 ,	_		
11	•	_		
31	291] ,,	_		
"	292	_		
**	296 297	_	00	3.
**	200.3	-	00	
11	300			
**	301			
11	302			
**	" ز 303			
79	2937 PAR	т —		
"; "	294 } .,	_	00	09
19	295 J			

Viliage	Gutt No.	Hissa	AREA	
			H	R
Kanhe	296) "			
**	297 ,,		00	39
))	298 } ,, 290 [,,	_		
"	304 ,,	_		
,,	307) ,,	2 D		
»,	332) (1 A 332 (1 A	2 ,, Para 3 ,, Part	}	
"	332 ,, (1	Å 3 Pa	1)	
**	333 ,, 334 ≻ ,,	•	00	03
#3 >>	335	_		
**	336 ,,	_		
,,	∠4à∫ ,,			
22 13	351 ;; 354 ;;			
,,	353 }		0	73
••	354 [;; 361] ;;	_		
,,	2242			
,	228 \			
•	229 (,,		0	05
,	327) ,, 330) ,,		0 0	02 29
,	334	=	00	2,9
	326		00	14
,	53	_		
,	54			
•	55 ,,			
•	56 ,,			
	257 ,,	_		
	258 PART			
	259	-		
· •	260 ;, 261 ;,	1111111		
	262]			
1	263 } ,, 264	_	00	41
	2651	_		
	266 1	_		
	267) ",	_		
	268) ,, 269 ,, 270 } ,,	_		
	270) ,,			
	2827	-		
	283 } ,,	_	00	13
	284 ,,		00	04
	288 ,,	_	00	29
	292 ,,	_	00	32
	293 ,,	_	00	22
	3127 ,,	_	00	27
	314) "	_		
	311 ,,	_	00	43
	316 "	_	00	08
	316 ,,	_	00	37
	512/2	_	00	19
	512/1 \ ,,	-		
	521 522 ;		00	17
	523 [,,	_		
	524] ,,	-		
	540 ,,	No.	00	16
the	536) PART			
	537 ,, 538 } ,,		m	17
	539] ,,	=	00	17
	E 44 1 "			
	., ز 541	_		

Village	Gutt No.	Hissa	AREA	
		No.	H.	R
,,	535 ,,		00	01
>>	533 ,,		00	43
19	460 ,,	_	00	45
,,	4527			
,,	453 ", 454 ", 455 } ", 456 ", 457 ",	_		
13	454		0.0	
1	455 } ,,	— ,	00-	04
17	456 ,,	<u>~</u> `	-	
,,	457 (,,	_		
"	458] ,,	←		
11	449 ,,	_	0.1	34

[No. 12016/49/82-Prod.]

का ब्लाव 4006. ---यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह भाषश्यक है कि गुजरात राज्य में कानावाड़ा-2 से बांगड़ा-1 तक पैट्रीलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस भागोग द्वारा विछाई जानी चाहिए।

भीर यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनो को विद्याने के प्रयोजन के निए एतद्पावक धनुसूची में बर्णित भूमि में उपयोग का स्रविकार भजित करना भावक्यक है।

मतः सब पैट्रोलियम भीर स्वितिज फाइपलाइन (भूमि में उपयोग कें परिकार का भर्जन) मधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (ii) द्वारा प्रियत्त सक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का सिष्ठकार भन्तित करने का भ्रपमा भागम एतब्द्वारा चोषित किया है।

बगर्ते कि उन्त भूमि में हिसबड़ कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन विछाने के लिए बालेप सक्तम प्राधिकारी, तैल तथा प्राकृतिक गैस ब्रायोग, निर्माण बीर देखनाल प्रभाग, मकरपुरा रीड, बड़ीवरा-9 की इस ब्रियुचना की तारीख से 21 विनों के भीतर कर सकेगा।

भौर ऐसा झाक्षेप करने वाला हर अ्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी क्यन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्गत।

अनुसूची कानावाबा 2 से भांगड़ा-1 तक पाइप लाइन विछाने के लिए

राज्य - गुजरात	जिला: चेड्रा		तालुका	: योदान
गाव	सर्वे नं ०	हेक्टे यर	एमारई	सेन्टीअर
कानावादा	91/1	0	15	20
		सं ० 1201	6/50/8	2-मोड०]

S.O. 4006.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Kanawada 2 to Changda-1 in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals plpelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009.)

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE
PHELINE FROM KANAWADA-2 TO CHANGADA-

State: Gujarat	District:	Kaira	Taluka	: Cambay
Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
KANAWADA	91/1	10	15	20

[No. 12016/50/82-Prod.]

का० आर० 4007.—यतः केम्ब्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में कि यह आवश्यक है गुजरात राज्य में एस०एन०ए०जे० पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा से एस०एन०ए०ओ० प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा विछाई जानी चाहिए।

भीर यतः यह प्रतीत होता है कि एँसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पावड भनुसूची में उचीय का वर्णित भूमि में धिधकार को ध्रांजत उपयोग का करना धावश्यक है।

भतः प्रव पैट्टोलियम भौर श्वामिल पाइपलाइन (भूमि में उपयोग को भ्रधिकार का ग्रजैन) भ्रधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 कीं उपधारा (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्सीय सरकार ने उसमें उपयोग का भ्रधिकार भ्रजित करने का भ्रपमा भ्राशय प्रतद्वारा भोषित किया है।

बत्तों कि उक्त भूमि में हितबड़ कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइम लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्तम प्राधिकारी, तेल तथा प्राइतिक गैस प्रायोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बदोदरा-9 को इस अधिसुचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

भीर ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर स्थिति विनिर्विष्टतः यह भी ज्यान करेगा कि क्या वह यह भाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की भार्णतः।

. अनुसूची

एस०एन०ए०जे० से एस० एन० ए० ग्रो० तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

सेन्टीघर
50
50-
80
80
10

[सं॰ 12016/51/82-प्रोह]

्एल ब्लंगम् व गोयल, निर्देशक

S.O. 4007. Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from SNAJ to SNAJ in Gujarat state pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto; Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any persons interested in the said land, may within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission Cons, truction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hearded in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Plpeline From S. N. A. J. to S. N. A. O.

State : Gujarat District : & Taluka : Mehsana

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
KASALPURA	<u> </u>	0	06	50
	672	0	12	50
	668	0	04	80
	669	0	13	80
	619	0	03	10

[No. 12016/51/82-Prod.]

L. M. GOYAL, Director

विका तथा संस्कृति मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 1982

का॰ अ१० ४००८. ---सार्वजनिक परिसर (ग्रनिधकृत दखल कारों को निकालने) प्रधितियम 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रवत्त सिकालने) प्रधितियम 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रवत्त सिकालयों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतर्द्वारा अलीगक मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर होने के ताते निम्निलिखित सारणी के कालम (1) में उस्लिखित व्यक्ति को भारत सरकार के राजपितत प्रधिकारी के दर्जे के समकक्ष इस प्रधितियम के प्रयोजनों के लिए एतद्वारा सम्पवा प्रधिकारी नियुक्त करती है भीर जो उक्त सारणी के कालम 2 की तदनुरूपी प्रविद्यि में निविद्य सार्वजनिक स्थानों के सम्बन्ध में उसकी सम्बन्धित प्रधासनिक नियंत्रण की स्थानीय सीमाधों के भीतर इस घीधनियम के भौतौत सम्पवा धीधकारी के प्रधिकारों का उपयोग करेंगे ग्रीर उनका कार्य निष्यावन करेंगे।

सारणी		
नीम	सार्वेजनिक स्थानों ग्रौर प्रशासनिक नियंत्रण की स्थानीय सीमाएं	
(1)	(2)	
प्रो० प्रब्दुल मजीव सिद्दीकी रसायन शास्त्र प्रोफेसर प्रलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रभीगट	म्रलीगढ़ मृरिलम विश्विधालय, प्रगासितक नियंत्रणाधीन ग्रीर उससे सम्बन्धित ग्रलीगढ़ जिले की क्षेत्रीय सीमाग्री के भीतर स्थान	

[सं॰ फा॰ 382/82/डेस्क(यू)] धासा सिंह, डेस्क ग्रीधकारी

MINISTRY OF EDUCATION & CULTURE (Department of Education)

New Delhi, the 16th November, 1982

S. O. 4008.—In excercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the person mentioned in clumn (1) of the Tuble below, being a professor of the Aligarh Muslim University, Aligarh, equivalent to the rank of a gazetted officer of the Government of India, to be Estate Officer for the purposes of the said Act, and who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on Estate Officer by or under the said Act, within the local limits of his respective jurisdiction in respect of the public premises specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table.

TABLE

Nam:	Categories of public premises and local limits of jurisdiction.
(1)	(2)
Professor Abdul Majid Siddiqi, Professor in Chemistry, Ali- garh Muslim University, Aligarh.	Premises within the territorial local limits of Aligarh District belonging to and under the administrative control of the Aligarh Muslim University, Aligarh.
	[No. F. 3-82/82/Desk (U)]

ASSA SINGH, Desk Officer

अम ग्रोरपुनर्वास मंत्रालय

(अम विभाग)

आदेश

नई दिस्सी, 14 ग्रन्तुबर, 1982

का॰आ॰ 4009.—केन्द्रीय मरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध प्रमुसूची में विनिविष्ट विषय के बारे में विशाखापटनम पत्तन क्यास के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध एक ग्रीधोगिक विवाद नियोजकों ग्रीर उनके कर्मकारों के बीच विश्वमान है:

भीर केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है,

षत. केन्द्रीय सरकार, प्रौधोगिक विवाद प्रक्षितियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क प्रौर धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त गिक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक प्रौधोगिक प्रधिकरण गठिस करती है जिसके पीठासीन प्रधिकारी श्री एस॰वी रामना रेडडी होंगे, जिनका मुख्यालय हैदराबाद में होगा धीर उनत विवाद को उक्त प्रधिकरण को व्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनूसूची

क्या एम०बी० अनुभाग के श्रेणी 11 के ड्राइवरों को जूते देने से इंकार करने की विभाषापटनम पत्तन न्यास के प्रबंधतंत्र की कार्रवाई न्यायोजित हैं? यदि नहीं तो संबधित कर्मकार किस अनुनीय के हकवार हैं?

> [सं॰ एल॰-34011(10)/8?-डी॰ iv(ए)] टी॰सी॰ सीतारामन, डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION >

(Department of Labour)

ORDER

New Delhi, the 14th October, 1982

S.O. 4009.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Visakhapatnam Port Trust and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas, the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri S. V. Ramana Reddy shall be the Presiding Officer, with headquarters at Hyderabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Visakhapatnam Port Trust in refusing to supply shoes to Grade-II Drivers of M. V. Section is justified? If not, to what relief are the concerned workmen antitled?"

> [No. L-34011(10)/82-D. IV(A)] T. B. SITARAMAN, Desk Officer

आदेश

नई विल्ली 20 अक्तूबर, 1982

का०आ० 4010. — केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपावश्व भनुसूची में विनिर्विष्ट विषयों के बारे में दक्षिण रेल प्रणासन के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध एक भौद्योगिक विवाद नियोजकों भौर उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है:

भौर केम्ब्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निद्राणित करना वाछनीय समझती है;

भ्रतः, केस्त्रीय सरकार, श्रीबोगिक विवाद मधितयम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7 क और धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदश्च गिनियों का प्रयोग करते हुए, एक भीडोगिक अधिकरण पित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी॰भ्रष्टल राज होगे, जिनका मुख्यालय मद्रास में होगा और उसत विवाद को उसत अधिकरण को स्यायनिर्णयन ो लिए निर्देशित करती है।

अन् सूची

'रेल बोर्ड के पत्न संख्या पी०जी०-72/मार०एल०टी०/69-3, ता० 12-6-71 में सर्ताविष्ट भादेशों को ध्यान में रहते हुए, क्या विभाग रेल प्रशासन उन पुन निस्कृत किए गए श्रिमिको को, जिनकी पहले छुटनी की गई भी भीर जो भ्रपनी छंटनी के समय मजदूरी की स्केल वरें प्राप्त कर रहे थे, मजदूरी की स्केल दरों का संवाय न करना न्यायोजित ठहराया जा सकता है? यदि नहीं, तो कर्मकार किम भ्रमुतोय के हकवार है?

[एल-41011(6) 82-जी-II-बी] एस०एस० परागर, डेस्क मधिकारी

ORDER

New Delhi, the 20th October, 1982

S.O. 4010.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Southern Railway Administration and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule

in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri T. Arul Raj shall be the Presiding Officer, with headquarters at Madras and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"The view of the Railway Board's orders contained in letter No. PG-72/RLT/69-3 dated 12-6-1974 whether the Southern Railway Administration is justified in not paying the scale rate of wages to re-engaged workers who were retrenched earlier and were in receipt of the scale rate of wages at the time of their retrenchment? If not, to what relief are the workmen entitled?"

[No. L-41011(6)/82-D. II (B)]

New Delhi, the 23rd November, 1982

S.O. 4011.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Airforce Halleswar, Post Office Tezpur, District Darrang, Assam, and their workmen, which was received by the Central Government on the 17th November, 1982.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA.

Reference No. 30 of 1982

PARTIES:

Employers in relation to the management of Airforce, Halleswar, P. O. Tezpur, Distt. Darrang, Assam.

AND

Their Workmen.

PRESENT:

Mr. Justice M. P. Singh .- Presiding Officer.

APPEARANCES:

On behalf of Employers.—Absent On behalf of Workmen,—Absent.

STATE: ASSAM

AWARD

By Order No. L-14012/3/81-D. II(B) dated 23 August 1982 the Government of India, Ministry of Labour sent to this Tribunal the following dispute for adjudication:

"Whether the action of Garrison Engineer, Airforce, M.E.S. Tezpur in discharging Shri Kamal Chandra Keot, Valveman from service w.e.f. 24-8-72 is justified? If not, to what relief the workman is entitled?"

2. On receipt of the Reference notices were issued to parties fixing 2-11-1982 as first hearing date with direction to file their respective documents and written statements, if any. But to-day when the case was called out nobody appeared. The Tribunal received a letter from the office of Garrison Engineer Airforce, Tezpur, P. O. Halleswar intimating that the concerned workman Sri Kamal Chandra Keot,

Valveman had been reinstated and he reported for duty on 14th July, 1982 (Forenoon). In view of above there seems to exist no dispute in the matter.

I, therefore, pass a 'No Dispute' Award in the case. Dated, Calcutta, The 2nd November, 1982.

Sd/-

M. P. SINGH, Presiding Office, [No. L-14012(3)/81-D. II (B)]

New Delhi, the 23rd November, 1982

S.O. 4012.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Security Paper Mills, Hoshangabad, and their workmen, which was received by the Central Government on 9-11-82. 9-11-82.

BEFORE JUSTICE SHRI S. R. VYAS (REGD.) PRESID-ING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR(M.P.)

Case No. CGIT/LC(R) (45) of 1981

PARTIES:

Employers in relation to the management of Security Paper Mills, Hoshangabad and their workmen represented through the S.P.M. Staff Union, C/o Security Paper Mills, Hoshangabad (M.P.).

APPEARANCES:

For Workmen.—Shri P. S. Nair, Advocate.

For Management.-Shri K. K. Adhikari, Advocate.

INDUSTRY: Paper Mills DISTRICT: Hoshangabad (M.P.)

AWARD

Hoshangabad, the 29th October, 1982

This is a reference made by the Central Government in the Ministry of Labour vide Notification No. L-42011(12)/80-D. II (B) dated 20th November, 1981, for adjudication of the following dispute by this Tribunal:—

"Whether the action of the management of Security Paper Mills, Hosganbabad in denying overtime and night duty allowances to its staff members drawing basic pay of Rs. 751 and above is legal and justified when their counterparts in Indian Security Press, Nasik are entitled to such allowances? If not, to what relief the concerned workmen are entitled?"

2. Facts which are not in dispute in this case are as under :—

Workmen in this case are the employees of the Security Paper Mills, Hoshangabad, hereinafter referred to as the Mills. The Mills employ different categories of workmen some of whom are getting Rs. 750 p.m. as wages. Neither any Overtime Allowance nor any Night Duty Allowance is paid by the Mills management to such workmen who are drawing their basic pay of niore than Rs. 750 p.m. Workmen claim that since in the Indian Security Press at Nasik such allowances are paid to such members of the staff whose basic pay is more than Rs. 750 p.m. the Mills management is not justified in denying such allowances to them also. As the claim made by the workmen of the Mills was not conceded to by the Mills management an industrial dispute was raised which has resulted in the present reference to this Tribunal.

3. The case of the workmen is that in the Indian Security Press, Nasik, which is also an Undertaking of the Government of India as also in other Government Undertakings

like Ordnance Factory etc. Overtime Allowance and Night Duty Allowances are paid to those employees whose basic pay is more than Rs. 750; that those workmen who are receiving these two allowances in the Indian Security Press, Nasik and other Undertakings of the Government of Indian are employees of the same Government of which these workmen are the employees; that in the other establishment of Security Press Nasik there is no ceiling of basic pay for entitlement of these two allowances; that in the Ordnance Factory Khamaria, Jabalpur, Ordance Factory Itarsi, Government Mint₃ at Calcutta, Hyderabad and Bombay, Central Government pays these two allowances to the workmen even though their basic pay is more than Rs. 750; that duty hours of the employees are fixed at 8 hours per day and taking duties from the workmen beyond this duty period of 8 hours without payment of Overtime Allowance is not legal; that the Government cannot discriminate the case of one employee with the case of the other employees in the other establishment; that Overtime & Night duties involve extra physical and mental burden on the workmen and that denial of Overtime and Night Duty Allawances to the workmen by the Government and grant the same allowances to the similar workmen working in similar undertakings is a clear discrimination in law by the Government of India.

- 4. On behalf of the management, it is contended that members of the Security Papers Mills Staff Union (at whose instance the present reference ans been made) are not workers defined under the Factories Act, 1948; that overtime allowance of the workers who are covered under the Factories Act is regulated under Sec. 59 of the Factories Act; that these workmen are non-industrial workmen in the Mills; that the question of overtime allowance of workers of the Mills except those covered under Sec. 59 of the Factories Act is regulated by the Government of India Circulers referred to in Annexures A to E; that in accordance with these circulars overtime allowance is not payable to those employees who have been drawing basic pay Rs. 750 and above; that in accordance with the Ministry of Finance letters (Annexures H to Annexure I) the industrial and non-industrial employees drawing a basic salary exceeding Rs. 750 are not eligible for Night Shift Allowance; that these circulars are applicable to al departmental undertakings of the Government of India; that the terms and conditions with regard to Overtime and Night Shift Allowances which are applicable to the members of the Staff of the Security Press, Nasik, can-not be made applicable to the non-industrial employees of the Mills; that the Government of India have a number of industrial undertakings and unless the dispute referred to for adjudication is in respect of all the Industrial Undertaking; the employees of the Mills cannot choose one undertaking only for determination of the question of Overtime and Night Shift Allowances; that the Government have the absolute right to determine the terms and conditions of service of the employees of a particular undertaking; that Overtime Allowance and Night Shift Allowance is paid to the employees of the Indian Security Press Naulk by two different orders of the Government of India (These orders are referred to in Para 11 of the statement); that the Government are justified in regulating, fixing and prescribing different scales of pay and other allowances for different industrial undertakings; that in the Security Paper Mills the employees are getting preduction incentive allowance which is not neld to the employees of the Security Press at Nasik and that in the Security Press Nasik and Security Paper Mills at Hoshangabad the working hours are different.
 - 5. Rejoinder was filed only by the workmen and not by the Mills. In this rejoinder the workmen have reiterated the allegations of discrimination allegedly being made by the Government as also for their entitlement to the Overtime and Night Shift Allowances at par with the employees of the Security Press at Nasik.
 - 6. On these pleadings of the parties, the following issues were framed:

ISSUES

1(a) Whether the workmen of the Security Paner Mills Hoshangabed are entitled to claim Overtime Allow-

- ance and Night Shift Allowance as claimed in this case?
- (b) If so, from what date and at what rates ?
- 2. Relief.
- 7. My finding on the aforesaid issues are as under :-

Issue No. 1(a).—That the workmen of the Seucrity Paper Mills Ltd. drawing pay of Rs. 751 or more are entitled to Overtime and Night Shift Allowance at the same rate at which the same is being to the similar employees of the Security Press at Nasik.

Issue No. 1(b) & (2).—As per order passed below, Reasons for the above findings:

- 8. Issue No. 1(a).—In this case no oral evidence has been given by either party. Only the management of the Mills has filed certain Government Circulars/Orders etc. in support of its contentions. Accordingly in the absence of any oral evidence the issues referred to above have to be decided on the basis of the pleadings of the parties and the documents filed by the management.
- 9. Ex. M/10 is the first document in order of time dated 10-8-1927 from the Finance Department, Government of India, addressed to the Master, Security Printing, India which gives him power to employ overtime labour to meet the work. It also specifies the manner in which the overtime is to be paid. Ex. M/11 is the next order of the Finance Department, Government of India, dated 6-1-1942 which allows 25 per cent more in addition to normal days pay as Night Shift Allowance. The next order of the Government in order of time is Ex. M/1 dated 8-3-1968 by which overtime allowance was allowed to non-industrial staff of the Mills for work done in excess of 48 hours on the terms and conditions stated therein. Ex. M/7 is the next document in order of time dated 10-2-1970. By this order the Finance Ministry allowed Night Duty Allowance to non-industrial employees of the Mills drawing pay upto Rs. 470 Ex. M/2 is the next document dated 18-5-1972 by which calculation of the rate of overtime allowance was fixed. By Ex. M/3 dated 13-10-1972 the period of work for entitlement of over-time and night shift allowances to workmen drawing basic pay of Rs. 500/- was regulated. Ex. M/4 dated 1-5-1974 is the next order of the Finance Ministry by which the ceiling of Rs. 500/- was raised to Rs. 750/-. To the same effect is order Ex. M/5 dated 6-1-75. The last order is dated 6-6-1980 Ex. M/6. By this order the General Manager of the Mills was informed by the Ministry of Labour that the limit of Rs. 759/- has been fixed on the recommendation of the Third Pay Commission and is applicable to all Industrial undertakings of the Government. It was further stated in this letter dated 6-6-1980 that under Sec. 64(1) of he Factories Act payment of overtime allowance to em drawing pay Rs. 750/- or more per month is barred. to employees
- 10. From the aforesaid documentary evidence it would therefore be clear that sometime in the beginning overrime/night duty allowance was payable but subsequently the ceiling was fixed at Rs. 470 Rs. 500 and lastly at Rs. 750.
- 11. Section 59 of the Factorics Act referred to in the statement of demand provides that where a worker works in a factory for more than nine hours in any day or more than forty-eight hours in any week, he shall be entitled to overtime wages at the date of twice his ordinary rate of wages. Sub-section (1) of Sec. 64 referred to in Ex. M/6 dated 6-6-1980, with is the last order of the Government, Provides for making rules to define persons who holds position of Supervision or management or who are employed in confidential position in a factory. No document has been produced before this Tribunal about the making of such rules or definition of persons holding the position of supervision or management employed as a confidential position in the factory. In the light of the aforesaid documentary evidence given by the management only, the only question that arises for consideration is as to whether the non-payment of overtime and night shift duty allowance of employees getting Rs. 750/or more can be said to be justified only on the basis of the Government Order?

- 12. The grievance of the workmen that their counter-parts in the Security Press at Nasik are being paid these two allowances and the same are being denied to them.
- 13. In para 11 it is stated by the management that restrictions imposed by the Government Order dated 1-5-1974 (Ex.M/4) for payment of overtime allowance to persons getting Rs. 750 is applicable to all the industrial undertakings of the Government including the Indian Security Press at Nasik. It is, however, admitted in this paragraph that despite the imposition of celling non-industrial employees of the Security Press at Nasik are paid overtime at the single rate in view of an old practice of paying this allowance without putting any limitation by virtue of the Government of India in the Finance Minstry's letter dated 16-8-1927 (Ex.M/10). It is also admitted that night shift allowance is also allowed to the employees of the Security Press in view of the order dated 6-1-1942 (Ex.M/11).
- 14. It would thus be clear that despite the order Ex. M-10 dated 16-8-1927 and Ex. M/11 dated 6-1-1942 and the subsequent orders passed by the Government of India by which ceilings have been fixed the employees of the Security Press are paid overtime and night shift allowances by the Government of India. Government of India is the owner of the Security Press at Nasik and the Security Paper Mills at Hoshangabad. An important question arises is as to whether there can be any discrimination between the two employees of the same employer in the matter of payment of overtime and night shift allowances?
- 15. Though the Government have absolute right to fix different scales of pay and allowances according to categories of employees in different industrial undertakings but there can be no departure from the basic principle of equal pay for equal work which is deducible from the constitutional provisions of the Constitution of India.
- 16. The question whether there can be any such discrimination as is apparent in this case was considered in the case of Randhir Singh Vs. Union of India and others (AIR 1982 SC 879). In that case their Lordships were considering the case of a Driver in the Delhi Police Force whose pay scale was different and lower as compared to the other drivers in the Railway Protection Force and other Departments of the Government. Considering the question as to whether the principle of equal pay for equal work is or is not a fundamental right or an abstract doctrine, it was held by their Lordships as under:—
 - "Construing Articles 14 and 16 in the light of the Preamble and Art. 30(d), we are of the view that the principle Eual pay for Equal work' is deducible from those Articles and may be properly applied to cases of unequal scales of pay based on no classification or irrational classification though those drawing the different scales of pay do identical work under the same employer."

On the facts of that case their Lordships directed the Delhi Administration to fix the scale of pay of the Petitioner at least at par with the scale of pay of the Drivers of the Railway Protection Force which was higher than the scale of pay admissible to the petitioner driver-constable in that case.

- 17. In this case in para 11 referred to above the management admits that the ceiling of Rs. 750 for non-entitlement of night shift and overtime allowances though applicable to the non-industrial employees of the Security Press also but that is being paid because of the two orders of 1927 and 1942 (Ex. M/10 and Ex. 11/11). It is not understood as to why when employees of the same employer i.e. Government of India in this case are being paid overtime and night duty allowances to employees of one industrial undertaking the same should be denied to the employees of the other industrial undertaking of the same employer.
- 18. It may also be observed that there are fixed working hours of the employees in all the industrial undertakings. At some stage employees getting less than Rs. 750 were allowed overtime and night shift allowance but the same is being

denied now. How can an employee in an industrial undertaking be asked to work overtime without payment of over-time allowance. Night shift allowance is paid because an employee is required to work during night hours which are not the normal hours of work. However, on principles of equity and on the principle of Equal pay for Equal work the claim by the workmen in this case appears to be justifi-Though it was stated that the conditions of working in the Security Press at Nasik and Security Paper Mills Hoshangabad are different but there is not an lota of evidence placed before this Tribunal by the management to show as to whether and to what extent the difference lies in the work and method of these two industrial undertakings. If some material has been placed before this Tribunal to justify the discrimination the matter could have been considered in the light of the material so placed, but since that has not been done the only inference is that the general conditions of both the industrial undertakings under which the employees getting pay over Rs, 750 is the same. Consequently, there is no justification made out by the management for discrimination in the matter of payment of overtime and night shift allowances.

- 19. Issue No. 1(b) & (2).—As per orders passed below.
- 20. Accordingly for the reasons given above, the following award is given:—

The workmen of the Security Paper Mills Ltd., Hoshangabad who are drawing pay over Rs. 750 are entitled to overtime allowance and night shift allowance at par with such allowances being paid to the similar employees of the Security Press at Nasik. Such allowance shall be paid to these workmen from the date of this award.

In the circumstances of the case, both the parties shall bear their own costs as incurred.

S. R. VYAS, Presiding Officer
[No. L-42011(12)/80-D.Π(B)]
S. S. PRASHER, Desk Officer

आदेश

नई विल्ली, 4 सवस्मर, 1982

का०आ० 4013. — केम्ब्रीय सरकार, शीकोिंगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रवस्त शिक्तयों का प्रयोग करने हुए स्यू मंगरोर एन्ट्रन और टूटीकोरन परान के प्रश्यक्ष से यह प्रपेशा फरती है कि वह श्रीकोिंगिक विवाद (केन्द्रीय) नियम, 1957 में विहित सामले के लिए अपने भ्रष्टीन भ्रीकौंगिक स्थापन में एक कार्य समिति गठिन करें।

[फा॰ सं॰ एस०-11018(6)/81-की 1(ए)]

ORDER

New Delhi, the 4th November, 1982

S.O. 4013.—In exericse of the powers conferred by subsection (1) of section 3 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby requires the Chairman of New Mangalore Port and Toticorin Port to constitute a Works Committee in the industrial establishment under him in the manner prescribed in the Industrial Disputes (Central) Rules, 1957.

[F. No. S-11018(6)/81-D.I(A)]

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 1987

का शा 4014 — के द्वीय सरकार, भीषोगिक विवाद मधिनियम, 1947 (1947 के 14) की भ्रारा 33-ग की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त गिक्तयों का प्रयोग करने हुए भारत सरकार के भूतपूर्य श्रम, रोजगार भीर पुनर्वास मंत्रालय (श्रम प्रौर रोजगार विभाग) की प्रशिस्चना सै० का ०न० 4650 नारीक 19 दिसस्यर, 1967 का निस्नलिखत और मंगोधन करती है, प्रथान

उन्त अधिसूचना से.उप बढ़ सारणी में कम स० 9 और उससे मंबिति प्रविध्यों के स्थान पर निम्नलिखन रखा जाएगा प्रशीन —

- '9(क) कर्नाटक राज्य सरकार गुलबर्गा जिना बदिर जिना रामचर जिला द्वारा गठिन श्रम न्य यालय वन्ल रो जिला बेलगम जिला हुबती उत्तर क्लारा जिला, बीजापुर जिना ग्रीर धारवा जिला।
- 9 (ख) श्रमन्याय नय बगलाह गलवर्ग ग्रीप वेनगाम प्रभागो को छोन्कर कर्नाटक राज्य

निरमण मृल ग्रि.सिन्तः। कंश्यं० 1650 तार्रेख 19-12-67 भारत के राजपंत्र भाग 2 खंड 3 उपखंद (11) तारीखं 30-12-67 को पक्तिशित में गई ग्रीम तत्पश्चीत निम्नलिखित द्वारण उसका संशोधन किया गया

- (1) ग्राध्यूचना म०का०ग्रा॰ 1175 तारीख 20-3-68 30-3-68 वा
- (11) শ্রাঘির্বান ন০ কা০য়া০ 668না বিজ 11-2 69 22-2-69 কা ব সাধার
- (111) अधिस्वना म० का०मा० 1894 तारीख 9-5-69 17-5-69 का राजपत्र
- (IV) ग्रिधिम्बना म० का०ग्रा० 1768 नारीख 30-4-69, 10 5-69 का राजपत
- (v) प्रधिम्चना म० का॰घा॰ 2796 नारीख 3-7 71 24-7-71 का राजपत
- (VI) अधिमूचना स० का०मा० 3810 तारीख 23-9-72, 4 11 72 का राजपत्र
- (VII) अधिचना स० का०आ ० 4521 तारीख 26-9-75, 18-10-80 का राजपत्र
- (VIII) ग्रिसियूचन, स० का॰ग्रा० 2914 तारीख 13-10-80 25-10-80 का राजपत
- (ix) ब्रिधिसूचना स० का० ग्रंग्० 45 नारीख 19-12-81, 2-1-82 का राजपत्र
- (x) म्रिधसूचना २० का॰मा॰ 1633 तारीख 16-482, 15-82 का राजपत

[संव एस-11020/9/81-3 व प्रई० ए]० एल०के० नारायणन श्रवर मचिव

New Delhi the 22nd November 1982

S. O. 4014 . In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 33-C of the Industrial Disputes Act, 1947 (4 of 1947), the Central Government hereby makes the following furth a smendments in the notifier ion of the Government of India in the erstwhile Ministry of Labour, Employment and R habilita ion (Department of Labour and Employment) No. S. O. 4650. died the 19th Docember, 1967, namely

In the Table when d to the said Notific tien, for scrial No. 9 and the entry's relating thereto the following shall be substituted, namely —

"3(1) Labor Cor Hubbi cons- Gulbarga District, Bidar tried by the Sixte Go- Dritt, vernment of Karia ka Raichur District, Bell ry District

Belging District Lt' re Kinn District By pur District and District District

9(b) L b itr Court Bingalore Tr Sate of Krit ka excliding Gilbarg and Blgaum Divisions

Note Principal Notification midth 1 vites 0 4650 dited the 19 12-67, Part II, Silving 3 Silving tion of Gazitte of India ted the 30 12-1667 subsequently then by

- (i) Notific tion No S O i175 dated 20-3-68. Gazette of 30-3-69.
- (ii) Notification No S.O. 668 dat d 11 2-6 G 7 tte of 22-2-69
- (III) Not fication No S O 1894 dated 9-5 69 Gazette of 17-5-69
- (iv) Notification No. S.O. 1768 dated 20 4-62, Gaz tt. of 10-5-69
- (v) Notification No. S.O. 2696, 1 ted, 3-7-71. G zett. of 24-7-71.
- (vi) Notification No. S. O. 3510 dated 23 9-72. Gazette C. 41-1-72.
- (vii) Notification No. S.O. 4521 dated 26-9-75, Gwatte of 18-10.80
- (viii) No ification N ... O 2914 d ted 13-10-99 Gazette of 25-10-80
- (ix) Notificati n No S O 45 d ted 10-12-81, Gazette of 2-1-82
- (x) Notification No. S. O. 1633, Juted 16-4-82, Gazette of 1-5-82

[Nc S 11020 (9)/81 D I (A)] I K NARAYANAN Undu Secy

नई दिल्ल 22 गर्नम्बर 1982

का ब्लार 4015 - वेन्द्र यं सरव र की यह राज है कि राव पास्पेट (भ्रपाट इट खानो) व नियाजन की बाबन मजदूर के द न्यूनतम मजदूरी भ्रष्टिनियम 1948 (1)48 का 11) ये अन्य न नियम ना ज्यान चाहिए

भ्रत कन्द्रीय सरक र उक्त श्रधिनियम क धारा 77 हार। प्रदत्त मिक्तियों का प्रयोग करने हुए उक्त नियाजन का उक्त श्रधिनियम का अनस्चीं के भाग 1 से जा ने के अपने अग्रय क स्चना दन न

इस ग्रधिपूचना क राजप त मं प्रकार का ताराख में तीत माम की भ्रावधि का समाप्ति पर या उसस पूर उक्त पारवान के बंबा किसी व्यक्ति संजो भ सुधाव या ग्राध्य प्राप्त हा केस्य समरक र उनपर विचार वरेगा।

> [एस 3 '017' 3 8 1 डन्यू स (एस ाय)] एम० वर्ष भहेत अवर सचिव

New Delh, the 22n1 November 1982

S.O 4015.—Whereas the Certral Government s of opinion that the minimum rates of wages should be fixed under ne Minimum Wages Act 1948 (11 of 1948) in respect of the employment in Rock Phosphate (Apatite Mines),

Now, therefore in exercise of the powers conferred by Section 27 of the said Act the Central Government hereby gives notice of its intention to add the said employment to Part-I of the Schedule to the said Act,

Any suggestions or objections which may be received from any person in respect of the said addition on or before the expiry of a period of three months from the date of publication of this notification in the Official Gazette, will be considered by the Central Government.

[No S-32017/3/81-WC (M.W.)] M. L. MFHTA, Under Secy.

New Delhi the 22nd November, 1982

S.O. 4016—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Hyderabad, in the industrial dispute between the employers in relation to the mangement of Singarem Collieries Co. I imited Kothagudem, and their workmen, which was received by the Central Government on the 13th November, 1982.

BFFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CFN'TRAL) AT HYDERABAD

Industrial Dispute No. 20 of 1980

BF TWEEN

Workmen of Singareni Collieries C mpany I imited, Kothagudem, Kharimam District (A.P.).

AND

The Management of Singareni Collievies Company Limited Kothagudem, Khammam District (A P.).

APPEARANCES:

- Sri D. S. R. Varma, Advocate-for the Workmen.
- Shi K. Srinivasa Murthy, Honorary Secretary Andhra Pradesh Chambers sof Commerce and Industry, Hyderabad—for the Management

AWARD

By Order No. L-21012(1)/80-D IV.B, dated 15-12-1980, the Government of India referred the following industrial dispute existing between the Singaieni Collieries Company Limited, Kothagudem and their Workmen to this Tribunal for adjudication:

- "Whether the management of Messrs Singarem Collieries Company Limited, Kothagudem is instified in dismissing Shri D. Subbanao, Watchman, Managur Collieries with effect from 7-4-1980? If not to what relief is he entitled?"
- 2. After the above industrial dispute was taken on file in I.D. No. 20 of 1980 on 22-12-1980, notices were issued to both the Management and the Workmen. The Workmen filed their claims statement on 12-2-1981. To the above claims statement, the Management filed their counter on 17-3-1981. Sri K. Srinivasa Murthy appeared for the Management as Management's representative whereas Sri D.S.R. Varma filed his vakalat for the Workmen with the consent of the other side. The case underwent seme adjournments for enquiry.
- 3. While so, on 9-8-1982, a compromise retifion signed by the Management and the Workmen was filed into this Tribunal. Since the parties were absent on that day, the compromise petition numbried as M.P. No. 100/82 was posted to 27-8-1982 for appearance of the parties to record the compromise On 27-8-1982 Sri. V. Gopala Sastry, Deputy Chief Personnel Manager of the Company was present. He admitted the execution and the terms of the compromise read over to him. As the Workmen were not present on that day, the case was adjourned from time to time till today. Today also the Workmen were absent. The advocate of the Workmen namely, Sri.D. S. R. Vanna, who is present for

om the Workmen admits the truth and the execution of the compromise and the terms thereof. Hence the compromise is iblirecorded today.

- 4. The following are the terms of the compromise recorded in M.P. No. 100/82:—
 - "(1) The Management agreed to consider the case of Sri D Subba Rio, Hx-Watchman, S&PC, Manuguru on compassionate grounds
 - (2) Sri D. Subba Rao will be reappointed as Watchman, S&PC., in the Company and posted in any Division. He will be allowed the basic pay he was drawing at the time of his dismissal.
 - (3) The intervening period i.e. from the date of dismissal to the date of his reporting for work on reappointment will be treated as leave on loss of pay.

 Mr. Subba Rao shall not have any claim for wages or other benefits during the intervening period.
 - (4) The parties are filing this compromise on the above terms and conditions before the Hon'ble Tribunal, in full and final settlement of the dispute, with a prayer to the Hon'ble Tribunal to pass an Award accordingly"
- 5 In view of the above compromise admitted by both the patties, this Award is passed in terms of the above compromise. A copy of the compromise petition is appended to this Award.

Dictated to the Stenographer, transcribed by him and corrected by me and given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 15th day of October, 1982.

'No. L-21012(12)/80-D.IV(B)]

5d/-

S S. MFHTA, Desk Officer Industrial Tribunal

APPENDIX OF EVIDENCE

−ΝJΙ **−**

Sd7-

Industrial Tribimal

BITFORE THE HON'BLI- INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL). HYDERABA D

In the matter of I.D. No 20 of 1980

BETWEEN

The Workmen of S.C. Co Itd., Manuguru Division.

-Claimant/Workman,

AND

The Management of S.C. Co. 1td., Management Division, Respondent/Management.

It is submitted that without prejudice to the merits of the case before the Hon'ble Industrial Tribunal (Central), the paties desired to settle the issue mutually. Accordingly, the issue is settled on the terms and conditions set out hereunder.—

- "(1) The Management agreed to consider the case of Sri-D. Subba Rao, Fx-Watchman, S&PC., Managuru on compassionate grounds.
- (2) Sri D. Subba R to will be reappointed as Watchman, S&P,C., in the Company and posted in any Division. He will be allowed the basic pay he was drawing at the time of his dismissal.
- (3) The intervening period i.e., from the date of dismissal to the date of his reporting for work on reappointment will be treated as leave on loss of pay. Mr. Subba Rao shall not have any claim for wages of other benefits during the intervening period.

(4) The parties are filling this compromise on the above terms and conditions before the Houble Tribunal, in full and final settlement of the dispute, with a prayer to the Hon'ble Tribunal to pass an Award accordingly".

In the circumstances, both the parties, pray the Honble Industrial Tribunal (Central), to pass an Award in terms of the above compromise.

For Workmen:

For Management:

Sd/-Sd/-

(M. Komaraiah),

(R. D. Sharma).

General Secretary,

Executive Director,

Singateni Collieries Workers' Union.

M/s. The Singareni

Sd/- D Subba Rao.

Collieries Company Limited.

Dated: 13-7-1982.

Kothagudem Collieries.

New Delhi, the 23rd November, 1982

S.O. 4017.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government enment Industrial Tribunal, Calcutta, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Deoli Colliery, Ranipur Sub-Atea of Messis Eastern Coalfields Limited, and their worknien, which was received by the Central Government on the 17th November 1982

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL. CALCUTTA

Reference No. 51 of 1978

PARTIES:

Management of Deoli Colliery, Rampur Sub-Area, Eastern Coalfields Limited

AND

Their Workmen.

APPLARANCES.

On behalf of Management -- Mr. J. N. Mishia, Senior Personnel Manager,

On behalf of Workmen-Absent

STATE: West Bengal

INDUSTRY : Coal Mine

AWARD

The following dispute was sent to this Tribunal by the Government of India, Ministry of Labour vide Order No. L-19012(63)/77-D.IV(B) dated 12th May, 1978, for adjudication:

"Whether the action of the management of Ranipur Sub-Area of Eastern Coalfields Limited in stopping

Shii Umapada Kumbhakar, Office Boy Colhery from work with effect from 30-4-73 is justified? If not, to what relief is the concerned workman entitled?

- 2. No one appeared on behalf of the workman. The management is present and the case has been heard ex-parte. The case of the Coal Mane Employees. Union, Dishetgarh (Briefly the Union) is that the concerned workman Uma-pada Kumbhakai was an oline buy of the colliery and he worked as such till 29th April, 1973 But the management illegally stopped him from work with effect from 30th April 1973 on the ground that he was a minor. The management of the Deoli Colliery, Ranipin Sub-Area of Eastern Coalhelds I td contends that the reference is not maintainbale against the Government company the dispute having arisen prior to 1st May, 1973 the appointed date as per the coalmine, Nationalisation Act, 1973 and also because no industrial dispute existed between the parties concerned. It is denied that the concerned workman was an office boy of the The management stated that the concerned workcolliery. man was a domestic servant of an officer of the colliery and was aged only 14 years.
- 3. In view of the order dated 1st October, 1980 passed in this case by Sri R. Bhattacharya, my predecessor-m-office, it is not necessary to go into the merits of the case of other contentions of the management. By that older it has been held that no appreciable number of workmen of Deoli colliery were members of this union, that no appreciable number of workmen authorised the union to espouse the cause of the workman and that the union had no authority or locus stands to esponse the cause of the concerned workman and had no representative character to tepiesent the workman of the Deoli collicity. It has also been held by that order that the present dispute R, therefore, not an industrial dis-pute. After having held so the Jearned. Tribunal applied Section 2A of the Act and directed the concerned workman to authorise the loint Secretary of the Union or any other competent person to conduct his case. In my opnion this case cannot be treated as one under Section 2A of the Act. No individual workman raised any industrial dispute in this case. It was the Union who raised the present industrial dispute. It was a collective dispute which was referred to this Tribunal for adjudication. When the union has been held to have no locus stands to espouse the cause of Umapada Khumbhakar the reference is not maintainable, I see the Division Bench case of Calcutta High Court in Deepak Industries 1td and another vs. State of West Bengal and Others, 1975 Lab. IC 1133. In Swapan Dasgupta v .1st Labour Court, West Bengal, 1976 Lab. IC 202 at 206, Para 9 it has been held by Sabyasachi Mukherji J. that when the reference is not under Section 10 read with Section 2A, that is to say, the reference has not been made on the ground that there is a dispute existing between the employer and the individual workman, the reference cannot be upheld on the ground of Section 2A of the Act. Further more, it has to be noticed that it is a case of non employment, that is, stopping the concerned workman from work and not a case of dismissal, discharge of termination of service and hence Section 2A of the Act can have no application.

Accordingly I hold that the present reference is not maintainable and it is dismissed as such.

Dated, Calcutta,

The 2nd November 1982.

Sd/-

M P. SINGH, Presiding Officer [No. L-19012(63)/77-D.IV(B)] S. S. MEIIIA, Desk Officer

New Delhi, the 231d November, 1982

S.O 4018.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Hyderabad in the industrial dispute letween the employers in relation to the management of State Bank of Hyderabad and their workman, which was received by the Central Government on the 13-11 82.

For Petitioner

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL) :- AT HYDERABAD.

INDUSTRIAL DISPUTE NO. 9 OF 1982.

BETWEEN :

The Workmen of State Bank of Hyderabid.

AND

The Management of State of Bank of Hyderabad.

APPLARANCES .

Sri B. V. Raghavulu, President, State Bank of Hyderabad Staff Association for Workmen.

Sri K Srinivasa Murthy, Honourary Secretary, Andhra Pradesh Federation of Commerce and Industry, Hyderabad for Monagement.

AWARD

By Order No. L-12011/41/81-D II(A), dated 19-2-1982, The Government of India referred the following industrial dispute existing between State Bank of Hyderabad and their Workmen to this Industrial Tribunal for adjudication:—

"Whether the management of State Bank of Hyderabad is justified in discontinuing the subsidised transport facility provided to the Workmen working at their Ramehandrapurum Branch, Medak District, Andhra Pradesh with effect from 1st lune, 1981?"

- 2 After the above industrial dispute was taken on file in I. D. No. 9 of 1982 on 25-2-1982, notice were issued to both sides. The workmen engaged their representative, namely. Sir B. V. Raghavalu, whereas the Management engaged Sir K. Smirasa Murthy. The Workmen took some adjournments for filing their claims statement. Then both parties represented that the matter was under talks of compromise.
- 3 Ultimately today both the parties, representing that they settled this dispute out of Court, filed a joint memo withdrawing the industrial dispute. Accordingly permission was granted to the parties for withdrawing the dispute and this Award is passed. A copy of the joint memo is appended to this Award

Dietated to the Stepographer, transcribed by him and corrected by me and given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 29th day of October, 1982.

INDUSTRIAL TRIBUNAL.

APPENDIX OF FVIDENCE:

--NIL---

S. V. RAMANA REDDY, Presiding Officer.

[No. L-12011/41/81-D.H(A)] N. K. VERMA, Desk Officer

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL) AT HYDFRABAD A. P.

Industrial Dispute No. 9 of 1982

BETWEEN

The Workmen of State Bank of Hyderabad.

AND

The Management of State Bank of Hyderabad.

JOINT MEMO LILED BY BOTH THE PARTIES

It is submitted that

The petinoners pray that the petidon be treated as withdrawing as the dispute no longer exists.

For Management (P. V. Bapicaju)

Manager, Personnel Administration Dept. State Bank of Hyderabad

Hyderabad,

Hyderabad. 29-10-82.

(B. V. RAGHAVULU, President)

State Bank of Hyderabad Staff Association.

New Delhi, the 24th November, 1982

S.O. 4019.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government bereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Court No. 1, Bombay in the industrial dispute between the employers in relation to the Food Corporation of India, Bombay and their workmen, which was received by the Central Government on the 6th November, 1982.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1 AT BOMBAY

PRESENT:

Justice M. D. Kambli Fsqr, Presiding Officer

Reference No. CGIT 24 of 1978

PARTIES:

Employers in relation to the Food Corporation of India.

AND

Their Werkman

APPEARANCES:

For the employer. -- Mr. S. G. Ghate, Advocate.

For the workman, -- Mr. A. R. Atrey, Advocate,

INDUSTRY: Food Corporation

STATE :

MAHARASHTRA

Camp :

Nagpur

Nagpur, the 20th October, 1982

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, by order No. L-42012(7)/78-D. 11(B). dated 4th December, 1978, in exercise of the powers conferred by clause (d) of subsection (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred to this Tribunal for adjudication an industrial dispute between the employers in relation to the management of the Food Corporation of India and their workman in respect of the matters mentioned in the schedule given below.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of the Food Corporation of India (Maharashtra Region), Bombay in removing Shri D. C. Thakkar, Jeep Driver, from service with effect from the 23rd March, 1977 is justified? If not, to what relief is the said workman entitled?"

2. The workman, D. C. Thakkar, Ieep Driver, vas in the employment of the Food Corporation of India (Maharashtra Region) He has been removed from service after hold-

ing a domestic inquiry with effect from 23 3-1977. The point to be decided in this reference is whether the action of the management in removing the workman from service is justified.

- 3. The workman was chargesheeted on the following charges:—
 - "(1) That in spite of repeated instructions given, Shri D. C. Thakkat, Driver Grade II refused to comply with and obey lewful orders and refused to wear uniform thus contravened conduct Regulation 31(d) and 32 of the F.C.I. (Staff) Regulations, 1971.
 - (2) That Shri D. C. Thakkar, wilfully absented from duty w.e.f. 16-9-75 to 26-12-75 and again w.e.f. 5-1-1976 till date to avoid wearing uniform thus contravened Regulation 24(iv) & (vi) of FCI (Staff) Regulations, 1971.
 - (3) That Shi D. C. Thakkar, misbehaved with the acting District Manager, Shri N. G. Tongachkar on 12-8-75 and also with the Assit. Manager (Audit) camp Nigpur during August 1975 when he was instructed in writing to wear uniform, contravening the conduct Regulation 31 of the FCI (Staff) Regulations. 1971.
 - (4) That Shri Thakku, purchased 20 liters petrol on credit compons, when there was sufficient petrol in tank of Jeep No. MPJ-8883 and 20 liters petrol could not be accommodated in the tank. Thus Shri Thakker has misappropriated and used petrol for non-official use.
 - (5) That Shri D. C. Thakkar, Driver is doing private business of plying three wheeler as Taxi, contravening the conduct Pepulations 24(iii) and 45(i) of the FCI (Stair) Rev Patr ns. 1971".
- 4. One Miss. I. M. rahiha ii was appointed as the Inquiry Officer. She issued a notice dated 20th October, 1976, calling upon the workman to attend the hearing on 29-11-1976. Accordingly, the Inquiry Officer held the inquiry which she called the preliminary hearing on 29-11-1976 at the office of the Zonal Manager, Mistry Bhavan, Bombay. Accordingly, the delinquent workman remained present before the Inquiry Officer on hat date. It is not in dispute that on that day the workman appeared before he Inquiry Officer and admitted the charge No. 1 viz., that inspite of repeated instructions given to him he refused to comply with them and refused to went uniform thus contravening conduct Regulation 31(d) and 32 of the F.C.I. (Staff) Regulations, 1971. At that time, he did not admit the other charges.
- 5. According to the employer-corporation, later on, on the same day, the workman gave a letter to the Inquiry Officer which stated:—
 - "With reference to to lay's proceedings of the inquiry, I agreed for the charges against me and I therefore request you, kindly to excuse me and further I request for appology."

According to the employer, on the same day he submitted his resignation to the Fegion 1 Manager, Food Corporation of India, Bombay, with a copy addressed to the District Manager, Food Corporation of India, Nagpur. However, before this letter admit ing the other charges was given to the Inquiry Officer, the inquiry proceedings of that day i.e. of 29-11-1976 were closed and the next date for the inquiry was fixed on 13-12-1976.

- 6. According to the employer, as the workman had filed a letter admitting all the charges he did not appear before the Inquiry Officer on 13-12-1976. The Inquiry Officer, therefore, submitted her report on 14-12-1976 to the Regional Manager (Maharashtra), Food Corporation of India, informing him:
 - "Since the official has admitted all the charges and therefore there is no necessity for any further en-

- quiries to be conducted into the charges framed against him. Moreover it is learnt that the official has also submitted his resignation to the office. Under the circumstances ro further action appears to be taken by the Inquity Office. The enquiry is therefore treated as completed from my side."
- 7. After the said report was received from the Inquiry Oh. C., the Regional Manager (Maharashira) issued a show-caute notice to the workman informing him that he had come to the cenely ion that the workman was not a fit person to be retained in service and he proposed to impose on him the penalty of removal from service. The workman was called upon to show-cause against the proposed penalty.
- 8. The workman gave a reply to the show-cause notice on 12-2-1977 stating ther in that he had accepted only the charge No. 1 and that some writing was obtained from him in which it was said that he had accepted the other charges also. In this reply the workman denied that he had accepted the other charges. He, timefore, requested that he may be given a chance to defend him before the Inquiry Committee. The Regional Manager (Maharasht a) did not accept this representation and he proceeded to remove the workman from service from the date the order was served on him.
- 9. In the statement of claim the workman stated that he had admitted charge No. I in the morning at about 11 or 11.30 a.m on 29-11-1976 before the loquiny Officer Thereafter, he was called by the Inquiry Officer in the afternoon for collecting the relieving order to enable him to collect his train farc, etc. The nonkman alleged that when he went before the Inquiry Officer in the afternoon she started effering inducements. His version in the statement of claim is as follows:—
 - "It may be stated here that though the workman is Gugarathi, he knows Sindhi. The Inquiry Officer was also a Studhi lady and she induced the workman to admit charges tramed against him by observing that he would only be warned in the matter and nothing would be done to him. She also made it clear to the workman that in case he does not accept the course suggested by her of admitting the charges framed against him, he would find himself in a very tight position. She also had promised and assured the workman that she shall see that he gets all the leave, dues etc. In case he accepts the charges. It is during the talk the workman had also informed the Inquiry Officer that on account of the behaviour of Shri Rathod, he does not want to work under him. It is in this background, the Inquiry Officer collected two documents from the workman on or about 29-11-76. Those documents do not represent the true state of affairs. Latter dated 29-11-76 wherein the alleged claim is made that all the charges are admitted by the workman, is not a voluntary admission on the eart of the workman; nor it is an admission of the fact that he his committed any mission of the fact t

It will thus be seen that the workman wanted to say that the Inquiry Officer had induced him to give some writing and collected two documents from him viz., the document admitting all the charges and the other document of resignation. The version of the management is that the letter of resignation was sent by the workman direct to the Regional Manager, Bombay.

- 10. A preliminary inquiry was therefore held as to whether the inquiry conducted against the workman was fair and proper. In that preliminary inquiry the employer examined the Inquiry Officer, Mis, I. M. Tahilianl. She was cross-pamined at leath by Mr. Atrey, the learned coursel for the workman. The workman also examined himself. There is on record an application given by the workman to the Inquiry Officer on 29-11-1976 (exhibit XE-33). The text of the application is as follows:
 - "With reference to today's proceedings of the inquiry.
 I agreed for the charge, against me, and I, therefore,

request you kindly to excuse me and further I request for appology. Further it is requested to do the necessary in my favour on humanitarian ground as I am having a family and I did not receive the salary since Sept., 1975

The workman admits that this letter bears his signature. There is another application dated 29-11-1976 (exhibit E-4) by the workman to the Regional Manager, Food Corporation of India, Bombay, whereby he submitted his resigna-tion from the post of Driver grade II at Nagpus and requested the Regional Manager to accept the same at The workman admits that this application also early date. bears his signature. In the preliminary inquiry held by me as regards the fairness of the departmental inquiry the version of the workman was that the Inquiry Officer had got the two above documents written from some clerk and that she had induced him to sign them. The version of the Inquiry Officer was that the workman handed over to her the letter at exhibit E-3 in the afternoon of 29-11-1976 in the earlier part of the day in which admittedly the work-main admitted the charge No. 1 The Inquiry Officer stated in the preliminary inquiry held by me that when the work-man handed over to her the letter at exhibit F-3 she asked him why he was admitting all the charges. The workman then told her that he had already submitted his resignation to the competent authority i.e. the Regional Manager, Bombay and therefore he was not interested in the job and he was therefore admitting all the charges. The varsion of the workman as regards the document or resignation i.e. exhibit L-4 was that the liquiny Officer had prepared the document and had obtained his signature telling him that it was in respect of the sanction of his leave. The version of the workman in respect of the document at exhibit E-3 wherein he is said to have admitted all the charges is that he was told that it was in respect of the admission of the charge In my order on the preliminary point dated No. 1 only. 27-8-1982 I have disbelieved the version of the workman as regards these two documents. I have given my reasons in that order. I have held there that the workman wanted to tesign on his on accord as he was not pulling on well with his immediate superior one Mr. Rothod, the District Manager, Nagpur. I have also held that the workman voluntarily admitted all the charges against him, probably to ensure that he was leniently dealt with in respect of the sanctioning the leave to his credit and other benefits, if any. Rejecting all the contentions raised on behalf of the workman I held in my order on the preliminary point dated 27-8-1982 that I did not find any substantial infirmity in the inquiry proceedings and that the workman had voluntarily admitted at the charges. One of the charges framed against the workman was that he was doing private business while remaining absent from duty and that he has been plying a three wheeler as taxi. It is therefore probable that he was not interested in his job under the present employer. I have therefore pointed out in my said order that this may be one of the reasons why he wanted to resign the job and to admit all the charges in the inquiry.

11. It is not in dispute that he admitted the charge No. 1. It is not in dispute that he signed the letter dated 29-11-1976 (exhibit F-3) in which he admined an the that he had I have rejected the contention of the workman that he had I have rejected the contents there of on (exhibit F-3) in which he admitted all the other charges. signed that letter not knowing the contents there of on account of some inducement offered by the Industry Officer. The charge No. 1 is as follows:-

"That inspite of repeated instructions given. Shri D C. Thakkai, Driver Gride II refused to comply with and obey lawful orders and refused to wear uniform thus contravened conduct Regulation 31 (d) and 32 of the F.C.I. (Staff) Regulations, 1971.

The other charges which are set out in paragraph 3 above show that the workman wilfully absented form duty for a substantial period. He misbehaved with the acting District Manager, Mr. N. G. Tongaonkar on the date mentioned in the charge and also with the Assit Manager (Audit) camp Nagar when he was instructed in valting some time in the month of August, 1975, to wear uniform. He purchased 20 littee of petrol on credit coupons when there was sufficient petrol in the tank of the jeen and thus misappropriated and

used petrol for non-official use. He was doing private business of plying a three wheeler as taxi thereby contravening the conduct Regulations 24(iii) and 45(i) of the F.C.I. (Staff) Regulations, 1971. The regulations of the employercorporation which he contravened by committing the above nots have been set out in the charges.

- 12. The question for consideration is whether the punishment awarded to the workman is justified. Now, the punishment awarded upon the workman is justified, from the parties ment imposed upon the workman by the competent authority, Regional Manager, (Maharashtia) is one of removal from service. Mr. Ghate, the learned counsel for the employer, submitted that the charges admitted by the workman merited the punishment of dismissal. However, on compassionate ground the punishment awarded against him is only one of removal from service. I am inclined to hold that no interference is called for the in the punishment awarded to the workman.
- 13. Mr. Atray, the learned counsel for the workman, submitted that as the workman had tendered his resignation, further departmental proceedings should have been dropped. He also submitted that the punishment at any rate is highly disproportionate to the charges held proved against the workman. His arguments further was that the competent authority who awarded the punishment was not examined on behalf of the employer and did not offer himself for crossevamination. I do not find any substance in any of the submissions. Admittedly the workman admitted the charges That charge, in my opinion, is sufficient to merit the punishment awarded to the workman.
- 14. I therefore find that the action of the management of the Food Corporation of India (Maharashtra Region), Bombay, in removing the workman, D. C. Thakkar, from service with effect from 23-3-1977 is justified, and, therefore, the workman is not entitled to any relief.
 - 15. My award accordingly. No order as to costs

M. D. KAMBLI, Presiding Officer, [No. L-42012(7)/78-D II(B)]

S. S. PRASHER, Desk Officer,

New Delhi, the 24th November, 1982

S.O. 4020.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 2, Bombay, in the industrial dispute herman the application to the management dispute between the employers in iclation to the management of Punjab National Bank, Bombay, and their workman, which was received by the Central Government.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, BOMBAY

Reference No. CGIT-2/2 of 1982

PARTIES:

Employers in relation to the management of Punjab National Bank

AND

Their Workmen.

APPEARANCES:

For the Employers-Shri Gurbachan Singh, Manager (Staff)

For the workmen—Shri K. N. Mehrotra, Vice-President, A.I.P.N.B. Employee, Association, 2. Shri G. L. Kadam, General Secretary, P.N.B. Staff Union.

INDUSTRY: Banking.

STATE: Maharashira.

Bombay, the 19th October, 1982

AWARD

By_their_ouder No. L-12012/8/81-D.II(A), dated 6-1-1982 the Central Government have referred the following dispute for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Dis-

"Whether the action of the management of Punjab National Bank, Bombay in refusing to grant extra allowance to Shri G. L. Kadam, Clerk, is justified? If not, to what rehef is the workman concerned entitled?"

- 2. On the allegation that the clerk-cum-typist Shri G. L. Kadam besides his routine duties was performing other extra duties like Care-taker officer looking after the property of the Bank both moveable and immovable and also performing some additional duties, the Union who is espousing the cause of the workman namely Punjab National Bank Staff Union has made a demand for special allowing as payable to Special Assistant from 18-8-1965 till June 1973 and in the statement of claim, although the order of reference does not speak to this effect, a further demand that from July, 1973, the clerk-cum-typist should be promoted in the grade of an officer grade 'C' or in the alternative as a Special Assistant.
- 3. The claim is refuted by the Respondent Bank on whose behalf written statement is filed at Ex. 2/M and rejoinder at Ex. 16/M, denying the allegation that the clerk-cum-typist was performing any extra duties involving greater skill and responsibilities and therefore according to the Bank the employee concerned is not entitled to any extra allowance as claimed neither under any award nor under the Bipartite Settlements and as such the claim is not entertainable.
- 4. On the strength of these pleadings the following issues arise for determination and my findings thereto are:—

ISSUES

FINDINGS

1. Whether the Union proves that Shri G.L.Kadam was performing special duties as contended?

Doing extra dutie,

2. If yes, was he entitled to special allowance as claimed?

Extra allowance of Rs.50/-per month.

3. Whether in the light of the order of reference the question regarding the wearingful designation as tried to be plouded by the Union in the statement of claim can be gone rate?

No

4. What award

As per award'

REASONS

5. In support of the contention that Shri Kadam was petforming some extra duties besides his normal duties namely the routine duties there is the evidence of the clerk concerned Ex. WW whereby stating that he was performing some extra duties namely attending to the complaints of the tenants occupying the Bank's quarters, attending the Corporation office to obtain permission for carrying out additions and alterations of the property of the Bank, examining the work of repairs carried out in the building and also the repairs to furniture and fixtures and to see whether the repairs were carried out according to the specification and to report to the superior officer and to attend the property cases pending in the courts, attending the office of the Bombay Telephone for obtain in additional lines, attending various garages for obtaining quotations for carrying out repairs to vehicles of the Bank, attending the office of the R.T.O. for getting the vehicles passed and to pay taxes. He used to purchase cloth from the market for preparing the uniform for the s'aff in the region and verify the petrol bills of the cash-Vans, looking after the work of contractors undertaking repairs to Typewriters, Water-coolers, Air conditioners etc. and to see the same is done according to the specification, to arrange disposal and auction of urserviceable goods, attending the office of the Controller of accommodation for obtaining N.O.C. and booking Railway and plane tickets for the executives, obtaining quotations for purchase of stationery and to visit the shops and make recommendations to the Manager and also to be incharge of the furniture and fixtures lying in the residential houses of executives on transfer.

- 6. Though in the cross-examination the actual nature of duties was tried to be challenged, the fact that all duties were performed by the employee is also stated by another two witnesses serving in the same Bank S/shir B. L. Desar and S. V. Pikelay and further there is an important piece of evidence in the shape of report by the Manager under whom Shiri kadam was then serving recommending the grant of Rs. 50 P.M. as special allowance. Shir B. L. Desar who is serving as a Special Assistant says that from June, 1981 he is serving in Property Section of the Bank and that before him Shiri kadam was performing the duties in the said Section and there is further admission that his duties were wider than the duties performed by the Special Assistant. But Special Assistant performing certain duties would not make them duties of a Special Assistant for which purpose we shall have to refer to the Award and Settlements especially Chapter V and Appendix B of Bipartite Settlement of 1966. Another witness Shir S. V. Pikelay refers to the attendance of Shri Kadam in the Municipal Corporation office in connection with Bank work, but this evidence is not of much help to the Union.
- 7. It is evident that the claim of Shri Kadam or the Union on his behalf cannot be for special allowance as admissible and defined under Chapter V of the Bipartite Settlement dated 19-10-1966, for such special allowance an employee must be appointed as a Special Assistant and performing such duties for which certain modalities have been prescribed in the tarlier awards. Consequently unless and until Shri Kadam was entitled to become a Special Assistant or performing duties as laid down he could not have claimed special allowance pyable to the Special Assistant.
- 8. This however does not mean that if there is proof of his performing extra duties, duties not routine, of a clerk-cumtypist and further the duties for which he was required to work during odd hours and not restricted to the office hours, then the claim of the workman shall not stand justified, especially when the record speaks that for such type of duties outsiders were demanding Rs. 800 per month, and that too for attending the work for one or two hours a day.
- 9. Apart from the oral evidence, there are the various reports of the Manager under whom Shri Kadam was then serving. At Ex. 20/M there is a Memorandum dated 25-7-73 written by the Manager, P.N.B. House, to the Senior Rigional Manager recommending the sanction of an allowance to the tune of Rs. 50 per month since Shri Kadam according to him was well trained in attending to such type of work re-ferred in the letter. The Asstt. Regional Manager however as can be seen from Ex. 21/M turned down the said recommendations, even then the Manager by another Memorandum dated 26-11-1973 Ex. 22/M made the same recommendation saying that it was not possible to requisition a sub-overseer and it would be economical to pay the same amount to Shri Kadam was posted as Clerk-cum-typist and in that capa-nother letter Ex. 25/M dated 19-8-1974 from the same Manager to the Regional Manager followed by another letter Fx. 26/M dated 30-9-1974 and Ex. 27/M dated 7-10-1974. When all these letters are reach together, the only conclusion nos ible is that besides his normal duties Shri Kadam was performing some extra duties to the knowledge of the Manager under whom he was placed and said authority was also satisfied nbout the legitimacy of the employee's claim, We know that Shii Kadam was posted as Clerk-cum-typist and in that canacity he could not have been expected to attend the Municipal Cornoration office to obtain permission for carrying on addit ins and alteration of the property of the Bank, to examine the work of renairs carried out in the buildings and repairs was corried out according to the specification and to attend various offices in connection with the Bank's work and he was not adhering to the office hours and even the manager in his letter says that he was required to work at odd hours. Considering therefore the proof rendered by the Manager's correspondence although the superior authorities were not comminced of the legality of the claim, having regard to the totality of the evidence and having regard to the fact that a sub-overseer would have been required to be appointed for neiforming the same duties and that subsequently the Pank approinted as Special Assistant agreeing to pay him Rs. 283 as special allowance for doing the same type of duties done hy Shri Kadam. I am convinced that he was performing extra duties as contended and that his claim for extra allowance can be said to be just and legitimate.

- 10. From the representation of Shri Kadam which is referred in the Manager's letter dated 25-7-1973, Ex. 20/M it seems that for the first time the incumbent started claiming extra emoluments from July, 1973 though he was on that job since 1965 and if the incumbent himself realised about the extra duties in the year 1973 and then started moving in the matter, despite the proof that he was doing the same type of work earlier in point to the time he claim will have to be restricted to the period from July, 1973 and not before.
- 11. Once it is appreciated that what is claimed is not special allowance which cannot be claimed by Shri Kadam as he could never be appointed as special Assistant till 16-8-81, the quantum of Special allowance can never be Rs. 283 which is the special allowance prescribed under the Bipartite Setdement. The Union has got produced various correspondence and since the Manager who was the best person under whom Shri Kadam was working has recommended to grant Rs. 50 as allowance, it carries great weight. What was the representation of Shri Kadam is not on record but the fact that the correspondence was got produced shows that the Union also must be agreeing with his recommendations. Considering therefore that it is not special allowance but at the same time considering that Shri Kadam was performing extra duties other than the normal routine duties that too during odd hours which fact the Bank has admitted, I am convinced that he is entitled to extra allowance of Rs. 50 from July, 1973 to the end of July, 1981.
- 12. There is a prayer that either Shri Kadam should be granted the special allowance as Special Assistant or he should be promoted as Officer in grade 'C' but in the light of the order of reference, the prayer can never be considered as the prayer falls outside the scope of reference. I may add here that for promotion as officer there are certain formalities prescribed, similarly for the posting as Special Assistant there are certain modalities. So far as the promotion to the Officer's cadre, not only there is seniorily but also it depends upon how Shri Kadam is suitable to the post which can be judged by the superior officers of the Bank appointed for the same purpose. While deciding the present reference I can not considered the claim for promotion or for his posting as Special Assistant, as such request to this effect cannot be considered at all. The only conclusion is that Shri Kadam is granted extra allowance of Rs. 50 per month for the period as stated earlier. The Bank is to calculate the extra allowance and accordingly to pay the same to the concerned employee within one month from the date of this Award. No order as to costs,

M. A. DESHPANDE. Presiding Officer
[No. L-12012(8)/81-D.H(A)]
Central Govt. Industrial Tribunal
N. K. VERMA, Desk Officer.

New Delhi, the 24th November, 1982

S.O. 4021.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Acr. 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of New India Assurance Company Limited, Calcutta, and their workmen, which was received by the Central Government on the 11th November, 1982.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL. CALCUTTA

Reference No. 60 of 1980

PARTIES:

Employers in relation to the management of New India Assurance Company Limited, Calcutta

AND

Their Workmen.

PRESENT:

Mr. Justice M. P. Singh, Presiding Officer.

APPEARANCES:

- On behalf of Employers—Mr. T. N. Mukherjee, Labour Adviser for the management.
- On behalf of Workmen-Mr. Anil Das Choudhury, Advocate,

STATE: West Bengal, INDUSTRY: Insurance.

AWARD

By its Order No. L-17011/5/79-D.IV(A) dated 15th July, 1980 the Government of India, Ministry of Labour, referred the following dispute to this Tribunal for adjudication:

- "Whether the action of the management of New India Assurance Co. Ltd., Calcutta in denying efficiating position and officiating ellowance to Shri N. C. Tarafdar, Assistant at Area Office Accounts and Shri M. Dhara, Assistant et Division No. 3, with effect from 7th July, 1976 is justified? If not, to what relief are the conterned workmen entitled?"
- 2. The two questions to be determined in the present case are, (i) whether the two assistants aforesaid officiated in the port of Senior Assistant and (ii) whether they are entitled to officiating allowance from the management for the same with effect from 7th July, 1976. In my opinion the answer should be in the affirmative.
- 3. WW-1 Nemai Chandra Tarafdar, the Assistant (No. 4643) of the Area office Accounts is one of those two. His evidence is that he acted in officiating capacity on the post of Senior Assistant K. P. Nair from March, 1976 to March, 1979 when K. P. Nair Senior Assistant was promoted as acting Superintendent, under verbal order of the Assistant Manager R. Krishnan. His further evidence is that that was a higher post and that all the relevant documents concerning his officiating position were lying with the management; that he while acting in the post of Senior Assistant performed the duties mentioned in the letter Ext. W-1 dated 29th March, 1978. Those duties are also mentioned in para (8) of the written statement and run as follows:—
 - (i) G.I.C. Premium Statistics (Eastern Region).
 - (li) Area performance Gross Direct premium Income.
 - (iii) Monthly premium in respect of number of claums paid and outstanding summary (Eastern Region).
 - (iv) Number of documents Summary.
 - (v) Codewise analysis of Misc. Disbursement book.
 - (vi) Various,"

He has further said that M. Dhara, another Assistant also officiating in the higher post of Senior Assistant and he too performed underwriting work in connection with the Inspector Code. The witness has also deposed that Barin Ghoss and Prudeep Kumar Dutta got officiating allowance for having done the work of Mr. Taimol in the Marine Claim Deportment, that they also had worked under the verbal order and similarly one Chakraborty (Samar Chakraborty as per written statement) and N. Chanda got officiating allowance. These two had worked with Mr. M. Dhar and they also had worked under the verbal order. In the cross-examination WW-1 says that there is clear division between the work of the Assistant and the work of Senior Assistant, that the work of underwriting is done both by Assistant and Senior Assistant. He explained it by saying that an Assistant does it without correspondence. He has further deposed that in the branch and Divisional office either Assistant or Senior Assistant does the work of statistics but in the Area office or

in Controlling office the it is done only by Senier Assistant. It is needless of say that WW-1 is in the Area office. I see no reason to disbelieve him.

- 4. The managements own letters to the various Assistants go to show that the fact of officiating was not challenged. Ext. M-1 is letter dated 27th June, 1978 written by the management to Samarendra Chakraborty, another letter Ext. M-2 dated 5th December, 1979 written to Subir Chakraborty (with whom N. Dhar and N. Chanda had worked) and Ext. W-2 the letter written to WW-1, namely, Mr. Tarafdar indicates that the fact of officiating was not in dispute. All these persons had claimed officiating allowance The claim was considered and rejected on the ground that officiating allowance was not admissible as per provisons officiating allowance. The claim was rejected on a vague technical ground and not on the ground that they did not officiate.
- 5. The argument of the management before this Tribuhas not examined R. Krishnan, the Assistant Manager under not at all correct. It is to be noted that the management has not examined R. Krishnan, the Assistant Manager under whose verbal order WW-1 claim to have acted in officiating capacity. It is also to be noted that in the written statement the management raised only preliminary issue and did not deny the fact officiation. In the written statement which is on record only preliminary objection has been stated. No. statement about the fact of officiating has been made. The reference is of the year 1980. Even within this period of two years and more no other written statement on merit has been filed. There is thus no denial of the fact of officiation. So far as the preliminary objection is concerned it is frivolous and at the very commencement of the hearing of the case I nonted it out and then evidence was taken on merit. The witness of the union was cross-examined by the management and the case has been heard on merit only. From the various letters aforesaid indicating that the fact of officiation was not in dispute, from the absence of denial in the written statement of the management and from the evidence of WW-1 N. C. Tarafdar I come to the conclusion that the two Assistants officiated in the post of Senior Assistant. There can be no doubt that the two nosts are different with difference scales of nav. The post of Senior Assistant carries a scale of Rs. 230 735 and the post of Assistant bas the scale of Rs. 175-585. The contention of the management that there is
- 6. The next question is whether the two Assistants are entitled to officiating allowance. There can be no doubt that they are entitled. Clause 15 of the General Insurance (N fichalisation) and Revision of Pay Scales and other conditions of service of Supervisory Clerical and Subordinate Staff) Scheme, 1974 runs as follows:
 - "15. Officiating Allowance—An employee may be required to hold officiating charge of a post in a higher category or additional charge of an equivalent post whenever considered necessary and where such officiating charge or additional charge is held for a continuous period of 15 days or more, the employee shall be paid a pro-rata allowance as follows, namely:—
 - (i) Officiating in a higher category of post: 20 per cent of his basic salary, subject to a maximum of Rs. 1000/- per month;
 - (ii) Additional charge of an equivalent post: 10 per cent of his basic salary, subject to a maximum amount of Rs. 50/- per month."

On a perusal of the above it is obvious that the two Assistants concerned in the present case are entitled to officinting allowance. The management argued that there was doubt and difficulty in the interpretation of this clause and so in 1001 GI/82—4

paragraph 21 of the 1974 Scheme it is the Central Government which can decide the dispute and not this Tribunal. The point has no froce. I do not see any doubt or difficulty in interpreting the provisions of Clause 15. The words of this clause are plain and unambiguous. It clearly confers light on an employee to get officiating allowance on pro-rata basis as mentioned therein. The contention is, therefore, rejected.

7. In the result my award is that the action of the management in denying officiating position and officiating allowance to Sri N. C. Tarafder Assistant at Area office Accounts and Sri M. Dhar, Assistant at Division No. III with effect from 7th July 1976 is unjustified. Both these Assistants are held to have officiated in the post of Senior Assistant as claimed by them and both are entitled to office and allowance admissible in Clause 15 of General Insurence (Nationalisation and Revision of Pav Scales and other conditions of service of Supervisory, Clerical and Subordinate Staff) Scheme, 1974,

[No. L-17011(5)/79-D.IV(A)] M. P. SINGH, Presiding Officer

Dated, calcutta the 7th October, 1982

New Delhi, the 25th November, 1982

S.O. 4022.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Bombay in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Life Insurance Corporation of India, Nasik Division and their workmen, which was received by the Central Government on the 9th November, 1982.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, BOMBAY

PARTIES:

Employers in relation to the Management of Life Insurance corporation of India Nasik Division.

AND

Their Workmen

APPEARANCES:

For the Employers-Shri P. R. Pal, Advocate.

For the workmen—Shri V. D. Kalhurla, Jt. Secretary, All India Life Insurance Corporation Employees' Federation.

STATE: Maharashtra INDUS

INDUSTRY: Insurance

Bombay, dated the 18th October, 1982

AWARD

By their order No. L-17011/4/78-D.IV(A) dated 15-4-1980 the following disputes pertaining to Nagpur Division has been referred for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act and subsequently by order No. L-17025/4/30-D.IV(A) dated 31-3-1981 the Nasik Division of the Life Insurance Corporation of India was added:

- 'Whether the demand of the existing empanelled badli workmen In Nagpur and Nasik Divisions of the Life Insurance Corporation of India for their absorption as regular employees is justified? If so, to what relief and from which date are the concerned workmen entitled?"
- 2. The Parties including Vima Karamchari Sanghatana Nasik have filed their pleadings and the written statement of Sanghatana assumes importance that being the only Union which is dontesting the whole claim.
- 3. Now though as reference stands speaks of the existing empanelled badli workmen, the Union in paragraph 17 of Ex. 13/W states that there is no panel of Badli workmen at Nasik. Because of this assertion the contention raised on behalf of the Life Insurance Corporation of India is that when there was no panel, while the reference speaks of existing empanelled badli workmen, and if it is the order of reference which gives and confers jurisdiction to entertain the dispute, the present reference would not be sustainable in the absence of any panel. There is great force in this contention and when the order of reference is specific I cannot read in between the line or something different than what it speaks and the only course open to the Tribunal is to dispose of the reference on the ground that it is not sustainable This order is not being passed on merits nor the real dispute is being decided and therefore if the parties especially the workmen are in a position to raise a dispute, the disposal of the present reference on the issue in question should not create any bar in their path.
- 4. I was given to understand that with regard to similarly placed badli workmen at Nagpur, the Life Insurance Corporation of India entered into a settlement with the Union representing the case of those workmen whereby certain rights have been conferred and they have been absorbed in service, in terms of which settlement I am told there is an award passed by the Tribunal. When therefore the Life Insurance Corporation has entered into a settlement with regard to similarly placed employees at Nagpur, apart from the technical defect as noted, when the case of the employees at Nasik is on par with their counterpart at Nagpur, the Corporation should consider whether those very benefits which it has decided to extend to the Badli workmen at Nagpur should not be conferred on the workmen similarly placed at Nasik, since their contentions are of similar nature and they are alleged to have put in certain years of service in the Corporation. After all the Corporation has to give lead to other employers so that no cause for any just grievance remains.

No order are to costs.

Dt: 2-11-82.

M. A. DESHPANDE, Presiding Officer [No. L-17025/4/80/DIV(A)]

T. B. SITARAMAN, Desk Officer.

New Delhi, the 25th November, 1982

S.O. 4023.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 3, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Kenda Area of Messrs Eastern Coaifields Limited, Post

Office Bahula, District Burdwan, and their workmen, which was received by the Central Government on the 18th November, 1982.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT NO. 3. DHANBAD

Reference No 52/82

PRESENT:

Shrri J. N. Singh. Presiding Officer.

PARTIES:

Employers in relation to the management of Kenda Area of M/s. Eastern Coalfields Ltd., P.O. Bahula, Dist. Burdwan.

AND

Their workmen

APPEARANCES:

For the Employers-Shri N Das, Advocate.

For the Workmen-None.

INDUSTRY : Coal.

STATE :West Bengal

Dated, the 9th November, 1982

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them U/S 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 14 of 1947 has referred the dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. 19012 (23)/82-D. IV (B) dated the 28th May, 1982.

SCHEDULE

- 'Whether the action of the General Manager, Kenda Area of M/s. Eastern Coalfields Ltd., P.O. Bahula, Dist. Burdwan in not properly designating and placing Shri Sushil Kumar Pathak and Paresh Chandra Mandal as Store Keepers in Clerical Grade-I, is justified? If not, to what relief are the workmen concerned entitled?"
- 2. After receipt of the Reference notices were issued to both the parties for submission of their written statement. The management filed their written statement on 10-8-82 but the union was absent inspite of notice. The case was adjourned to 1-9-82 and on that date also the union absented themselves. A fresh notice was issued to the union directing them to file written statement by 24-9-82 failing which the case will proceed exparte. On 24-9-82 also the union did not appear inspite of service of notice and again a fresh notice was issued fixing 22-10-82 for hearing but again the union did not appear nor filed any written statement.
- 3. Thus it is clear that the union is not taking any interest in the case and they have no dispute with the management.
 - 4. In such circumstances a 'no dispute' award is passed.

J.N. SINGH, Presiding Officer [No. L-19012/(23)/82-D.IV(B)]

S.O. 4024.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Goverument Industrial Tribunal No. 3, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Nimcha Colliery of Messrs Eastern Coalfields Limited, Post Office Jaykaynagar, District Burdwan, and their workmen which was received by the Central Government on the 18th November 1982

BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, NO. 3, DHANBAD

Reference No. 4/81

PRESENT:

Shri J. N. Singh, Presiding Officer.

PARTIES ·

Employers in relation to the management of Nimcha Colliery of Eastern Coalfields Ltd., P.O. Jaykaynagar, Dist. Burdwan

AND

Their workman.

APPEARANCES:

For the Employers-Shri N. Das, Advocate

For the Workman-None.

INDUSTRY : Coal.

STATE: West Bengal.

Dated, the 10th November, 1982

AWARD

The Govt, of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them U/S 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 14 of 1947 has referred the dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. L-19012(35)/ 80-D.IV(B) dated the 31st January, 1981.

SCHEDULE

"Whether the management of Nimcha Colliery of M/s. Eastern Coalfields Ltd., P.O. Jaykaynagar (Burdwan) was justified in not regularising Shri Kamta Prasad Gupta as Canteen Manager/Canteen Supervisor in Clerical Grade II with effect from 1-12-1977? If not, to what relief the workman is entitled to?"

- 2. On 9-11-82 both the parties have filed a joint petition of compromise duly signed on their behalf and they pray that an award be passed in term, of the settlement.
- 3. I have gone through the settlement which is beneficial for the workman.

4. In the circumstances the award is passed in terms of the settlement which shall form part of the award.

> I N. SINGH, Presiding Officer [No. L-19012(35)/80-D.IV(B)]

Enc : Settlement.

BEFORE THE HONOURABLE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 3, DHANBAD

Ref. No. 4 of 1981

PARTIES:

Employers in relation to the Management of Nimcha Colliery, ECL, P.O. Jaykaynagar, Dist. Burdwan

AND

Their workman

The Parties most humbly pray as under :-

That the above mentioned reference case has been fixed for hearing on 9-11-82.

That, the parties have discussed the matter and have come to an amicable settlement in favour of disposal of the case on the following terms and conditions,

- (a) the incumbent namely Sii Kamta Piasad and Gupta will be designated as Canteen Manager and will be placed in Clerical Grade-II in the pay scale of Rs. 508-23-692-29-808/- under the Wage Board for the Coal Mining Industry/NCWA-II with effect from 1-4-1982.
- (b) Sri Gupta will continue to be posted at Nimcha Colliery until further orders.
- (c) It has been also considered and agreed by parties that Srî Gupta would be given 3 increments in the aforesaid Clerical Gr. II on fixation/fitment of his basic salary in G1. II. The union or the workman shall have no claim for any other payments on any account relating to the dispute under disposal.
- (d) the instant settlement shall have no precedence. Under the aforesaid circumstances, the parties jointly pray for accepting the said terms of settlement by the Hon'ble Tribunal and to pass on Award accordingly for disposal of the case under the Reference No. 4 of 1981.

J. N. SINGH, Presiding Officer

For the Union representing the workman,

For the Fmployers,

Sd/-

(Shiv Kant Pandey).

Sd/-(D.R.K. Rac).

Secretary,

Personnel Manager,

Koyala Mazdoor Congress.

Satgram Area, ECL.

Satgram Area,

Filed by Sd/-

Dt. 8-11-82.

P. L. OJHA,

9-11-82 S. R.P.O. Salgram Area. S.O. 4025.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government Mereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 3, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Ningha Colliery of Messrs Eastern Coalfields Limited, Post Office Kalipahari, District Burdwan, and their workmen which was received by the Central Government on the 18th December, 1982.

BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT NO. 3, DHANBAD

Reference No. 57/80

PRESENT:

Shri J. N. Singh, Presiding Officer.

PARTIES:

Employers in relation to the management of Ningha Colliery, Eastern Coalfields Ltd., P.O. Kalipahari (Burdwan)

AND

Their workman.

APPEARANCES:

For the Employers-Shri B. N. Lala, Advocate.

For the Workman-None.

INDUSTRY : Coal

STATE: West Bengal

Dated, the 10th November, 1982

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them U/S 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 14 of 1947 has referred the dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. L-19012(63)/79-D.IV(B) dated the 23rd September, 1980.

SCHEDULE

- "Whether the action of the managemen t of Ningha Colliery, Eastern Coalfield, Ltd., P.O. Kalipahari, (Burdwan) in not changing the designation of Shri Rameshwar Yadav as Labour Supervisor and in not placing him in proper grade with effect from 1st Septmebr 1974 was justified? If not, to what relief is the concerned workman entitled?"
- 2. On 8-11-82 both the parties have filed joint petition of compromise duly signed on their behalf and they pray that an award be passed in their terms of the settlement.
- 3. I have gone through the settlement which is beneficial for the workman.
- 4. In the circumstances the award is passed in terms of the settlement which shall form part of the award.

BEFORE THE HON'BLE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT NO. 3, DHANBAD

Ref. No. 57 of 1980

PARTIES:

Employers in relation to the Management of Ningah Colliery of Eastern Coalfields Limited

AND

Their workman.

Joint petition of compromise:—
Both the parties, herein concerned, most respectfully submit and state as follows:—

- That the above matter is pending adjudication before the Hon'ble Tribunal.
- (2) That, in the meantime, both the parties mutually negotiated the instant dispute and have settled the dispute on the following terms:
 - (a) That the employers agree to post Sri Rameshwar Yadav, the workman, herein concerned in the post of Clerk in Clerical Gr. II of the National Coal Wage Board Recommendation NCWA-I and II within a week from the date of Honble Tribunal accepts this settlement.
 - (b) That the workmen agree that they shall have no claim whatsoever for any back wages in any matter arising out of the present dispute.
 - (c) That the settlement fully resolves the insant dispute.
 - (d) That the parties shall bear their own costs of the proceedings.
- (3) Both the parties pray that the Honble Tribunal may be pleased to accept this settlement on fair and reasonable and may be pleased to pass on award in terms of the settlement.

And for this act of kindness the parties as in duty bound shall ever pray.

Dated this the 6th day of November, 1982

Sd/- Sd/-

For and on behalf of the workman. For and on behalf of the General Scoretary.

Management.

[No. L-19012(63)/79-D.IV(B)] S. S. MEHTA, Desk Officer

आवेश

नई दिल्ली, 3 भगस्त, 1982

का॰आ॰ 4026---केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपायब प्रनुसूची में विनिविध्ट निषय के बारे में सेन्ट्रल बैंक प्राफ इंडिया, अयपुर के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध एक प्रीद्योगिक विवाद नियोजकों भौर उनके कर्म-कारों के बीच विद्यमान है;

भीर केलीय सरकार उक्त विवाद की न्यामनिर्णयम के लिए निर्वेशित करना बोछनीय समझती है;

सत: केन्द्रीय सरकार, भोधोगिक विवाद प्रक्षित्यम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क भीर धारा 10की उप-धारा (i) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त प्रक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक प्रौद्योगिक भिधकरण गठित करती है जिसके पोठासीन प्रक्षिकारी श्री रामराज खाल गुन्त होंगे, जिनका मुख्याक्षय जयगुर में होगा भीर उकत विवाद को उक्त प्रधिकरण को स्यायनिर्णयन के लिए निवैणित करती है।

अनुसची

च्या सेन्द्रल बैंक घाफ इंडिया, जयपुर के प्रबंधतंत्र की श्री एस० एस० शर्मा, उप-लेखापाल तथा एक संरक्षित कर्मकार की तारीख 19—10--66 के द्विपंकीय समझौते के उपवंधों के प्रनुसार बयूटी छुट्टी तथा याज्ञा भला/वैनिक भला न वेने की कार्यवाई व्यायोखित है ? यदि नहीं, तो संबंधित कर्मकार किस प्रमुतोय के हकवार हैं ?

[सं॰ एल-12012/269/81-की. II. ए.]

ORDER

New Delhi, the 3rd August, 1982

S.O. 4026.—Whereas the Central Government is of the opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Central Bank of India Jaipur and their workman in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A and clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitute an Industrial Tribunal of which Shri Ramtaj Lai Gupta shall be the Presiding Officer, with headquarters at Jaipur and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Central Bank of India, Jalpur in denying duty leave and payment of T.A./D.A. as per the provisions of Bipartite Settlement dated 19-10-66 to Shri S S. Sharma, Sub-Accountant, and a protected workman is justified? if not, to what relief is the workman concerned entitled?".

INO. L-12012/269/81-D. II(A)I

आबेगः-

नई' दिस्सी,' 10 ग्रगस्त, 1982

का ब्लार 4027 — केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपावड धनु-सूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में कर्नाटक बैंक लिए, हाबारी के प्रबंध-र्तक से सम्बद्ध एक भौद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है;

भीर केन्द्रीय सरकार उपत विवाद को स्थायनिर्णयम के लिए निर्वेशित करना बांछनीय समझती है ; धतः केलीय सरकार, बौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उप-धारा (i) के खंड (घ) द्वारा प्रवत्त मिल्तियों का प्रयोग करते हुए, एक बौद्योगिक धिधकरण गठित करती है जिसके पीठाक्षीन प्रधिकारी श्री बी॰ एच॰ उपाध्याय होंगे, जिनका मुख्यालय बेंगलीर में होगा और उक्त विवाद की उक्त प्रधिकरण की न्यायनिर्णयम के लिए निर्वेशित करती है।

अनत्वी

क्या कर्नाटक मैक लिं०, हुक्ली के प्रबंधतंत्र को हावारी शाका के धन निक्षेप प्रचारक श्री एस. सी. बेल्लारी की देय मासिक कमीश्रम की पेकने उसकी दिए गए संबहण कार्जों को मोगने तथा प्रबंधतंत्र के आर्थेश एं० 5306/81 सारीक 23-9-81 द्वारा 1-9-81 के भूतलकी प्रभाव से उसकी सेवाझों को समान्त करने की कार्रवाई ग्यायोचित है ? यदि नहीं तो कर्मकार किस-अमुवीच का हक्कार है ?

[स॰ एल-12011/75/81-डी.2ए.]

ORDER:

New Deihi, dated the 10th August, 1982

S.O. 4027.—Whereas the Central Government is of the opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Karnataka Bank Itd., Havari and their workman in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed:

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A and clause (d) of sub-section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri V. H. Upadhaya shall be the Presiding Officer, with headquarters at Bangalore and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Karnataka Bank Ltd, Hubli in with holding the monthly commission payable to Shri S. C. Bellary. Money Deposit Canvasser, Havari Branch in demanding collection cards given to him and in terminating his services with retrospective effect from 1-9-81 by order No. 5306/81 dated 23-9-81 of the manager is justifled? If not, to what relief is the workman entitled?".

[No. L-12011/75/81-D,II(A)]

आवेश

नई बिल्ली, 21 झगस्त, 1982

का० औं० 4028.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबत मनुसूची मैं विनिर्दिष्ट विषय के बारे में स्टेट वैंक भाष सौराष्ट्र के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध एक भीधोगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है ;

भौर केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निवॅशित करका विक्रतीय समझती है ;

भत : केम्डीम सरकार, भौद्योगिक विवाद भिर्मित्यम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उप-धारा (1) के खंड (म) द्वारा प्रदत्त सक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक मौद्योगिक भिर्मिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन भिर्मिकारी श्री जी एस बरीत होंगे, जिनका मुख्यालय घहमदाबाद में होगा और उक्त विवाद की उक्त भिर्मिकरण की न्यानिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची ं

"क्या स्टेट बैक ब्राफ सौराष्ट्र के प्रबंधतंत्र की श्री विजु भाई रायाभाई चेकासिया, गोवाम चौकीवार, जवाहर चौक शाखा सुरेन्द्र नगर, की सैव. 1-8-79 से समाप्त करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो संबंधित कर्मकार किस अनुसोष का हकदार है ?"

[सं॰ एल-12012/348/81-डी. 2(ए)]

ORDER

New Delhi, the 21st August, 1982

S.O. 4928.—Whereas the Central Government is of the opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of State Bank of Saurashtra, Surendranagar and their workman in respect of the matter specified in the Schedule hereto annxed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri G. S. Bafot shall be the Presiding Officer, with headquarters at Ahmedabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of State Bank of Saurashtra in terminating the service of Shri Vijubhai Rayabhai Chekhalia. Godown Chowkidar Jawahar Chowk Branch. Surendranagar with effect from 1-8-79 is justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled?".

[No. L-12012/348/81-D. II(A)]

आवेश

न'ई विस्ली, 23 प्रगस्त 1982

का॰ ऑ॰ 4029 — केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपायक अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के आरे में बैंक आफ बड़ौदा, अहमदाबाद के प्रवन्धर्तत से सम्बद्ध एक भौधोगिक विवाद नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है ;

भीर केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को व्यायनिर्णयन के लिए निर्वेशित करना बौछनीय समझती है ,

भत: केस्प्रीय सरकार, भौदोगिक विवाद श्रधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क भीर धारा 10 की उप-धारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रवस यक्तियों का प्रयोग करने हुए, एक श्रीद्योगिक श्रधिकरण गठित करती है जिसके पीठामीन श्रधिकारी श्री जी० एस० बरीत होने, जिनका मुख्यालय भहमदाबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त श्रधिकरणको न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची:

"क्या बैंक आफ बड़ौबा के क्षेत्रीय कार्यालय, प्रहमबाबाद के प्रबंधकंत्र की श्री एन० बी० दिगे, सब-स्टाफ की 31-5-1981 से सेवाओं की विछीन्न करने तथा समाप्त करने की कार्रवाई उचित और न्यायसंगत है? यदि नहीं, सो कर्मकार किस अनुतोप का हकदार है ?"

[स॰ 12012/397/81-की॰ 2(ए)]

ORDER

New Delhi, the 23rd August, 1982

S.O. 4029.—Whereas the Central Government is of the opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Bank of Baroda, Ahmedabad- and their workman in respect of the matter specified in the Schedulo hereto annexed:

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri G. S. Barot, shall be the Presiding Officer with headquarters at Ahmedabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the action of the Baroda Region Office, Ahmedabad in terminating and or discontinuing the services of Shri N. V. Dige, sub-staff with effect from 31-5-80 is legal, proper and justified? If not, to what relief is the said workman entitled?".

[No. 12012/397/81-D. II(A)]

आदेश

नई विल्ली, 25 भगस्त, 1982

का० आर० 4030.--केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद अनुसूची में विनिधित्ट विषय के बारे में जयपुर ख्रांचलिक ग्रामीण बैक के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध एक खीद्योगिक विवाद नियोजकों खीर उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है:

भीर केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वाळनीय समझती है;

घतः, केन्द्रीय सरकार, भौद्योगिक विवाद प्रधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क भौर धारा 10 की उप-धारा (1) के खब (व) द्वारा प्रवत्त समितयों का प्रयोग करते हुए, एक धौद्योगिक ध्रधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन ध्रधिकारी श्री रामराज लाल गुष्ता होंगें, जिनका मुख्यालय जयपुर में होगा धौर उपत विवाद को उक्त ध्रधिकरण को स्थायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

"क्या जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक, जयपुर के प्रबन्धतंत्र की मपने कर्मचारियों की भविष्य निधि मंगवान की कटौती 1-11-1978 से 8.33 प्रतिशत के स्थान पर 6.25 प्रतिशत करना न्यायोचित हैं ? यदि नहीं तो संबंधित कर्मकार किस मनुतोष के हकदार हैं?"

> [सं॰ एल-12011/65/81-को॰ 2(ए)] एन० के॰ वर्मा, डेस्क अधिकारी

ORDER

New Delhi, the 25th August, 1982

S.O. 4030.—Whereas the Central Government is of the opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Jaipur Aanchlik Gramin Bank and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri Ram Raj Lal Gupta shall be the Presiding Officer, with headquarters at Jaipur and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Jaipur Nagaur Aanchalik Gramin Bank, Jaipur in deducting Provident Fund Contribution of its employees @ 6.25 pcr cent of their basic Pay instead of @ 8.33 per cent with effect from 1-11,1978 is justified? If not, to what relief are the workmen concerned entitled?".

[No. L-12011/65/81-D. Π (A)] N. K. VERMA, Desk Officer

नई किंगे 8 नक्षा, 1993

का० आ० 4031 — मेसर्स जुपटर रेडियों (रिज०) सी-46, श्रोकला, इण्डस्ट्रियल एरिया, फेम II. नई विल्ली-20 (जिले इसमें इसके पश्चास् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी एविष्य निधि और प्रकीर्ण उपवन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-श्वारा (2क) के अधीन छूट विष्ण जाने के लिए शावेंदन किया है;

भीर लेखीय संरकार का समाधान हो गया है कि उनत स्थापन के कर्मचारी, किनी पृथक श्राभदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय की जन बीमा निगम की सामृहिक बीमा स्कीम के प्रधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है श्रीर ऐसे कर्मचारियों के लिये ये फायदे उन फायबों से ग्राधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप महबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चान उक्त स्कीम कहा गया है) के प्रधीन उन्हें अनुक्षेय हैं;

भत , केर्चा सरकार, उसत प्रधितियम की धारा 17 की उपधारा (2क) इत्तरा प्रवन्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपावदा धनुसूचे। में विभिर्विष्ट शतों के भ्रधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की संबंधि के लिए उनते स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन में खुट देती हैं।

अमुसूची

- 1 उसत स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक स्थिप्य निधि धासुकत नई दिल्ली को ऐसी विवर्णियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा तिरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रवान करेगा जो भेन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निदिष्ट करे।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाध्ति के 15 बिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उनत प्रधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के प्रधीन समय-समय पर निर्विष्ट करे।
- 3. सामृहिक दीमा स्कीम के प्रणासन में, जिसके प्रत्यांत लेखाग्रों का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संबाय, लेखाग्रों का प्रत्यत्या, निरीक्षण प्रभारों का संवाय गादि भी है, होने वाले सभी व्ययों का बहुन नियोजक द्वारा किया जायेगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमावित मामहिक बीमा स्की म के नियमो की एक प्रति, भीर जब कभी उनमें संगोधन किया आए, तब उस संगोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंक्या की भाषा में उसकी मुख्य वातों का प्रमुवाव, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निश्चि का या उक्स प्रधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किती स्यापन की भविष्य निश्चि का पहुले ही सबस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक मामूहिक बीमा स्कीम के मबस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त धर्ज करेगा घौर उसकी बावत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को पंदन करेगा।
- 6. यदि उदन स्कीम के भ्रधीन वर्मचारियों को उपलब्ध फायदे वढ़ाए आते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के भ्रधीन कर्मजारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि पर्मचारियों के जिए मानृहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अभिक अनुकूल हों जो उदत स्कीम के अधीन अनुक्रेय है।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मकारी की मृत्यु पर इस स्कीम के प्रधीन संदेय रक्षम उस रक्षम से कम है, जो कर्मकारी की उस दशा में संदेय होती, जब बहु उनत स्कीम प्रधीन होता तो, नियोजक कर्मकारी के विधिक आरिस/नामनिवें शिती को प्रतिकर् के रूप में दोनों रकमों के धन्तर के बराबर रक्षम का संदास करेगा।

- 8. मामूहिक अभि स्कीम की उपमन्धों में कोई भी संसोधन, प्रावेशिक प्रित्य निधि श्रामुक्त गई दिल्ली के पूर्व अनुसोधन के बिना नहीं किया जायेगा और जहा किसी सणोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृष प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रावेशिक भविष्य निधि आयुक्त, ध्यमन अनुसोधन देने से पूर्व नर्मचारियों को अपना वृष्टिकोण स्पष्ट करमें का युक्तियुक्त अवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवंश, स्थापन के कर्मवारी, भारतीय श्रीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका हैं प्रधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मवारियों को प्राप्त होने बाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्व की जा सकती है।
- · 10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियस तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीभा निगम नियन करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिमी की ज्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रहुव की जा सकती है।
- 11. नियांजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किए गए किसी व्यक्तिकम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिष्धितियों या विधिक वारिसों की जो यबि यह, छूट न वी गई होती तो उक्त स्कीम के झस्तर्गत होते, बीमा फायदों के संवाय का उत्तरवायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के प्रधील पाने वासे किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्वेशितियों/ विधिक बारिसों की बीमाकृत रकम का संवाय तत्वरता से कौर प्रस्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एम-35014/230/82-र्पा॰एफ-2]

New Delhi, the 8th November, 1982

S.O. 4031.—Whereas Messrs Jupiter Radios (Regd.) C-46, Okhia Industrial Area, Phase-II, New Delhi-20 (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3) of section 17 of the said Act. within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of

accounts, payment of inspection charges etc. chail be borne by the employers.

- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Br. p Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the emptyees
- 5 Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Gran; Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6 The employer shall at range in eathance, he benefits available to the enviloyees ande, the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Nowithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee theamount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium within the due date, as fixed by the Life Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium etc. the responsibility for navment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the spid Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014 (230)/82-PF, III

नदिविल्ली, 9 मधम्बर, 1982

का॰आ॰4032---केसीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कैसिकस बिस्ट्रीक्यूटर्स कारपोरेशन, 573, ब्लाक-एन॰, न्यू प्रलीपुर, कलकत्ता-53 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक भीर कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहनत हो गई है कि कर्मचारी भिष्ण्य निधि भीर प्रकीर्ण उपक्षण्य प्रधिनियम, 1952(1952 का 19) के जपबश्य जनत स्थापन को लागू किये जाने चाहिये;

भतः कैन्द्रीय सरकार, उक्त मिन्नियम की धारा 1 की उपधारा (4) हारा प्रदश्न सक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त मिन्नियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागु करती है।

सिक्या, एस०-35017/101/82-पीर् एफ०-III

New Delhi, the 9th November, 1982

S.O. 4032.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Chemical Distributors Corporation, 573, Block-N, New Alipore, Calcutta-53, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1932), should be made applicable to the said establishment:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35017/101/82-PF. II]

का॰आ॰ 4033 — केश्वीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स प्राटं ट्रेंब एक्सपीटंस (प्राइवेट) किसिटेड, 12, च्रग रोड, कलकत्ता-17 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचा पित्र पिछ और प्रकीण अपबन्ध ग्राधिनियम, 1952(1952 का 19) के उपबन्ध उकत स्थापन को लाग किये जाने काहिये;

भात केन्द्रीय सरकार, उक्त मिनियम की द्वारा 1 की उपधास (4) द्वारा प्रदत्त सक्तियों का प्रयोग करन हुए, उक्त स्थिनियम के स्थापन उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं॰ एस॰-35017/96/82-पी॰ एफ॰-IJ]

S.O. 4033.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Art-Trend Exports (Private) Limited, 12, Darge Road, Calcutta-17, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No.S-35017]96[82-PF.II]

कां कां 4034---केंग्ड्रीय सरकार की यह प्रतीत होता है कि मैससें जालान प्रोडक्शन्स, 183/1, धर्मदोला स्ट्रांट, (वूसरी मंजिल) कलकत्ता-13 तामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस धात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीण उपवश्च धंधिनियम, 1952 (1952 का 19) के अपंत्रक उक्त स्थापन की लागू किये जाने कांशिय;

सतः केग्द्रीय सरकार, उपन अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रवत्त पक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपत अधिनियम के उपबन्ध उपत स्थापन की लाग करती है।

[सं० एस०-35017/89/82-पी०एफ०-II]

S.O. 4034.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Jalan Producctions, 183|1, Dharamtolla Street, (2nd Floor), Calcutta-13, have agreed that the provisions of the Employees' provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (1° of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No.S-35017]89]82-PF.II]

का॰ आ॰ 4035.—केन्द्रीय सरकार की यह प्रतीत होता है कि मैसर्स बरतनाक्षय, 56/1, कैनिंग स्ट्रीट, कलकला-1 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजन और कर्मकारियों की बहुसंख्या इस बान पर सहमत हो गई है कि कर्मकारी भिवष्य निधि और प्रकीण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये;

भतः केन्द्रीय सरकार, उक्त श्रधिनियम की धारा १ की उपवारा (4) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त श्राधिनियम के उपवक्त एक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं॰ एम॰-35017/94-/82-पि॰एफ॰-II]

8.0. 4035.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Baratanalaya 56[1, Canning Street, Calcutta-1, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017/94/82-PF.II]

काल्आ 4036.— केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कुमार एजेर्स्स. 1/4, डी० खासेन्द्र बटर्जी रीड, कोसीपुर, कलकला-2 जिमके प्रत्नार्गत 16 इंडिया एक्सचेज प्लेस कलकला-1 स्थित इसका मुख्यालय भी है, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक ग्रीर कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निश्चि भीर प्रकीण उपबन्ध प्रधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये;

णतः केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा 1 की अपधारा (4) द्वारा प्रवत्त गमितयों का प्रयोग करने हुए, उक्त धाधिनियम के उपक्रमध उक्त स्थापन को सागू करती है।

[सं० एस०-35017/110/82-पी०एफ०-II]

S.O. 4036.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Kumar Agencles, 1/4-D, Khagendra Chatterjee Road, Cossipore Calcutta-2 Including its Head Office at 16, Indla Exchange Place, Calcutta-1, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35017/110/82-PF.II]

कांश्याः 4037.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैससे सिस्वर क्लोस्टोबम (प्राइवेट) लिमिटेड, सी०-101, हिन्द गीराष्ट्र इंडस्ट्रियल एस्टेट) ग्रंबेरी कुर्ला रांड, मुम्बई-59 जिसके भन्तरीत 95 साबेरी बाजार कालबादेवी रींड मुम्बई-2 स्थित इसका रकिस्ट्र इत कार्यालय भी है नामक स्थापन से सावद्य नियोजक गौर कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बान पर सहमल हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि भीर प्रकीण उपबन्ध मधिनियम, 1952(1952 का 19) के उपबन्ध उकत स्थापन को लागू किये जाने चाहियों:

अतः केर्न्द्रीय सरकार, उकत स्थितियम की धारा । की उपधारा (4) बारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त स्थितियम के उपक्रम उक्त स्थापन की लागू करता है।

[स॰ एस॰-35018/57/82-पी॰एफ॰-II]

S.O. 4037.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Mesure Silver Plastochem (Private) Limited, C-101, Hind Saurashtra Industrial Estate, Andheri Kurla Road, Bombay-59 including its Registered Office at 95, Zaveri Bazar, Kalbadevi Road, Bombay-2, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the sald establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35018/57/82-PF.II]

काल्यात 4038.—केन्द्रीय गरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मुनावला धाईस फैक्ट्री, 188, लेभिगटन रोड, मिनर्वा सिनेमा के पीछे, मुम्बई-4 और उनके 35-सी जेराईभीय स्ट्रीट, म्मूनिसिपल वर्कशाप के पास, फीरस रोड, मुम्बई-8 स्थित कार्यालय सहित नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक भौर कर्मजारियों की बहुसंख्या इस बात पर महमत हो गई है कि कर्मजारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध प्रधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने आहिये;

भत. केम्ब्रीय सरकार, उक्त भिक्षित्यम की घारा 1 की उपधारा (4) बारा प्रवत्त समितयों का प्रयोग करते हुए, उक्त ग्रिधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन की लागू करती है।

[सं० एस०-35018/58/82-पी०एफ०-II]

S.O. 4038.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sunawalla Ice Factory, 188, Lamington Road, Behind Minerva Cinema, Bombay-4, including its office at 35/C, Jeraijbhoy Street, Near Municipal Workshop, Foras Road, Bombay-8, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the sald establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conerred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment,

[No. S-35018/58/82-PF.II]

णां आ 4039. --- केन्द्रीय सरकार की यह प्रतीत होता है कि मैससं धार्डनेंस फैक्टरी एम्प्लाइन करूप्यममं को-धापरेटिव सोसाइडी लिमिटेड, धार्डनेंस फैक्टरी एस्टेट, वरणगांव, जिला जलगांव, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक धीर कर्मचारियों की बहुसंख्या इस धान पर सहमत ही गई है कि कर्मचारी श्रविष्य निधि भीर प्रकीण उपवस्त्र घितियम, 1952 (1952 का 19) ने उपवस्थ उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहियें;

भतः केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रवत्त सक्तियो का प्रयोग करते हुए, उक्त प्रधिनियम के उपबक्त उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं०एस०-35018/65/82-पी०एपा०-]]]

S.O. 4039.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Ordnance Factory Employees Consumers Co-operative Society Limited, Ordnance Factory Estate, Varangaon, District Jalgaon, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35018/65/82-PF.II]

ं नगं अगि 4040. — केन्द्रिय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स हुवं प्रिटरा, 122, डा-मगहरा रीड, धर्योदय केन्द्र खिल्डग, मुम्बई-9, मामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुमंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी अविषय निधि भौर प्रकीर्ण उपबन्ध प्रधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को जागु किये जाने चाहियों;

भत. केन्द्र य सरकार , उवत श्रिधिक्यम की धारा 1 की उपघारा (4) द्वारा प्रदक्त शक्तिया का प्रयोग करते हुए, उवत भौधीनयम के उपयन्ध उवत स्थापन को लागू करती है।

सिं एस०-35018/66/82-पी एफ०-Iा

S.O. 4040.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Harsha Printery, 122. Dr. Meisheri Road, Sarvodava Kendra Building, Bombay-9, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35018/66/82-PF.II]

का आ 4041. — के ब्रिय सरकार को यह प्रतित होता है कि मैससं पटेल सिन्पैटिक यानें (पाइबेट) लिमिटेड, मिसल एस्टेट सं० 2, गाला सं० 6 और 10, अंग्रेरी-कुर्ला रीड, सुम्बई-59, जिसके अन्तर्गत चोकसे चैम्बर्स, 117, आवेरी बाजार, सुम्बई-2 स्थित इसका मुख्यालय में है। नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों का बहुसंख्या इस बात पर महमत हो गई है कि कर्मचारी अधिक्य निर्धि और प्रकृणें उपबन्ध अधिनयम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन का लागू किये जाने चाहरीं,

प्रत केन्द्र य सरकार, उक्त प्रधिनियम क धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रवत्त सक्तियो का प्रयोग करते हुए, उक्त प्रधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागु करती है।

[स॰ एस०-35018/68/82-पी०एफ०-1]

S.O. 4041.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messis Patel Synthetic Yarn (Private) Limited, Mittal Etate No. 2, Gala No. 6 and 10, Andheri-Kurla Road, Bombay-59 including its Head Office at Choksey Chambers, 117, Zaveri Bazar, Bombay-2, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act. the Central Government her-by applies the provisions of the said act to the said establishment.

INo. S-35018/68/82-PF.III

का० आ० 4042 -- भेन्द्रीय सरकार की यह प्रतीस होसा है कि मैसर्स भनीकात मलक नन्द, 11वी मंजिल, राहेजा चेम्बर्स, निरमन पाइंट, मस्बई-21 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक ग्रीर कर्मेचारियो की बहु-संख्या इस बात पर सहमत हो गई है का कर्मचारी अविद्य निधि ग्रीर-प्रकीण उपवन्य ग्रीविन्यम, 1952 (1952 का 19) के उपवन्य एक स्थापन की लागू किए जाने चाहिए;

कर्ता केन्द्रीय सरकार, एक किंधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त पक्तियों का प्रयाग करते हुए, उक्त प्रक्षिनियम के उपवन्ध एक स्थापन की लाग करती है।

[सं० एस-35018/56/82-पी०एफ०-II]

8.0. 4042.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Manilal Talakchand, 11th Floor, Reheja Chambers, Nariman Point, Bombay-21, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35018/56/82-PF.II]

का० आ० 4043.—मेन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैससै लक्ष्मी फाइनेंस, 3-6-140/5-सी, हिमायत नगर, हैदराबाद-29. नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक भीर कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि वर्मचारी 'विष्ण निधि भीर प्रवीण जवबन्ध श्रीध-नियम, 1952 (1952 को 19) के जनबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

भत येन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की घोरा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त प्राक्तियों को प्रयाप करते हुए, उक्त प्रधिनियम के उपकृष्य उक्त स्थापन की लागू करती है।

[सं० एस-35019/197/82-पी०एफ-II]

S.O. 4043.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Lakshmi Finance, 3-6-140/5C, Himayat Nagar, Hyderabad-29, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35018/197/82-PF.II]

कां आ 4044. -- केन्द्रीय राज्यार को यह प्रतीत होता है कि मैससे वेंस्केटश्वर एवं के मकल्य एण्ड भिनश्स्स (प्राह्मवेट) कि मिटेड, इंजीनियरिय डिविजन, प्लाट सक 3-वी, इंडिस्ट्र्यल एस्टेट, ग्रम्बाट्र, महास-98, नामक स्थाय से सम्बद्ध नियाजन और कर्मविधियों की बहुसक्या इस बात पर सहसत हो गई है कि कर्मवारी जिंवण्य विधि और प्रकीर्ण उपवस्य अधिनियम, 1952 (1952 की 19) के उपवस्य उक्त स्थापन की लागू किए जाने वाहिर्;

भतः केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रक्षिणियमं की धारा 1 की उपवारा (4) द्वारा प्रवत्त पत्तियों की प्रयान करने हुए, उक्त श्रीधनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन की साम् करती है।

[सं० एम-35019/185/82-पी०एफ-]]]

S.O. 4044.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Venkateswara Agro Chemicals and Minerals (Private) Limited, Ingineering Division, Plot No. 3-B, Indivitrial Estate, Ambattur, Madras-98, have agreed that the provisions of the Fmployees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35019/185/82-PF.II]

का० आ 4045 --- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैससं ए० श्रीनिवास भट्ट एष्ड बम्पनी, कांट्रकुलम रोड, कोचीन-2, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक भीर कर्मवारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मवारी भविष्य निधि भीर प्रकीर्ण उपबन्ध धिनियम, 1932 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन की लागू किए जाने वाहिए;

भतः केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त मक्तियों को प्रयोग करते हुए, उक्त मीर्जनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन की लागू करती है।

[स॰ एस-35019/186/82-पी॰एफ-2]

S.O. 4045.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs A. Srinivasa Bhat and Company, Kettukulam Road, Cochin-2, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

INo. S-35019/186/82-PF.JII

का॰ आ॰ 4046.---केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्सं श्री विजय इंडस्ट्रीअ, पलाट सं॰ 19, आई॰डी॰ए॰ पत्तनचेक मेडक जिला, आन्ध्र प्रदेश, लामक स्थापन से सम्बद्ध नियंजिक और कर्मचान्यों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी विवय निर्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

भतः केन्द्रीय सरकार, उक्त भविनियम की घारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त मक्तियों को प्रयोग करते मुण्, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019/187/82-पी०एफ-2]

S.O. 4046.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sri Vijaya Industries, Plot No. 19, I.D.A., Pathancheru, Medak District, Andhra Pradesh, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the sald establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35010/187/82-PF.II]

का० आ० 4047.-- केन्द्रीय सरकार की यह प्रसीत होसा है कि भैसर्स मुनल महल रेस्तरां, सेठी भवन, राजेन्द्र प्लेल, नई विल्ली-8 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक भीर कर्मचारियों की बहुनंख्या इस बात पर सहसत हा गई है कि कर्मचारी भिवष्य निधि भीर प्रकीण उपबंध भिवित्यम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उनते स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

मतः केन्द्रीय सरकार, उपस प्रधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदक्त प्रक्रियों का प्रयोग करते द्वार, उक्स घाधिनियम के उपग्रंध उक्त स्थापन को लागू करती हैं।

[सं॰ एन-38019/195/82-यी॰ एफ॰-2]

S.O. 4047.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Mughal Mahal Restaurant, Sethi Bhavan, Rajendra Place, New Delhi-8, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellancous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the sald establl.hment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35019]195[82-PE. II]

का० आ० 4048.- केन्द्रीय सम्कार की यह प्रतीस होता है कि भैगर्स श्रीवाकुलम गवर्नमेंट एम्प्याइज, बी-प्रापरेटिव स्टंमी लिसिटेड, श्रीकाकुलम (ग्रान्थ पदेण), सम्राह्म स्थापन से सम्बद्ध नियाज । ग्रीर कर्मबारियों की बहुमंत्रा इस बात पर सहमन हो गई है कि कर्नबारा निवध निक्षि ग्रीर प्रकीण उपबंध ग्राजिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन का लागू किए जाने चाहिएं;

भतः केन्द्रीय करलार, उक्त प्रधिनियम की धारा । की उपधारी (4) द्वारा प्रदक्त सिक्तयों का प्रयोग करते हुए, उक्त प्रधिनियम के उपक्षा उक्त स्थापन की लागू करती है।

मि॰ (म-35019/196/82 पा॰ (फ॰ t)

S.O. 4048.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs The Srikakulam Government Employees Co-operative Stores Limited Srikakulam (Andhra Pradesh), have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

INo. S-35019|196|82-PF. II]

का० आ० 4049.--केन्द्रीय सरकार की यह प्रतीत हीता है कि गैसने मेल्स एफ सिंवर, प्रारंक एनक वर्नाड बिन्डर, उर्दर्भ 576101 जिन्न सनारा कर्नीत्म, नामक स्थापन से सम्बद्ध, निसंजक प्रीर कर्म-पारियों की बहुसंख्या इस आत पर सहसन हो गई है कि कर्मचारी अधिधानियम, 1952 (1952 पा 19) के उप् बंध उक्त बापन की लागू किए जाने चाहिए;

ग्रासः केन्द्रीय सरकार, जन्न ग्रिधिनिय की-घारा 1- की उपधारा, (4) हारा प्रदक्त ग्रिक्तियों का प्रयोग करते हु,ए., उक्त ग्रिधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को सागू करती है।

[सं॰ एस-35019/199/82-पी॰ एफ॰ 2]

S.O. 4049.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees In relation to the establishment known as Messrs Sales and Service, R. M. Karnad Building, Udupi-576101, District Kannada, Karnataka, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35019]199[82-PF. II]

का० आ० 4050.— केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीस होता है कि भैसर्स धौकर इडिया आर्क एंड भैसर्स वैस्टिंग धवर्स, 18, कोन्नूर हाई रोड, महास-23, नामक स्थापन से सभ्यत नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी अविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध धौधनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उसत स्थापन को लागू किए आने चाहिए;

श्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त श्रक्षिनयम की घारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रवस्त शक्तियो या प्रयोग करते हुए, उक्त मधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019/204/82-पी० एफ०-2]

8.0. 4050.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messra Our India Are and Gas Welding Works, 18, Konnur High Road, Madras-23, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35019]204[82-PF. II]

का० आ० 4051.-- केन्द्रीय रास्कार को यह प्रतीत हीता है कि भैसर्स मिलाक बदर्स, कोबला फी ट्रेड जीन, गांसी घाम (कच्छ.) जिसके मंत्रगंत 509, वर्षगेट चैम्बर्स-5, न्यू भेरीन लाइका, मुस्वई-20 स्थित इसकी गांखा भी है, नामक स्थापन से सम्बद्ध, नियोजक प्रौर-कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बान पर सहमन हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि प्रौर प्रकीर्ण उपबंध श्रिधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध, उक्त स्थापन को लाग किए जाने वाहिएं;

श्रतः भेत्य्रीय -सरकार, उक्त श्रीधितियम -की धारा 1 की उपधारा (4) -कारा प्रवस्त गक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त श्रीधितियम के उपजंज उक्त स्थालन को सागू करती है।

[म॰ एस-35019/205/82-पी॰ एफ०-2]

8.0. 4051.—Whoreas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Mesars Milak Brothers, Kandla Free Trade Zone, Gandhidham (Kutch) including its branch at 509, Churchgate Chambers, 5, New Marine Lines, Bombay-20, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35019]205[82-PF, II]

का बार 4052, — के सीय सरकार की यह प्रतीत होता है कि मैससे एक्सप्रेस प्राप्तस एक्सप्रेस, 4/1, की तिकार, श्रीक्षींगक सेंब, नई दिल्ली-15, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मवारियों की बहुसंक्या इस बाल पर सहमत हो गई है कि कर्मवारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपर्धक्ष प्रधिनियम, 1952 (1952 का 18) के उपबंध उक्त स्थापन की लागृ किए जाने वाहिए;

मतः केन्द्रीय सरकार उन्त मधिनियम की घारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रवंत सक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपवक्त उक्त स्वापंत की लाम करती है।

सि॰ एस॰-35019/210/82-पी॰एफ॰-2]

S.O. 4052.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Express Process Engravers, 4|1, Kirti Nagar. Industrial Area, New Delhi-15, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35019]210[82-PF. II]

काव्याव 4053.—केन्द्रीय सरकार की यह प्रतीस होता है कि मैससे यूनिसम इंजीनियसे 7/27 कीर्तिनगर भौधोगिक क्षेत्र नई दिल्ली, नामक स्यापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्नचारियों की बहुसंख्या इस बात पर महमत हो गई है कि कर्नचारी स्विध्य निश्चि और प्रकीण उपवंध बक्षिनियम 1952 (1952 का 19) के उनवन्ध उक्त स्थान को लागू किए जाने बाहिए;

अक्षः केन्द्रीय संस्कार उकन अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उकन अधिनियम के उपबन्ध उक्न स्थापन को आगु करती है।

[सं॰ एम-35019/211/82-पी एफ-2]

S.O. 4053.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Unison Engineers, 7|27, Kirti Nagar, Industrial Area, New Delhi, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35019]211]82-PF. III

का० आ० ६054.—केन्द्रीय भरकार को यह प्रतीत होना है कि मैसर्स प्रभात किरण पसैट मोनसं एसोसिएगन प्रमात किरण 17 राजेन्द्र प्लेस नई विल्ली-8 जिनके मंतर्गन इसके दो मून्टि अर्थात् थीप शिका पसैट भोनसं एसोसिएगन मोर कॉर्नि महल पसैट मोनसं 17 राजेन्द्र प्लेस नई विल्ली भी है नामक स्थान से सम्बद्ध कियोजक मौर कर्मवानियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मवारी प्रविष्य निधि भीर प्रकीर्ण उपबन्ध मधिनयम 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्क स्थापन को शागू किए जाने चाहिए;

मतः केन्द्रीय सरकार, उक्त मधिनियम की धारा 1 की उपन्नारा (4) द्वारा प्रवत्त सम्बद्धों कः प्रयोग करते हुए उक्त पश्चिनियम के उप-वश्च एक्त स्थापन को मागू करती है।

[मं॰ एम॰ 35019/212/82-पो॰एफ॰-2]

8.0. 4054.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Prabhat Kiran Flatowners Association, Prabhat Kiran, 17, Rajindra Place, New Delhi-8 including its two units namely Deep Shikha Flatowners Association and Kirti Mahal Flatowners, 17, Rajindra Place, New Delhi, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35019]212[82-PF, II]

का० आ० 4055--- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होना है कि मैंसरी कावेरी कन्टेनर्स (प्राइवेट) लिमिटेड वी /12-13/जय भारत इंडिस्ट्रियल एस्टेट जलहानी कैम्परोड यग्नवंतपुर बगलीर-22 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक गीर कर्मवारियां की वसुनंतरा इस बात पर मह्नन हो गई है कि कर्मवारी पश्चित्व निधि ग्रीर प्रकीण उपवन्ध प्रधिनियस 1952 (1952 का 19) के उपवन्ध जनन स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः केन्द्रीय सरकार जक्त मिश्रिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त मिश्रितयों का प्रयोग करने हुए उक्त प्रधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन की लागू करनी है।

[स॰ एस॰-35019/213/82-पी एफ-II]

S.O. 4055.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Cauvery Containers (Private) Limited, B, 12-13, Jai Bharat Industrial Estate, Jalahalli Camp Road, Yeswanthpur, Bangalore-22, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019]213[82-PF. II]

का० थां 0 4056. — केशीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि भैसर्स की बालानी माइन राइस मिल, 27, रेलवे स्टेशन रोड, मिरफाली,तिमिल माबु, नामक स्थापन से सम्बद्ध निधीजक भीर कर्मचारणों की वह संख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि सर्मचारी अधिष्य निवि भीर प्रकीण उपवन्ध मधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपवन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

प्रतः केन्द्रीय सरकार, उका प्रक्षितियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते द्वुए, उक्त प्रक्षितियम के उपबक्ष्य उक्त स्थापन की लागु करती है।

[रॉ॰ एग॰-35019/221/82-पी॰एफ॰-II]

S.O. 4056.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sree Balaji Modern Rice Mill, 27, Railway Station Road, Sirkali, Tamil Nadu, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the sald establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019]221'82-PF. II]

का ब्ह्रा० 4057. -- फेक्ट्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स गांधीगंज प्राइमरी को स्नापरेटिक बैंध लिमिटेड, गांधी गंग, बीदार, कर्नाटज, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोज के और कर्म नारियों की बहुनंद्व्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भिक्तिय निश्चि और प्रकीर्ण उपबन्ध स्विधिनयम, 1952 (1952 वा 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू फिए जाने चाहिए;

मत केन्द्रीय सरकार, उन्न प्रधिनियम की प्रारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त प्रविचयों का प्रयोग करने हुए, उना प्रधिनियम के उपबन्ध उन्त स्थापन की लागू करती है।

[मं॰ एस॰-35019/232/82-पी॰एफ॰-II]

8.0. 4057.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messre The Gandhl Gunj Primary Co-operative Bank Limited, Gandhi Gunj, Bidar, Karnataka, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section I of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019]232[82-PF. II]

का ब्यां 4058. -- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीस होगा है कि भैसर्स इंटेंगरेटिड प्रासेस घाटोमेणन (प्राइवेट) लिमिटेड, ए-173 फर्स्ट फेंच, फोर्च काम, पीनिया इंडस्ट्रियल एस्टेट, बॅगलीर-58 जिसके घन्तरांत वार्ड संव 16, कासरीडीह, धानी बजन के सामने, दुर्ग-1, मध्य प्रदेश स्थित इसकी बाल्या भी है, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक घौर कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमन हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि छोर क्रकीण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उमत स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

भतः केन्द्रीय भरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा 1 की उपघारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, उक्त श्रिधिनियम के उप-वंश उक्त स्थापन को सागु करती है।

[सं॰ एग॰-35019/231/82-पी॰एफ॰-II]

S.O. 4058.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs integrated Process Automation (Private) Limited, A-173, 1st Phase, 4th Cross, Peenya Industrial Estate, Bangalore-58 Including its branch at Ward No. 16, Kasaridih, Opposite Dhani Bhavan, Durg-1, Madhya Pradesh, have agreed that the provisions of the Employees' Povident Funds and Miscel-Integrated Process Automation (Private) Limited, A-173, applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019[233]82-PF. II]

का आ 4059. -- वेक्डीय सरकार की यह प्रतीप होता है कि मैसर्स रोमर फैशक्स, 2, दराबालू चेट्ट स्ट्रीट, पहली मंजिल, महाम-1, नाम स्यापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंक्षा इस बात पर सहमत हो गई है कि यमचारी भविष्य निधि और प्रकीण उपवन्ध मिध-नियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्यापन की लागू किए जाने चाहिए;

मृतः केन्द्रीय सरकार, उक्त मधिनियम की द्वारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, उक्त मधिनियम के उपयन्त्र उक्त स्थापन को सागु करती है।

सि॰ एस-35019/334/83-पी: ०एफ ०-III

S.O. 4059.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the cstablishment known as Messrs Romar Fashions, 2, Errabalu Chetty Street, Ist Floor, Madias-1, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-ection (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019]234]82-PF. II]

का॰जा॰ 4060. — केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसमें जनरल काममें लिमिटेड, 102, बंगला साहिब रोड, नई दिल्ली-1 जिसके अन्तर्गत 50/2-3 हनुमान रोड, नई दिल्ली-1 स्थित क्षाकी लाखा भी है, मामब स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कमैं वारियो की बहुसँख्या इस आस पर सहमत हो गई है कि क्षमंचारी मिश्रिक्य निधि और प्रकीण उप-बंध प्रधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लाग किए जाने चाहिएं,

म्रतः मेन्द्रीय सरकार, उक्त प्रश्वितियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रवत्त प्रक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त प्रधितियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं॰ एस-35019/238/82-पी॰एफ॰-II]

ए०के० भट्टाराई, प्रवर समिव

S.O. 4060.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs General Commerce Limited, 102, Bangla Sahib Road, New Delhi-1 including its brench at 50/2-3, Human Road, New Delhi-1, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019]236[82-PF. II]
A. K. BHATTARAI, Under Secy.

न्हें विल्ली, 11 मवम्बर, 1982

कां कां 4061. - फेल्बीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी ग्राधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 27 द्वारा प्रवत्त गक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदहारा उनन अधिनियम की अनुसूची के भाग-1 में मैगनेटाइट खानों का नियोजन जोड़नी है जिसे जोड़ने के संबंध में बहु भारत के राजपल धमाधारण, दिनीक 14 मई, 1982 के भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाणित भारत गरकार के मूल्पर्व अम मंद्रालय की अधिमूचना संक कां 320(प) दिनोंक 14 मई, 1982 द्वारा प्रपने धामाय की सूचना पहले दी जा चुकी है।

[स॰ एम॰-32017/2/81-डब्स्यू सी (एम॰ डब्स्यू॰)] एम॰एल॰ मेहना, धवर सचिव

New Delhi, the 11th November, 1982

S.O. 4061.—In exercise of the powers conferred by Section 27 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), the Central Government hereby adds to Part I of the Schedule to that Act, the employment in Magnetite mines, notice of its intention to do so having already been given, by the notification of Government of India in the late Ministry of Labour number S. O. 320 (E) dated the 14th May, 1982 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 14th May, 1982 as required by the said section.

[No. S-32017|2|81-WC(MW)] M. L. MEHTA, Under Secy. मई दिल्ली, 11 नवम्बर, 1982

कार अगर 4082.--मैसर्स अन्नः द्रासपोर्ट कारपोरान लिमिटेड, मं 12, नामकृष्ण रोड, सलीम-7 टी अन / 7480, (जिमे इसमें इसके पश्चात उक्स स्थापन कहा गया है) के कर्मचारी अविषय निधि भौर प्रकीण उपवश्य सिधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चास उक्स अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिन् जाने के लिए आवेदन किया है;

भौर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि जन्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निर्मा की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मवारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेत्र महच्छ बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इनके पश्चात उनन म्कीम कहा गता है) के अधीन उन्हें अनुत्रीय हैं;

श्रत केन्द्रीय सरकार, उक्त श्रीधिनयम की धारा 17 की उनधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीर इससे उपावक श्रमुलूबी में धिनिविष्ट शर्तों के श्रधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की श्रवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपवक्षी के प्रवर्तन से छूट देती हैं।

अनुसुकी

- उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक मिल्य निश्चित्रायुक्त, तिमलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे जेला रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी मुनिधाएँ प्रदान करेंगा जो केन्द्रीय संरकार, समय-समय पर निर्विष्ट करे।
- 2 नियोज क, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रश्वेक मास की समाध्त कि 15 दिन के भीतर सदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खड़ (क) के घधीन समय-समय पर निर्विष्ट करें।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके प्रस्तानेत लेखाओं का रखा जाना, विकरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, नेव्याओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय ग्रादि भी है, होने वाले सभी व्यायों का बहुन नियोजक द्वारा किया आएगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा धनुमीदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, प्रौर जब कभी उनमें संगोधन किया जाए, सब उस संगोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की धहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का धनुषाय, स्यापन के सुखना पट्ट पर प्रविश्वत करेशा।
- 5. यदि काई ऐसा कर्मकारी, जो कर्मबारी मविष्य निधि काँ या उक्त प्रधिनियम के प्रधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की मविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है ती, नियोजिक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम पुरन्त वर्ष करेगा और उसकी वाबत प्राययक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निश्म की संबत्त करेगा।
- 6. यदि उन्त स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाएं जाते हैं ती, नियाजक सामृष्टिक बीमा स्कीम के ध्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामृष्टिक बीमा स्कीम के ध्रधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से प्रधिक धनुकृत हों, जो उक्त स्कीम के ध्रधीन ग्रमुकृति हैं;

- 7. सामूहिक बीमा स्थीम में किसी बात के हांते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी भी मृत्यु पर इस स्थीम के प्रधीन संदेव रकम उस रजम से कम है जो कर्मचारी को उस बणा में संदेव हाती जब वह उकत स्थीम के प्रधीन हीता सी, भियाजक कर्मचारी के विधिक वारिस/गम निर्वेषिती को प्रसिवर के क्य में दोनों रकमों के प्रस्तर के बरावर रकम का सवाय करेगा।
- 8. सामृहिक बीना स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संगोधन, प्रादेणिक मिलिया निर्धि प्रायुवत, तिमलनाडु के पूर्व प्रनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किया संगोधन से कर्मचारियों के हिन पर प्रिक्त्ल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निर्धि यामुक्त, प्रपता प्रमुचेवन, प्रपता प्रमुचेवन देने से पूर्व कर्मचारियों को प्रपता वृष्टिकीण संक्ष्ट करने का युक्तियुक्त प्रथसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवा, स्थापना के कर्मकारी, भारतीय कींअन बीमा सिशम की उस सामृष्टिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले प्रपत्ता चुका है प्रधीन नहीं रह आते हैं, या इस स्कीम के प्रधीन कर्मकारियों की प्राप्त होने बाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती हैं।
- 10. यदि किसी कारणवंश, नियंशिक उस नियंश तारीख के भीतर, की भारतीय जीवन बीमा नियम नियंत करें, प्रीमिश्म का संदाय करने में, शक्यक्त रहता है, और पालिसी को व्यवस्थ हो जाने दिया आता है, तो छूट रद्द की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमिथम के संत्राय में किए गए किसी व्यक्ति-कम की दशा में, उन मूक सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसा को जो, यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होंने, बीमा फायंदीं के सदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. उनत स्थापन के संबंध में नियाजक, इस स्कीम के प्रधीन प्राने बाले किसी सबस्य की मृत्यु होने पर उपके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक बारिमों को बीमाकृत रकम का संबंध तत्सरना से श्रीर प्रायीन द्वारा में भारतीय जीवन बीमा नियम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के मान दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं० एस० 35014/440/82-भ०नि०- II]

New Delhi, the 11th November, 1982

S.O. 4062.—Whereas Messrs Anna Transport Corporation Limited, No. 12, Rama Krishna Road Salem-7 (TN/7460) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellancous Provision Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contributions or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner. Tamil Nadu, maintain such accounts and Provide for such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Where the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group rance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner. Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10 Where, for any reason, the employer falls to pay the premium within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would, have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014 (440)/82-PF, III

कॉ॰शा॰ 4063.-- मैसमें शन्याई पेरियार ट्रांगणेट कारपोरेशन लिमि-टेड, 3/137, मालमेट, बालधरेड़ी पोस्ट आफिन, पोस्ट बाबए नं० 56, बिल्लपुरम-605602 (तिमलनाड/8091), (िसे इनमें इसके परवण्य उक्त स्थापन कहा गया है) ने कमेंचारी भावटा निधि और प्रकीर्ण उप-बन्ध श्रीवित्यम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके परकात उक्त मधितियम कहा गया है) की घारा 17 की उपवास (2क) के घर्षीन छूट विस् जाने के लिए ग्रावेदन किया है;

धौर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक श्रीकवाय या प्रीमियम का सदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामृहिक बीमा स्कीम के प्रधीन जीवन बीमा के रूप में पायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिये ये फायदे उन फायदों से श्रीवक अनुकूल हैं जो वर्मचारी निक्षी सहस्रद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चाल उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें श्रनुओय हैं;

ग्रतः केखीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की घारा 17 की उपग्राना (2क) द्वारा प्रदत्त गक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्रीर इससे उपावद्व भनुसूची में विभिद्धिय गती के प्रधीन रहते हुए, उक्त स्थान को तीन वर्ष की प्रविध लिए उक्त स्थान के सभी उपवस्थी के प्रवर्तन से खुट वैती है।

अनुसूची

- क्रिक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रावेशिक भाविष्य निर्धि प्रायुक्त, तिसलनाडु को ऐसी विवर्षणया भेजना भीर ऐसे लेखा रखेना सथा निरीक्षण के लिए ऐसी मुखिबाएं प्रदान करेना जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निविद्ध घरे।
- 2. नियाजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मान की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त यधिनियम की धारा 17 की जपधारा (3क) के खण्ड (क) के धर्धन समय-समय पर मिदिण्ट करे।
- 3. सामृहिक बीमा रहीम के प्रशासन में, जिमके घन्तांत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का श्रन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय श्रावि भी है, होने वार्त सभी अवयों का बहन निर्याजक हारा किया जायेगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय संस्कार द्वारा यथा धनुमोदित सामृहिक बीमा स्कीम के नियमों का एक प्रति, ग्रीर जन कभी उनमें संशोधन किया आए, तथ उस संबोधन की प्रति तथा कर्नचारियों की बहुसंख्या की भाषा से उसकी मुख्य यानों का यनुवाद, स्थायन के सूचना पट्ट पर प्रविधित करेगा।
- 5. यदि काई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी मविष्य निधि पर या उक्त श्रीधिनियम के श्रधीन छूट प्राप्त किमी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही मवस्य है, उपके स्थापन में नियंजित किया जाता है सो, नियंजिक सामृहित वीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उनका नाम गुरस्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत श्रावश्यक शीमियम भारतीय श्रीवन बीमा नियम की संदक्त करेगा।
- 6 यदि उस्त महीन में प्रधीत कर्मनारियों की उपलब्ध कायदे वहाये आते हैं ता, नियंत्रक सामृहिक बीमा महीम के प्रधीन कर्मचारियों की उपलब्द फार्डों में समृचित रूप में बृद्धि की जाने की बादस्था करेगा जिसमें कि वर्मनारियां के गिए सामृहिक बीमा स्कीम के प्रधीन उपलब्ध कायदे उस कार्डों से अभिक अनुष्ल हों. की उपल स्कीम के प्रधीन अनुजेप हैं।
- 7. सामृहिश बीमा स्थीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कामैवारी की मृत्यु पर इस स्काम के अधीन सन्देय रक्षम उस रक्षम में बाम है, जो कर्मवारी की एम दक्षा में सदेय होती जान बहु उनत लीन के अधीन होता ती, निर्मातक कर्मनार्थ के विधिक वाष्टित्रीनामिदिशिली की प्रतित में रूप में दोनी रक्षमें के असार के बराबर रक्षम का संदाय करेगा।
- 8. सार्द्धि श्रीमा रतेन के एतन्त्रों में संदेशियां सीमंगीतन, प्रादेशियां सिंदि निधि प्रायुक्त सीमलनाडु से पूर्व श्रमुमंदन के विचा मही किया जातना श्रीर अटा किसी संशोधा से कर्मवर्गियों के हित पर प्रसिक्त

- प्रभाव पड़ने की संभावन। हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि भायुक्त, भपने। अनुभोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को भपना दृष्टिकाण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अयसर देगा।
- 9. यदि किसी कान्णवग, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन कीसा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कींग के, जिसे स्थापन पड़ी श्रपता चुका है भशीन नहीं रह जाते हैं, या इस महीम के श्रवीन कर्मचारियों की प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से क्षम हो जाते हैं, तो यह छूट रह की जासानी है।
- 10. यदि किसी कारणवा, नियोजक उस नियन तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रिमियम का मंदाय करने में असकल रहता है, और पालिशी को अपप्रत ही जाने दिया आता है तो, छुट रह की जासकती है।
- 11. नियंत्रक द्वारा प्रीमिथम के संदाय में किए गए किसी व्यक्तिका की दणा में उन भूत सरस्यों के नाम निर्देशिक्षियों या विधिक वाश्सिं को जो यदि यह छूट नदी गई होती तो उनत स्कीम के प्रतर्गत होते, बीमा फायदी के संदाय का उत्तरदायिस्य नियंत्रक पर होगा।
- 12 उकत स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के बधीन धानै बाके किसी साइस्व की मृत्यु हुंनि पर उसके हुकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संवाव तत्परता से भीर प्रत्येक दणा में भारतिय जीवन बीमा नियम से बीमाकृत रकम प्राप्त हुंनि के सात दिन के भीतर सुनिधिकन करेगा।

[संख्या एस-35014/383/82-पी ०एफ०-II]

S.O. 4063.—Whereas Messrs Thanthai Periyar Transport Corporation Limited, 3/137, Salamedu, Valudhareddy Post Office, Post Box No. 56, Villupuram-605602, (TN/8094) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenace of accounts, submission of returns, payment of insurace premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Choup Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, it the bentfits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme
- 7. Nowithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an empolyee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nada and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insutance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premimum etc. within the due date, as fixed by the life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominces or the legal heirs of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014 (383)/82-PF, 11]

का० आ० 4064—.मैसर्स पांडियान रोडवेज कारपोरेशन लिमिटेड, वार्ड पास रोड, सबुरी-625016 (टी एम/6882) (जिसे इसमें इसके पण्डान् उक्त स्थापन कहा गया है) ने वर्मचारी भांक्य निधि और प्रकीण उपवन्ध प्रधिनियम 1952 (1952 का 19), जिससे इसके पण्डान् उक्त श्रितियम कहा गया है) की धारा 17 की उपवारा (2क) के प्रधीन छट दिए जाने के लिए भावेदन किया है;

भीर केरद्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मकारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन कीमा निशम की मामृहिक कीमा स्कीम के अधीन कीवन बीमा के रूप में फायदे उटा रहे हैं और ऐसे वर्मवारियों के लिए में फायदे उन फायदों से आध्वानुकृषन है जो कर्मकारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इससे इनके पश्चान् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुकेय है;

ग्रन', केरद्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा 17 की उपकारा (2क) इत्या प्रदत्त प्रक्तियों का प्रयोग करने हुए ग्रोर इससे उपायद प्रनुमृत्वी में विनिद्धित एतों के प्रधीन रहते हुए, उक्त स्थापनी को तीन वर्ष की प्रविधि के लिए, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन में खूट देती है। धनसूर्यो

- । उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोज्ञक प्रदेशिक शिक्षण्य निधिकी के स्थान दिन के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के लिए ऐसी मुक्किएए प्रदान करेगा जा केन्द्रीय संस्थान, समय-समय पर निर्देश्य करें।
- ए नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर मदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त प्रयिनियम की धारा 17 की उपधारा (अक्ष) के खंड (क्ष) के प्रधीन समय-समय पर निविष्ट करें।
- अ सामृहिक बीना क्काम के प्रमामन में, जिसके प्रन्तर्गत लेखाओं का एखा जाना विकरणियां का प्रम्मुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाका का जन्तरण, निरीक्षण प्रभारों के मंदाय श्रादि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहने नियोजक द्वारा किया जायेगा।
- 3 नियोजक, केन्द्रीय गण्कार द्वारा यथा अनुमोदित सामहिक बीमा स्कीम के नियमी की एक प्रति, और जब कभी उनमे संगोधन किया जाए, तब उस संगोधन की प्रति नया कर्मवारियों की बहुसख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का ग्रानुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदिशित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कसंचारी, जो कसंचारी भविष्य सिंध का या उक्त मधिनिश्म के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियाजित किया जाता है तो, नियाजक सामृहिक बीमा स्कीम के मदस्य के रूप में उसका नाम सुरुख वर्ष करेगा भीर उसकी बाबत मावण्यक प्रीमिश्म भारतीय बीवम बीमा निशम को सदल करेगा।
- ा यदि जनन स्कीम के अधीन क्रमंचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाएं जाते हैं तो, नियोज्ञक सामूहिक बीमा स्कीन के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में ममुचित रूप से बुद्धि की जाने की ब्यवस्था करेगा अससे कि कर्मचारियों के लिए सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उसे फायदों से अदिक अनुकृत हो, जो उक्त स्कीम के अधीन मनुकेय है।
- 7 सामुहिक बीमा स्कीम में किसी बान के होते हुए भी पर्व किसी कर्मजारी की मृत्यु पर इस स्कीम के प्रधीन सन्देय रकम उस रक्षम से कम है, जो कर्मचारी को उस दणा में सदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के प्रधीन होता हो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देणिली की प्रात्कर के क्या में दोनों रक्षमी के ग्रन्तर के बराबर रक्षम का संदाय करेगा!
- अ सामृतिक कीमा रुकीस के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भिवट्य निधि प्रायुक्त तिमन्तातु के पूर्व प्रमुभावन के बिना नहीं किया आएगा भीर जहां किसी सणोधन से कर्मजारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की सभावना हो वहां प्रादेशिक भिवट्य निधि प्रायुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को प्रपन्त बृष्टिकोण स्पष्ट करसे का युक्तियुक्त अवसर देगा।
- 9 यदि किसी कारणवण, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय बीवन बीमा िशम की उस सामृहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं पत्र जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों की प्राटन होने वाले फायदें किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रह् की जा सकती है।
- 10 यदि किसी कारणवण, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, को भारतीय जीवन बीमा निशम नियत करे प्रीमियम का संदाय करते में भन्नक रहता है, भीर पालिसी को रूपगत हो जाने दिया जाता है तो छट रह की जा मकती?

1001 G of 1/82---6

- 11. नियोजक द्वारा प्रीमिश्म के संवाय में किए गए किसी व्यतिकाम चित्रा में उम मृत सबस्यों के नामनिद्धितियों या विधिक वारियों की जी शिव्य यह छूट न दी गई होनी ती उन्न स्कीम के प्रेमर्गत होते, बीमा फायसों के संदाय का उत्तरदाधिन्य नियोजक पर होगा।
- 12. उक्त स्वापन के संबंध में निर्याजक, इस स्कीम के अधीन प्राने वाले किसी सदस्य की मृत्युं हुँ ने पर उसके हक बार नाम निर्देणित्यों विश्विक वारिसों की बीसाकुत रक्षम का संवाय तरपरना से भीर प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा विश्वम से भीमाकुत रक्षम प्रान्त होने के साल दिन के भीनर सुनिध्यिश करेगा।

[संख्या एस 35014/278/82-पी•एफ II]

S.O. 4064.—Whereas Messis Pandiyan Roadways Corporation Limited, Byc Pass, Road, Madurai-625016 (TN/6882) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the henefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that

- would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment scheme do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premimum etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominces or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(278)/82 PF. II]

नई दिल्ली, 12 नवम्बर 1982

का०आ० 4065.- मैसर्सम पीको हलैक्ट्रोनिक्स एण्ड हलैक्ट्रिक्स्स लिमिटेइ, 7154, प्रकासलाई, महास (टी॰एन॰ 3072) (जिसे दसमें इसके पश्चात उक्स स्थापन क्ला गया है) ने कर्मचारी भित्रप्य निधि और प्रकीण उपकच्छ मधिनियम 1952 (1952 का 19) (जिसे दसमें इसके पश्चात उक्त प्रधिनियम कहा गया है) को धारा 17की उपधारा (2क) के प्रधीन छूट दिए जाने के लिए प्रावेदन किया है;

शीर केन्द्रीय सरकार का संसाधान हो गया है कि उकत स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक श्रिक्षिय या श्रीसियम का संदाय किए बिना ही, धारतीय जीवन बीमा निगम की सामृतिक बीमा स्वीम के श्रिश्चन जीवन बीमा के स्पाम के स्पाम के स्पाम की सामृतिक बीमा स्वीम के लिए ये फायदे उन फायदों से श्रीध अनुकृष है जो वर्मकारी निश्रीप सहबद्ध बीमा स्वीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चास उकत स्वीम कहा गया है) के श्रीय उन्हें अनजीय हैं

धन, केन्द्रिय सरकार, उत्तन श्रक्षितियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शांकनयों का प्रयोग करते हुए, और इससे उपाबद्ध श्रमुर्स्स में विनिविष्ट शर्तों के श्रधीन रहते हुए, उत्तन स्थापन को तीन वर्ष की धवधि के लिए उत्तन स्कीम के राभी उपबन्धों के प्रवर्गन से छूट देती है।

अनुसूची

उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि
ग्रायुक्त तमिलनाह को ऐसी विवर्गणया भीजेगा श्रीर ऐसे लेखा रखेगा तथा
निरीक्षण के लिए ऐसी मुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार,
समय-समय पर सिदिन्ट करे।

- 2 नियोजक, ऐसे निरंक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उत्तत श्रीधनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के श्रधीन समय-समय पर निविष्ट करें।
- 3. मामूहिक बीमा स्कीम के प्रणासन में, जिसके सन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियस क. संदाय, लेखाओं का प्रश्नरण निर्मक्षण प्रभारों का संवाय प्रादि भी है, होने वाले सभी व्ययों का बहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।
- 4 नियोजक, केन्द्रीय सरकार धारा यथा श्रमुमोदिन सामृहिक वैमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, श्रीर जब कभी उनमें समोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति स्था कर्मकारियों की बहुसच्य, की भाषा में उसकी मुख्य बातों का श्रमुकाद स्थापन के सूचना पष्ट्र पर प्रविज्ञित करेगा।
- 5 यदि कोई ऐसा कमंचारी, जो कर्मवारी भविष्य निधि का या उक्त प्रधिनियम के प्रधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की शविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजिक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुशस्य वर्ज करेगा और उसकी बाबन आवष्यक प्रीमियम भारतीय जीवन कीमा निमा को संदत्त करेगा।
- 6 यदि उसन स्कीम के प्रजीत कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियंजिक साभृष्ठिक बीमा स्कीम के प्रधीन कर्मचारियां की उपलब्ध फायदों में ममुचित रूप से युद्धि की जाने की व्यवस्था करेंग जिससे कि कर्मचारियों के लिए मामुष्ठिक मीमा स्कीम के प्रधीन उपलब्ध फायदों उन कायदों से प्रधिक अनुबूल हो, जो उसत स्वीम के प्रधीन अनुकेय है।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए थी, यदि किसी कर्मजारी की मृत्यू पर इस स्कीम के अधीन सन्वेय रकम उस रकम से अस है, जो कर्मजारी को उस घणा में सदेय होती, जब बहु उसत स्कीम के अधीन होता, नियंजिक कर्मजारी के विधिक वारिस/नामनिवेंशिनि को प्रतिकर के उप में बोनो रकमो के धन्तर के बरावर रकम का संवाय बरेगा।
- 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रावेशिक भिक्य निधि प्रायुक्त तिमलनाकु के पूर्व प्रमुगोधन के बिना नहीं किया जायेगा ग्रीर जहां किया संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृत्व प्रभाव पड़ने की सभावना हो वहां, प्रावेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त, प्रपत्न अनुमोबन देने से पूर्व कर्मचारियों को प्रपत्ना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर येगा।
- 9. यदि किसी कारणवंश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले मपना चुका है मधीन नहीं रह जाने है, या इस स्कीम के मधीन कर्मचारियों को ब्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाने हैं. तो यह छूठ रह की जा सकती है।
- 10- यदि किसी कारणवास, नियोजक उस नियत हारीख के भी सर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रोमियम का संबाय करने में ग्रसफल रहता है, ग्रीर पालिसी की व्यपगत हो जाने दिया जाता है सी, छट रह की जा सकती पर हैं।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किए गए किसी व्यक्तिकम की दशा में उन मृत सबस्यों के नामनिर्वेशियो या विधिक वारिसों को जो यदि यह, कूट नदी गई होती तो उक्त स्कीम के संतर्गत होते, बीमा कायशें के सवाय का उत्तरवायित्व निवोजक पर होगा।
- 12 उनन स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के प्रधीन प्राने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशिनियों/

विधिक पारिसो की र्यामाञ्चल २४म का संदाय तरपरता **क्षे क्षीर प्रत्येक** यथा में भारतीय जीवन कीमा निगम से वीमाकृत रकम काप्त हीने के सात दिस के भीतर सुनिधिचत करेगा।

[संख्याः एस० 35014/87/82-पी०एफ-2]

New Delhi, the 12th November, 1982

S.O. 4065.—Whereas Messrs Peico Electronics and Electricals 1td., Philips, 154, Anna Salai, Madras-600002 (TN/3072) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nautre of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premimum in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, I amil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be hable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium within the due date, as fixed by the Life Insulance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees of the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nomince/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

INo. S-35014(87)/82-PF. II]

का अभा ० 4066.— सैसमं की सेन्ट का इज एक कै सिकल्स लिसिटेक, को सेन्ट हाउस, बेलाई एस्टेट, बस्बई (महा/1108) (जिसे इसमें इसके पण्याह् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें क्रमके परचान अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के भधीन छूट विए जाने के लिए आयेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उकत स्थापन के कर्मजारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायरे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायरे उन फायदों में अधिकानुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहस्रक बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्जात् उकत स्कीम कहा गथा है) के अधीन उन्हें अनुजेय है,

धतः केन्द्रीय गरकार, उक्त श्रिधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) हारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए भीर इससे उपाबद्ध भनुसूची में विनिर्विष्ट शर्तों के ग्रधीन रहने हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की भनिध के लिए उक्त स्कीम के मधी उपबन्धों के प्रवर्तन से भूट देती है।

अनुसूची

- 1. उनत स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रावेशिक भविष्य निष्ठि भागुमन महाराष्ट्र का ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के सिए ऐसी मुलिझाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निविष्ट करें।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के प्रधीन समय-समय पर निर्विष्ट करें।
- 3. स(मृह्कि बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके घन्तर्गत लेखाओं का प्रखा जीना विवरणिया का प्रस्तुन किया जाता, बीमा प्रीमियम का सबाम, लेखाओं का घन्तरण, निर्दाक्षण प्रभारों का मंदाय आदि भी है, होने बाले सभी व्ययों का बहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार झारा यथा झनुमोदित सामृहिक कीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब सभी उनमें सशोधन किया जाए, तब उस सभोधन की प्रति सथा कर्मचारिया की बहुसंख्या की भाषा में, उसकी मुद्रय बातों का अनुवाद, स्थापन के सुचना-पट्ट पर प्रवर्णित करेगा।
- 5 यदि कोई ऐसा कर्मजारी, जो वर्मजारी भाषाय निश्चि का या उन्त अधिनयम के अधीन छुट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निश्चि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजिक सामृहिक विभा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम नुरस्त दर्भ करेगा। और उसकी बाबत आवश्यक प्रीसियम भारतीय जीवन बीमा निगम की सदस्य करेगा।
- 6 यदि उक्त स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों की उपलब्ध फायदे बढाए जाते हैं तो, नियोजक सामृष्ट्रिक बीमा स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समृजित रूप से बुद्धि को जाने की व्यवस्था करेगा जिसमें कि कर्मचारियों के लिए मासूहिक श्रीमा स्कीम के घंधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से प्रधिक प्रमुक्त हों, जो उक्त स्कीम के ग्रंथीन प्रमुक्तेय हैं।
- 7. मामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के हाते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के प्रधीन मस्देय रकस उस रक्षम के कम है, जो कांचारी को उस दणा में सदेय होती जब बह उक्त स्कीम के प्रधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के बिधिक बारिस/नामनिर्दणिती का प्रतिकर के रूप में दोनो रकमा के अस्तर के बराबर रक्षम का सदाय करेगा।
- 8. सामृहिक जीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त सहाराष्ट्र के पूर्व प्रनुमीवन के बिना नहीं किया जाएगा और जहा किसी संशोधन से कर्मचारियों के हिन पर प्रतिकृत प्रभाव पढ़ने की संभावना हो, बहा प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमीवन देन से पूर्व कर्मचारियों को प्रपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त प्रजमर वैगा।
- 4 यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन शीमा निगम की उस सामृष्टिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले घ्रयना चुका है धर्धान नहीं रह जाने हैं या इस स्कीम के घ्रधीन कर्मचारियों की प्राप्त होने वाले कायदे किसी रीति से कम ही जाने हैं, तो यह छूट रह की जी सकती हैं।
- 10. यदि किसी कारणवण, नियाजक उस नियत तारीक के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का मंदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, कुट रह की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यक्तिक की दमा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट नदी गई होती तो उथन स्कीम के प्रतिर्गत होने, बीमा फायदों के संदाय का उनरदायिस्व नियोजक पर होगा।
- 1.2. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के प्रधीन प्राने काले किसी सबस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्वेशितियो/विधिक बारिसो की बीमाकृत रकम का सवाय तत्परता से और प्रत्येक दणा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर मृतिशिवत करेगा।

[संख्या एस-35014/315/82 पी०एफ०-4]

S.O. 4066.—Whereas Messis Cresent Dyes and Chemicals Limited, Cresent House, Ballard Estate, Bombay-400038 (MH/1108), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance scheme of the

Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinalter referred to as the taid Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act, and subject to the conditions specified in the SCHFDULE annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashira, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the sahent features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund of the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premimum in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Institution Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtia and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable apportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Grone Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as aheads adonted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner the exemption shall be liable to be cancelled
- 10. Where, for any reason, the employer tails to now the premium etc. within the due date as fixed by the Life Insurance Cornoration of India and the noticy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11 In 1850 of definite if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees of the legal heirs of decensed members who would have been covered under the sail S hemobut for grain of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee (legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. \$-35014(315)/82-PF, II]

मा० आ० 4067—मैससं इतेक्य इजिन वास्त्रज्ञ लिसटेङ 17-बी, हदसार इडस्ट्रियल एस्टेट, पुणे-411013. (महा/11765) (जिसे इसमें इसमें इसमें पश्चान् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कार्मचाँनी भित्रप्य गिर्ध और प्रकीण उपवध प्रधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चान् उक्त प्रक्षितियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के प्रधीन छूट दिए जाने के लिए प्रावेदन किया है.

श्रीर केन्द्रिय सरकार का समाधान हो गरा है कि उन्न स्थापन के कर्मचारी, जिसी पृथक अभिदाय या प्रीमियन का सदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन जीमा निगम की सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन जीवन जीवन की मा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे वार्मचारियों के लिए ये फायदे उठा रहे है और ऐसे वार्मचारियों के लिए ये फायदे उने फायदा में अधिक अनुकृत है जो कर्मचारी निजीप सहबद्ध वीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके प्राचान उक्त स्कीम वाहा गरा है) के अधीन उन्हें अनुक्रेय है,

भन केन्द्रीय मण्याण, उस्त श्रिशिनास्त की धारा 17 की उत्थारा, (2%) द्वारा प्रवत्त गर्भक्तयों का प्रयोग करते हुए और इससे उत्शबद्ध अनुसूची में विनिधिक्ट शर्नों के प्रशीन रहते हुए उस्त स्थापन की नीन वर्ष की श्रवीध के लिए उका स्कीम के सभी उत्थायों के प्रवर्तन में छउ देनी है।

अनुमूचरे

- ा उक्त स्थापन के सबध में नियंजिक प्रादेशिक भविषय निर्धि आधुक्त महाराष्ट्र को ऐसी विवर्णाया भेजेश घौर ऐसे लेखा रखेगा तथा निर्धक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जा केन्द्रीय गरकार समय-गणय पर निष्टिष्ट करे।
- 2 नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभा ो का प्रत्येक साथ की सन्तादन के 15 दिन के भीतर सदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उसने फ्राधिन ने की धारा 17 की उपवारा (अक) के खंड (क) के ध्रधीन समय-समय पर निदिन्ट करे।
- 3 सामृद्धिक कीमा स्कीम के प्रणासन में, जिसके श्रन्तर्गत लेखांश्रा ना रखा जाना विवर्णणयों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रगमियम का संदाय, लेखांश्रो का श्रन्तरण, निर्मक्षण प्रभारों का सदाय प्रादि भी है, होत बांब सभी व्ययों का श्रह्त नियोजक द्वारा किया जायगा।
- 4. नियंक्क, केन्द्रीय सरकार द्वारा यता अनुमादित सामूहिक बीमा स्काम के नियमों की एक प्रति, घीर जब कभी उनमें मणोधन किया जाए, तथ उस सणाधन की प्रति सथा नार्यचारिया की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य यानों का घनुबाद, स्थापना क मूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।
- 5 यदि काई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भनित्य निधि का या उक्त अधिनियम के अञ्चीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भनित्य निधि का पहले ही सबस्य है, उसके स्थापन में नियंजित किसा गाता है तो, नियंजिक सामू-हिक बीमा स्कीम के सदस्य के हा। में उनात तीम तुरस्त दर्ज करेगा और उसकी बाबन आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निया को सदक्त करेगा।
- 6. यदि उक्त स्काम के अधीन कर्मचारियों को उन्तब्ध फायदे बढ़ाएं जात है तो, नियाँजध मामृहिव बीमा स्काम के अधीन कर्मचारबोका उपलब्ध फायदों में समृचित रूप से तृबि को जाने की व्यवस्था करेगा जितन कि कर्मचारियों के लिए मामृहित बीमा स्कीम के अनीन उन्नाम फायदे उन फायदी में आवफ अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अवीन अनुक्रेय हैं।

- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि विसी कार्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के धवीन मंदेय रकत उस रक्षम से कम है, जो वर्मचारी की उस दशा में संदेय होती, जब वह उकत स्कीन के धवीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिमानाम निर्देशिकी की प्रतिकार के रूप में दोनों रकमा के अन्तर्क बराबर रकम का संदीय करेगा।
- 8. सामूहिक कीमा स्कीम के उत्बंधों में कोई की संगोधन, प्रादेशिक भावित्य निधि धायुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोधन के बिना नहीं किया जीएमा और जहां कियी संगोधन से कर्मकारियों के हिन पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहा प्रादेशिक भश्वित्य निधि धायुक्त, धारता धनुमोदन देने से पूर्व कर्मकारिया को ध्रपना दृष्टिकोण स्वस्ट करने का युक्तियुक्त ध्रवसर देगा।
- 9 यदि किसी कारणपण, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन कीना निगम की उस सामूहिक कीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहाँ अपनी चुका है अर्धन नहीं रह जाने हैं, या इस रुकीन के अर्धीन कर्मचारियों को प्राप्त होने बाल फायदे किसी जीति से या हो जाने हैं, तो यह छूट रद की जा सकती है।
- 10. यदि कि.मी कारणवण, नियाजिक उस नियम तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन कीमा नियम नियत करे, प्रीमियम का सदाय करने में असकल रहता है, घौर पालिमी को व्यवस्थत हो जाने दिया जाता है तो, छुट रह की जा सकती है।
- 11. नियाजक द्वारा प्रिमियन के मंदाय में किए गए किसी व्यक्तिकम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाभनिर्देशितियों या विधिक जारिसों की जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उनत स्कीभ के प्रस्तरीय होते, बीमा कायदों के सदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होना।
- 12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के प्रवीत प्राते वाले किसी भदस्य की मृत्यु होने पर उसके हफदार नाम निर्देणिनियों विधिक वारिमों की की मालत रक्षम का संदाय तत्यरत। से ग्रीर प्रत्येक दणा में भारतीय जीवन बीमा निर्यम से बीमाकृत रक्षम प्राप्त होने के सात दिन के भीक्षर मिनिएवन करेगा।

[सं॰ एस-35014(313) / 82---पी॰एफ॰ II]

S.O. 4067.—Whereas Messrs Incx Engine Valves Limited, 17-B, Hadapsar Industrial Listate, Pune (MH/11765), there-inafter referred to as the said establishment, have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benlits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more tavourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 thereinatter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner. Maharashtia, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall Jisplay on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately emol him as a member of the Group Iusurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premimum etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in puyment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nomince/legal heirs entitled for it and in any case with 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(313)/82-PF.II]

का० आ० 4068. — मैसर्स एन० जी० ई० एफ० लिसिटेड, तिईर-कोन हाऊस, डा० ई० मोसेस रोड, सहालक्ष्मी, बस्बई-11 (सहा/17:509) (जिसे इसमें इसके पश्चाल उन्न स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी मिंबज्य निधि और प्रकीण उपबंध प्रधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिपे इसमें इसके पश्चान उन्न प्रधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उरवारा (2क) के प्रधीन छूट विए जाने के लिए प्रावेदन किया है;

ग्रीर केन्द्रीय मङ्गार का समाधात हो गया है कि उक्त स्थापत के कर्मचारी, किसी पूषक प्रभिनाय या प्रीमिथम का संवाय किए जिला ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की मामूहिक बीमा स्कीत के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए से फायदे उन फायदों ने अधिक अनुकृत है जो कर्मछ।री निक्षेप महम्बद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्वान् उत्तप स्कीम कहा ग्या है) के अधीन उन्हें अनुक्रेय है,

भतः, केन्द्रीय सरकार, उकत अधिनियम की घारा 17 की उश्वार। (2क) द्वारा प्रवक्त शक्तियों का प्रयोग करते द्वार और इसने उश्वद अनुसूची में किनिविष्ट शहीं के अधीन रहते हुए, उकत स्थापन को नीन वर्ष की भविष्ठ के लिए उकत स्कीभ के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूखी

- 1 जनम स्थापन के संबंध में तियोज अविधित अविधित अविध्य निष्ठि अप्युक्त महाराष्ट्र को ऐसी विवरणिया भीजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा तिरीक्षण के लिए ऐसी गुविधाएं प्रवान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निविष्ट करें।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रधारों का प्रस्येक माम की ममाध्यि के 15 विक के धीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की जारा 17 की उपधारा (अक) के खीड (क) के अधीन समय-नम्भ पर निरिष्ट करे।
- 3. मामुहिम बीम। स्कीम के प्रशासन में, जिसके घटाराँत लेखाओं का रखा जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का भन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का मंदाय प्रादि भी है, होने वाने सभी कामों का रहन निर्माणक हुना निया जाएता।
- 4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा भनुमोदिन मामृहिक बीमा रकीम के नियमों की एक प्रति, भीर जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुतंख्या की भाषा में उभकी मुक्य बातो का अनुवाद स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रवर्णित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी मिष्य्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की अबिष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजिक सामू-हिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरस्त वर्ज करेगा और उसकी बाबत आध्यस्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संबन्त करेगा।
- 6. यदि उक्त स्कीभ के ध्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाने हैं तो, नियोजक मामूहिक बीमा स्कीम के घ्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में ममूचिन रूप से बृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए मामूहिक बीमा स्कीम के ध्रधीन उपलब्ध फायदे उस फायदों से ग्रधिक ध्रमकृत हों, जो उक्त स्कीम के घ्रधीन घनुक्रेय हैं।
- 7. भामृहिक बीमा स्कीम मे किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्युपर इस स्कीम के प्रधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के प्रधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिमानामनिर्देणिती को प्रतिवार के रूप में दोनों एकमो के प्रंतर के अराबर रकम का मंदाय करेगा।
- 8. साम्हिक बीमा स्कीम के उपवेद्यों में कोई भी संशोधन, प्रावेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त महाराष्ट्र के पूर्व धनुमीवन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां कियी संशोधन से कर्मचारियों के हिन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की भावना हो, वहां प्रावेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त, प्रयता प्रनृशोदन देने से पूर्व कर्मचारि के को प्रयता दृष्टिकीण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त धनमर देगा।
- विद किसी कारणवण, स्वापन के नर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस मामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्वापन पहले अपनी चुका है

मधीन नहीं रह जाने हैं, या इस स्कीम के श्रधीन कर्मवास्थि को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाने हैं, तो यह छूट रह की जा सकती है।

- 10 यदि किसी कारणवा, नियोजक उस नियन तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का सदाय करने में भ्रमफल रहता है, भीर पालिसी को व्यवगत हो जाने विया जाता है तो, छुट रह की जा सकती है।
- 1.1. नियोजक हारा प्रीमिथम के संदाय में किए गए किसी व्यक्तिकम की दशा मैं उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक विरमों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के प्रन्तर्गत होते, बीमा फायवों के संदाय का उत्तरदायिस्व नियोजक पर होगा।
- 12. उनन स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के संबीत श्राने वाले किसी सदस्य की भृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्वेशितियों/विधिक वारिसों की बीसाइन रकम का संदाय तत्यरता से और प्रस्पेक दशा में सारतीय जीवन बीसा निगम से वीसाइन रकम प्राप्त होने के सान दिन के भीतर सनिश्चित करेगा।

[मंकार एस-3501 म 197| 8 3-मी० एक-II]

S.O. 4068.—Whereas Messrs N.G.F.F. Limited, Ticericon House, Dr. E. Moses Road, Mahalaxmi, Bombay-11 (MH/17509) (hereinsfler recerted to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in emoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India, in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident I und Commissioner, Maharashtia (Bombay), maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the clost of every month,
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme

appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance. Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heirs nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner. Maharashtia (Bombay) and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of defualt, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the stid Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the I ife Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(297)/82-PF, II]

का ब्आव 4069 -- मैसर्ग इर्ज निर्धारण इण्डस्ट्रियल फीण्डे कम्पनी, मेलपालाय म रोट कीयम्बल्र-१ (तिमलनाड्/2.356) (जिसे इसके इसके पण्चात उक्त म्थापन कहा गया है) ने वर्मवर्ण भिवन्य निश्चित्रीर पर्भण उन्नवस्थ अधिनयम, 1952 (1952 क. 19) जिसे इसके पण्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) को धारा 17 की उत्थारा (एक) के प्रधान छुट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

श्रीर केन्द्रीय सरकार का समाधान हा गया है कि उक्त स्थापन के कर्मजारी, किसी पृथक भिन्नाय या श्रीभियम का सवाय किए जिला ही, भारत या जीवन बामा निगम की सामृहिक बीमा स्वीम के अर्थात जीवन बोमा के रूप में पायद उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिये के प्रायव उन फायदों में श्रीधक श्रानुकृत है जो कर्मचारी सिक्षेप सहबद्ध कीमा स्कीम, 1976 (जिसे इंग्से इंग्से पश्चान उद्देन स्कीम कहा गया है) के श्रीधन उन्हें श्रानुश्ये है.

श्रात, केन्द्रीय संश्वार, उत्तत अधिनियम की धारा 17 की उत्तधार। (2क) द्वारा प्रवत्त श्राप्तिको के, प्रयोग करते हुए श्रीर इससे उपाधक्र धनुसूबो में विनिद्धिक सती के श्राप्ता रहते हुए, उत्तत स्थापन को न सं वर्ष की ग्राप्ति के लिए उद्दार रहीम के सभा उपगरण के अवर्तन से छुट देता है।

प्र**नम** भी

1 उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियाजक प्राद्याणक भविष्य निधि भ्रासभन तमिलनार का ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरोधण के लिए ऐस। युविधाए प्रदान भररंगा जा कन्द्रीय सरकार समय समय पर निदिष्ट करें।

- ... नियानक, ऐसे निर्माक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 13 दिन के भीतर सदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारों (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिग्द करें।
- अ सामृहिक बीमा र्काम के प्रणासन में, जिसके धन्तर्गत निकाधों का रखा जाना, विवर्णणयों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमिथम का सदय, लेखाओं का धन्तरण, निरीक्षण प्रभारों के सदाय प्रादि भी है, हाने वाले सभी ब्ययों का बहन नियोजक हारा किया जायेगा।
- 4. नियाजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा धनुमादित मामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, श्रीर जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तक उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुमंद्या की भाषा में उसकी मुख्य बासों का धनुनाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शिन करेगा।
- 5 यदि काई ऐसा कसचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनयम के अर्धान छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले हैं। सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाना है तो, नियोजक सामृहिक बीमा स्वाम के सदस्य के रूप में उनका नाम तुरन्त वर्ज करेगा और उसकी बाबत आवायक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदन्त करेगा।
- 6. यदि उनन रकी म के प्रश्लीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाएं जाते हैं तो, नियोजक सामृहिक बीमा स्कीम के अर्थान कर्मचारिया को उपलब्ध फायदों में समृजित गए से बृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामृहिक बीमा स्कीम के अर्थान उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकृष हो, जो उनत स्कीम के अर्धान अनुक्षेप हैं।
- 7. सामृहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के प्रधीत सत्येय रकम उस रक्षम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के प्रधीत होता तो, तियोजक कर्मचारी के विधिक बारिस/तामितिरिक्ती की प्रसिकर के रूप में दोतो रक्षमों के प्रत्तर के बराबर रक्षम का सदाय करेगा।
- 8 सामृहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में काई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त तिमलनाषु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मच रियो के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने नी सभावना हो, वहा प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त, प्रपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति-पुक्त अवसर देगा।
- 9 यदि किसी कारणवण, स्थापन के कर्मजारी, भारतीय जीवन मीमा निगम की उस सामृहिक मीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले मेपना जुका है क्रधीन नहीं रह जाने हैं, या इस स्कीम के श्रमीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाने हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियन नारीआ के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का सदाय करने में ग्रमकल रहता है, ग्रीर पासिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाना है सो, छूट रह की जा सकती है।
- 11 नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यक्तिकम की दश। में उन मृत सदस्यों के नामनिवेशिनियों या विश्विक वारिसों की जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उकत स्वीम के प्रन्तगंत हाते. बीमा फायदी के मदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

1.2. उक्त स्थापत के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के प्राचीत प्राप्त वाले किसी सदस्य की मृत्यु हीते पर उसक हकदार नाम निर्देणितियों। विधिक बारिसी की बीमाकुत रकम का संदाय ततारता में प्रीर प्रत्येक दशा में भारताय जीवन बीमा नियम से बीमाकुत रकम प्राप्त होते के माल दिन के भीतर मुनिष्टिचत करेगा।

[संख्याः एस- 3501 1/277/82-पी॰एफ॰-[I]

S.O. 4069.—Whereas Messrs Engineering Industrial Foundary Company, Mettupalayam Road, Coimbatore-9 (TN/2356) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act. 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, inenjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed here's, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the sald Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insutance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

 1001 GI/82—7

- 9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of defualt, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal helrs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for n and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(277)/82-PF. II]

का॰आ॰ 4070 -- मैसर्स श्री राम रेयन्स, श्रीराम नगर, कोटा-32404 (राजस्थान) (राज॰/1128) (जिसे इसमें इसके पश्चात उत्तत स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपवत्ध प्रधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उकत प्रधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) ने प्रधीन छूट दिए जाने के लिए धातेदन किया है

भीर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक भ्राभिदाय या प्रीमिश्रम का संदाय किए जिला ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामृहिक बीमा स्कीम के अभ्रीत जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं भीर ऐसे कर्मचारियों के लिये ये फायदे उन फायदों से भ्राधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पण्चात उन्त स्कीम कहा गया है) के अर्धन उन्हें अनुजोय हैं.

धतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त ग्रिधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त णिक्तयां का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध भ्रतुसूची में विनिर्विष्ट णतौं के श्रिधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की भ्रवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धीं के प्रवर्तन से छूट देती हैं।

अन्सृचरि

- 1 उक्त स्थापन के सबंध मे नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त राजस्थान को ऐसी विवर्णियां भेजेंगा प्रौर ऐसे लेखा रखेंगा तथा निरोक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करें।
- 2. नियाजक, ऐसे निरीक्षण प्रभावों का प्रत्येक माम की ममारित के 15 दिन के भीतर मंदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त मौधनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के स्रधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।
- 3 सामूहिक बीमा स्कीम के प्रणासन में, जिसके भ्रम्तर्गेत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुन किया जाना, बीमा प्रीमियम का सदाय, रेखाओं का भन्तरण, निरीक्षण प्रभावीं का संदाय-ध्रादि भी है, होने वाले सभी व्यथों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।
- 4 नियोजक, केन्द्रिय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के मूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

- 5. यदि कोई ऐंसा कमेंचारी, जो कमेंचारी भविष्य निधि का या उपन अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजिक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरून दर्ज करेगा और उसकी बाबन आयाण्यक प्रीमियम भारतिय जीवन विभा निगम को संदत्त करेगा।
- 6. यदि उकन स्कीम के भ्रधीन कर्मभारियों को उपलब्ध फायदे बढाए जाते हैं, तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के भ्रधीन कर्मभारियों की उपलब्ध फायदों में समुचिन रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मभारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के भ्रधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से भ्रधिक भनकल हो, जो उक्त स्कीम के भ्रधीन भन्नशेय है।
- 7. सामृहिक बीमा स्कीम में किमी बान के होते हुए भी, यदि किसी कर्मनारी की मृत्यु पर धूम स्कीम के प्रधीन सन्देय रकम उस रकम में कम है, जो कर्मनारी को उस दशा में मेदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के प्रधीन होता तो, नियोजक कर्मनारी के विधिक वारिम/नामनिर्देणिति को प्रतिकर के हप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेग, ।
- 8. सामूहिक वीसा स्कीम के उपकाकों में कोई भी संबोधन, प्रावेशिक मिल्य निधि मासुक्त राजस्थान के पूर्व मनुमीदन के विना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संबोधन से कर्मचारियों के हिंत पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि म्रासुक्त, म्रपना भनु-मोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को भ्रपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति-यक्त भ्रवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवण, स्थापन के कर्मनारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले प्रपत्त चुका है प्रश्लीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के प्रश्लीन कर्मनारियों को प्राप्त होने वाले फायवे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रह की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवण, नियोजक उस नियत तारीख़ के भीतण, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में भ्रसफल रहता है, ग्रीर पालिसी को व्यपगत हो जाने विया जाता है तो, छूट रह की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी ध्वितश्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक बारिमां को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के प्रंक्तर्गत होते. यीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. उपन स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के प्रश्नीन धाने बांधे किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्वेशितियों/ विधिक धारिसी की बीमाक्कन रकम का संदाय तत्परता से भीर प्रत्येक वशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाक्कन रकम प्राप्त होने के मान दिन के भीतर मृतिधिवन करेगा।

[सङ्या एम-35014/276/82-पी०एफ०-H]

S.O. 4070.—Whereas Messrs Shriram Rayons Shriram Nagar, Kota-324004 (Rajasthan) (RJ/1128) (hercinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miseellaneous Provisions Aet, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India, in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident 1-und Commissiner, Rajasthan, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may driect from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approved, give a reasonablt opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under the Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be eancelled.
- 11. In case of defualt, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment

shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case with 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(276)/82-PF. II]

का० आ० 4071....मैसर्ग रौनक इन्टरनेशनल लिमिन्ड, इलाहाबाद सैंक बिल्डिंग, 17-पालियामेंट स्ट्रीट, नई विल्ली-1 (डी एल/2229) (जिसे इसमें इसके पश्चन्। उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निश्च और प्रकीर्ण उपबन्ध प्रधितियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पण्चाएँ उक्त धर्धितियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के प्रधीन छूट दिए जाने के लिए घावेदन किया है;

श्रीर केन्द्रीय भरकार का समाधान हो गया है कि उकत स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथव अभिवाय या प्रीमियन का संवाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामृहिक बीमा स्कीम के ध्रश्रीन जीवन बीमा के स्प में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से श्रधिक भनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहस्र बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्वीम महा गया है) के भ्रधीन उन्हें भ्रमुक्षेय हैं;

भतः, केन्द्रीय सरकार, उस्त प्रधिनियम की घारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते श्रुए और इससे उप। सब धनुसूची में त्रिनिविच्ट शर्नों के प्रधीन रहने हुए, उक्त स्थापन को सीन वर्ष की श्रवधि के लिए उत्त स्कीम के सभी अववन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

भनुसूची

- 1. उन्त स्थापन के सम्बन्ध में नियाजक प्रावेशिक भविष्य निष्ठि प्रायुक्त, दिस्ली को ऐसी विवरणिया भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा सथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निविष्ट करें!
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों ना प्रत्येक माम की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के प्रधीन समय-समय पर निदिष्ट करे।
- 3. सामृहिक बीमा स्कीम के प्रणासन में, जिसके प्रस्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का प्रस्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय प्रादि भी हैं, हीने वाले सभी व्ययों का बहन नियोजक क्षारा किया जीयेगा।
- 4. तियां जभ, केन्द्रीय सरकार दारा यथा धनुमंदित सामृह्कि बीमा स्कीम के नियन की एक प्रति, ग्रीर जब कभी उनमे संशोधन किया जाए, तब उन संशोधन की प्रति तथा कर्में वास्थि को बंदुसंखा की भाषा में उसकी मुख्य बातो या ग्रमुबाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारा, जो वर्भचारी शविष्य निधि का या उक्त प्रधिनियम के प्रधीन हुट प्राप्त किसी स्थापन को भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित विष्या जाता है तो, नियोजिक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम सुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बामग प्रावश्यक प्रीमियम भारतं य जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।
- 6. यदि उनत स्काम के श्रश्नात कर्मश्रास्यां को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तां, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के धर्धन धर्मश्रास्यां को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से बृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मधारियों के लिए सामृहिष बीमा स्कीम के घर्धन उपलब्ध फायदे उन परायदों में अधिक धर्मुकून हों, जो उनत स्कीम के धर्धन धर्मुकून हों, जो उनत स्कीम के धर्मीन धर्मुक्रेय हैं।

- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बास के होने हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के भ्रधीन सब्देय रकम उस रकन से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के भ्रधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक बारिस/नामांनरिंशिसी को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के भ्रन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।
- 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संकोधन, प्रावेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त दिल्ली के पूर्व प्रनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन में कर्मचारियों के हिन पर प्रतिकृल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त, श्रपना धनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को प्रपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवस, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बोमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अथना भूका है प्रधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, सो यह छूट रछ की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवा, नियाजक उस नियत नारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियन करें, प्रीमियम का संदाय करने में प्रमफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाला है तो, सूट रह की जा गकती है।
- 1.1. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सवाय में किए गए किसी व्यक्तिकम की वर्णा में उन मृत सवस्यों के नामनिविधितियों या विधिक वारिसों को जो यवि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के झन्तर्गत होते, बीमा फायवों के संवाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के प्रधीन धाने वाले जिसी सवस्य की मृत्यु होने पर उसके हकवार नामनिर्देशितियों विधिक वारिसो की बीम। इत रकम का संव। य तत्परता से भीर प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमा इत रकम प्राप्त होने के सान विन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014(275)/82-पी०एफ०-11]

S.O. 4071.—Whereas Messrs Raunaq International Limited, Allahabad Bank Building, 17, Parliament Street, New Delhi-110001 (DL/2229) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India, in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the sald Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is fiable to be cancelled.
- 11. In case of defualt, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nomince/legal heirs entitled for it and in any case within / days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(275)/82-PF. II]

कां∘आं 4072 — मैसमं फटिलाइजर कारपोरेशन प्राफ इडिया लिमिटेड, मधुबन, 55 नेहरू प्लेम, नई विल्ली-110019 (जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी प्रविष्य निधि प्लोर प्रकोण उपबन्ध प्रधिनियम 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके परवास उकत ग्रीधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2क) के ग्राधीन छुट दिए जाने के लिए आविदन किया है।

श्रीर फेन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक श्रभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही भारतीय अधिक बीमा निगम की सामृष्टिक बीमा स्कीम के श्रधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उटा रहे हैं श्रीर ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से श्रधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्काम, 1976 (जिसे इसमे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के श्रधीन उन्हें अनुकृष हैं:

श्रतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त श्रधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध भ्रमुस्की में विनिद्धिय शर्तों के भ्रधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की श्रवधि के लिए उक्त स्कीम के सभा उपबन्धों के प्रवर्तन से पूट देवी है।

अनुसूर्च?

- उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रविधिक भनिष्य निधि अध्यक्त दिल्ली को ऐसी जिवरणिया भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी मुविधाएं प्रदान करेगा जो केछीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।
- 2. नियाजिक, ऐसे निर्दाक्षण प्रभारों का प्रत्येक मान की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संवाय करिया जो केखीय सरकार, उनत अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के प्रधःन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 3. स.मूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखामां का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुल किया जाना, कीमा प्रीमियम का सदाय, लेखामां का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का बहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमाहित सामृहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, श्रीर जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस मशोधन की प्रति क्षथा कर्मचारियों के बहुसक्या की भाषा मे उसकी मुख्य बातों का अनुबाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रविणित करेगा।
- 5 यदि कोई ऐसा कमंचारी, जो कमंचारी भविष्य निधि का या उक्त प्रिधिनियम के प्रधीन छूट प्राप्त किया स्थापन की भविष्य निधि का पहले हां सदस्य है, उसके स्थापन में नियंजित किया जाता है तो, नियोजिक सामूहिक बेभा स्कीम के सदस्य के एप में उसका नाम तुरस्त वर्ष करेगा और उसकी बाबत श्रावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम की संदल्त करेगा।
- 6. यदि उक्त स्कीम के प्रक्षीन कर्मणारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं ती, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के प्रक्षीत उपलब्ध फायदे उन फायदों में भिधिक अनुकृत हों, जो उक्त स्कीम के प्रक्षीन अनुक्षेत्र है।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के हीते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के प्रधीन सस्येय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दण। में संदेय हीती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामिग्वेंकिती को प्रतिकर के एप में दोनों रकमों के प्रत्तर के वरांबर रकम का संदाय करेगा।

- 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोर्न भी संशोधन, प्रादेशिक भिविष्य निश्चि प्रापुक्त दिल्ली के पूर्व धनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हिन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि धायुक्त, अपना धनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को धपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तिस्वन प्रवसर देगा ।
- 9 यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मुचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस मामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले प्रपना खुका है प्रधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीक्षि से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रहु की जा सकती है।
- 10 याँद किसी कारणवश, नियोजक उस नियत नारी सं के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम करे संदाय करने में प्रसक्त रहत है, भीर पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जात है तो. कुट रह की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए कियी व्यक्तिसम की दशा में उन मृत सबस्यों के नामनिर्देशितिया या विशिक्ष वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के प्रस्तर्गत होते, बींम। फायबों के संदाय का उत्तरदायत्व नियोजक पर होगा।
- 1.2. उकत स्थापन के सबंध में नियोजक, इस स्कीम के मर्धान माने बाले किसी सबस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्वेणितियों/विधिक वारिसों की बीमाक्कत रकम का संदाय तत्परता में और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाक्कत रकम "एन होने के मान दिन के भीतर मुनिश्चिन करेगा।

[संख्या एस- 35014/274/82-पी एफ- H]

S.O. 4072.—Whereas Messrs Fertilizer Corporation of India Limited, Madhuban, 55, Nehru Place, New Delhi-110019 (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellancous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the life Insurance Corporation of India, in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme):

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner. Delhi, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charge? as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.
- 3 All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient leadures thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance reporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heirs/nomlnee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reuson, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of defualt, if any made by the employer in payment of premium etc. the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nomineellegal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

lNo. S-35014(274)/82-PF. I]

का अ अ व 4073. -- मैसर्स घाई ० पी० सी० ए० - लेखीटरीज प्राइवेट लिमिटेड, 48-कांडिवर्मी एण्डस्ट्रियल एस्टैंट, काण्डीवर्मी (वेस्ट) - वस्वाई - 400067 (महा/1419) (जिसे इसमें इसके पण्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मेच री भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध घिधिनयम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पण्चात उक्त घिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के घर्धान छूट दिए जाने के सिए घानेवन किया है,

धीर केन्द्रीय सरकार का समधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिवाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामृष्टिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन भीमा के रूप में फायदे उटा रहे हैं और ऐसे कर्मनारियों के लिए ये फायदे उन फायदो से अधिक अनुकूष हैं जो कर्मनारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्क्रीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पण्जात् उकत स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुक्रेय हैं;

मृतः, केन्द्रीय सरकार, जनत अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदक्त गामितयों का प्रयोग करते हुए और इसके उपभिद्ध मृतुसूची में विनिधिष्ट गतौं के प्रधीम रहते हुए, उसत स्थापन को तीन वर्ष की प्रविध के लिए उनत स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

- उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य मिधि भागुक्त महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्धिष्ट करें।
- 2. तियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक माम की समारित के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केखीय सरकार, उक्त ग्राधिनियम की द्यारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के भ्राधीन समय-समय पर निर्विष्ट करें।
- 3. सामूहिक में:मा स्कीम के प्रशासन में, जिसके घन्नगैत लेखाओं का रखा जाना विवर्णियों का प्रस्तुन किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का प्रस्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय धादि भी है, होने वाले सभी अवयों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।
- 4. तियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा धनुमोदित सामृहिक बीमा स्कीम के नियमों का एक प्रति, भीर जब कभी उनमें संबोधन किया जाए, तब उस संबोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुमंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का धनुषाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रवर्शित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या जकत प्रधिनियम के प्रधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सबस्य है, उसके स्थापन में नियोजिस किया जाता है तो, नियोजिक सामूहिक बीमा स्कीम के सबस्य के रूप में उसका नाम तुरस्त हुजे करेगा भीर उसकी बाबन प्रावण्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संबत्त करेगा।
- 6. यदि उन्त स्कीम के मधीन कर्मचारियों को उपलब्ध कायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक भीमा स्कीम के मधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से युद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीम। स्कीम के अधीन उपलब्ध कायदे उन कायदों से अधिक मनुकूल हों, जो उन्त स्कीम के अधंन मनुक्रेय हैं।
- 7. सामृहिक बीम. स्कीम में किसी बात के हीते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के प्रधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उसत स्कीम के प्रधीन होता ती, नियोजक कर्मचारी के विधिक धारिस/नामनिर्देशिती को प्रसिकर के रूप में दोनों रकमो के प्रन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।
- 8. सामृहिक घोमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि मायुक्त महाराष्ट्र के पूर्व मनुमोधन के बिना नहीं किया जाएगा भौर जहां किसी संशोधन से कमंब, रियों के हिल पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रावेशिक भविष्य निधि मायुक्त, धपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मणारियों को मपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का स्किन्युक्त भवसर देगा।
- यदि किसी कारणवंश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा क्कीम के, जिसे स्थापन पहले सपना

चुका है भवीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के भवीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायवे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रह की जा सकती है।

- 10. यदि किसी कारणवर्गा, नियां जक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीम। निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में प्रसक्त रहता है, भीर पालिसी को व्ययगित हो जाने विमा जात. है तो, छूट रह की जा सकती है।
- 11 नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यक्तिकम की दश, में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों की जो यदि यह कूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के बन्तर्गत होते, बीमा कायदों के संदाय क. उत्तरव यस्त्र नियोजक पर होगा!
- 12. उनत स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के प्रधोन धाने धाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्वेषितियाँ/ विधिक बारिसी की बीम.कृत रकम का संदाय तत्परक्षा से धौर प्रस्पेक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के बीतर सुनिध्चित करेगा।

[सं**क्या** एस-35014/270/82-पी॰एफ-II]

S.O. 4073,—Whereas Messrs I.P.C.A. Laboratories Pvt. Limited 48, Kandivli Industrial Estate, Kandivli (West)-Bombay-400067 (MH/1419) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of Iudia, in the nature of Life Insurance which are more tavourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner. Maharashtra, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insume Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol

him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heirs/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Oroup Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled
- 10. Where, for any reason, the employer falls to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of defualt, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nomineellegal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(270)/82-PF, III

का० आ० 4074 मिर्म चेमफाब, धम्बत्तूर इण्डस्टियल एस्टेट, मद्राम (टी एन/6767) (जिसे इसमें इसके पण्णात् उनत स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारो भविष्य निश्चि ग्रीर प्रकीण उपबन्ध ग्रश्चित्त्यम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पण्णात् उपत ग्राधित्यम कहा गया है) की धारा 17 की उपक्षारा (2क) के अधीन छूट विए जाने के लिए ग्राचैदन किया है;

भीर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पूथक भिष्ठाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधीन जीवन बीमा के रूप में कायदे उठा रहे हैं भीर ऐसे कर्मचारियों के लिए ये कायदे उन कायदों से अधिन अनुबूल है जो बर्मचारी निजेप सहबद बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चान उक्त स्कीम कहा गया है) के मधीन जन्हें धनकीय है;

मतः, केस्टीय सरकार, उकत प्रधितियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त प्रावित्तयों का प्रयोग करते हुए और इससे उपासद मनुसूची में विनिद्धित गतौं के प्रधान रहते हुए, उकत स्थापन को तीन वर्ष की सबक्ष के लिए उकत स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अन्सूची

- 1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रावेशिक भविष्य निश्चि प्रायुक्त तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा ग्रीर ऐसे लेखा रखेगा नमा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्विष्ट करे।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय भरेगा जो केन्द्रीय मरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के प्रधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 3. मामूहिक बीमा स्कीम के प्रणासन में, जिसके धन्तर्गत लेखाधों का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का मंदाम, लेखाधों का चन्तरण, निरीक्षण प्रभागों का मंदाय घादि भी है, होने न.ले सभी व्ययों का बहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय मरफार द्वारा यथा अनुमोदिन सामूहिक बीमा स्कीम के नियमी का एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उम संशोधन की प्रति नया कर्मच।रियो की बहुमंख्या की भाषा में उमकी मुख्य बामों का अनुवाद, स्थापन के मुखना पर्ट पर प्रश्नान करेगा।
- 5. यवि कोई ऐसा कर्मकारी, जो कर्मकारी भविष्य निधि का या उन्त ग्रिधिनियम के ग्रिधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सवस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजिक सामृहिक बीमा स्कीम के सवस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त वर्ज करेगा ग्रीर उसकी बाबत ग्रायण्यक ग्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संबस करेगा।
- 6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मवारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाने हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मवारियों की उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से बुद्धि की जाने की व्यवस्था करेगी जिससे कि कर्मवारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनजेय हैं।
- 7. मामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, येवि किसी कर्मजारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अजीत सन्देय रक्तम उस रक्तम से कम है, जो कर्मचारी की उस दक्षा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अजीत होता तो, तियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/तामितिर्देणिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रक्षमों के प्रत्यार के बराबर रक्षम का संदाय करेगा।
- 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्राविधिक भिष्य निधि भ्रायुक्त निमलनाडु के पूर्व अनुमोवन के बिन। नहीं विया आएना भीर जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हिन पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रावेशिक भविष्य निधि भ्रायुक्त, अपना भनुमोवन वेने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति-युक्त भवमर वैगा।
- 9. यदि किसी कारणवशा, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीभा निगम की उस सामृहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना खुका है अधीन महीं रह जाते है, या इस स्कीम के अधान कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम ही जाते है, तो यह छूट रह की जा मकती है।
- 10. यदि किसी कारणवंश, नियोजक उस नियन तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियन करें, प्रीमियम का मंदाय करने में ग्रासकल रहता है, भीर पालिसी को व्यवधन हो जाने दिया जाता है तो, छुट रह की जा सकती है।
- 11 नियोजक हारा प्रीमियम के संदाय के किए गए किसी व्यक्तिकम की क्या में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियो या विधिक वारिसों को

जो यदि यह छुट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के घल्लाीत होते, यीमा फायदों के सदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्क स्थापन के सबध में नियोजफ, इस स्कीम के प्रधीन प्रान्त वाले किसी गदस्य की मृत्यु होन पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/ विधिक वारिसी की बीमाकुन रकम का संदाय तत्परता से प्रीर प्रस्येक वक्षा में भारतीय जीवन बीमा नियम से बीमाकुन रकम प्राप्त होने के मात दिन के भीतर सुनिश्चिम करेगा।

[मुख्या एस- 35014/249/82-पी०एफ-H]

S.O. 4074.—Whereas Messrs Chemfab, Ambattur Industrial Estate, Madras (TN|6767) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favoudable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner. Tamil Nadu maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Λ ct, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employers.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Schemes and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees then the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir nominee of the employee as compensation.

- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable apportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, of the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premimum etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibilty for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(249)/82-PF.II]

का आँ० 4075.—मैंसर्स धन्वर कारपोरेशन, लक्ष्मीतिवास, जयेन्द्रगंज, ग्वालियर, 474009 (एम पी/2261) (जिसे इसमें इसके प्रवात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निष्ठि और प्रकीण उपवस्य प्रधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके प्रवन्त जक्त धिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के धधीन छट विए जाने के लिए आयेवन किया है,

श्रीर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उकत स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन योगा निगम की मामृहिक बीमा स्कीम के प्रधीन जीवन बीमा निगम की मामृहिक बीमा स्कीम के प्रधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है श्रीर ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उकत स्कीम कहा गया है) के श्रिष्ठीन उन्हें अनुजेय है;

त्रत केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए भीर इससे उपाबद्ध प्रतुसूची में विनिर्दिष्ट शर्नों के प्रधीन रहने हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की खबधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपायन्थ्यों के प्रवर्तन से छट देती है।

अनुमुखी

- 1 उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायक्त सच्य प्रदेश को ऐसं। विवरणिया भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निर्दाक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्विष्ट करे।
- 2 नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रश्येक मःम वी समाप्ति के 15 विन के भीतर सदाय करेगा जो केन्द्रिय सरकार, उक्त श्रिक्षियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खड़ (क) के ब्रधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 3. स मूहित विमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बंध्या प्रीमियम का संवाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सवाय आदि भी है, होने बाते सभी व्ययों का बहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

- 4. नियोजक, केन्द्रीय नरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कत्री उनमें मंगोधन किया आए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मकारियों की बहुमंत्रया की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रविणित करेगा।
- 5. यकि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त मधिनियम के भवील छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सबस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजिक सामूहिक बीमा स्कीम के सबस्य के रूप में उसका नाम तुरस्त वर्ण करेगा भीर उसकी बाबत भावय्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संबक्त करेगा।
- 6. यपि उनन स्त्रीम के प्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध कायवे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्त्रीम के प्रधीन कर्मचारियों की उपलब्ध कायदी में समृजित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिमसे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्क्रीम के प्रधीन उपलब्ध कायदे उन कायदों से प्रधिक प्रनुकृत हो, जो उक्त स्क्रीम के प्रधीन श्रनु-होय हैं।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मेचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के ग्रर्थात सन्देग रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उकत स्कीम के भ्रंमीत होता तो, नियोजक कर्मचारी के विश्विक वारिस/नामनिर्देणिनी को प्रतिकार के रूप में दोनों रकमो के भ्रन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।
- 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संगोधन, प्रादेशिक मिष्य निधि प्रायुक्त मध्य प्रदेश के पूर्व भनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा भीर जहां किसी संगोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिबूल प्रभाष पढ़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त, प्रपना प्रमुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को भ्रपना दृष्टिकीण स्पष्ट करने का युक्तिस्विक भविष्य प्रकार देना ।
- 9. यदि भिसी कारणवर्ग, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की जस सामृष्टिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले भ्रापना चुका है अभीन नहीं रह जाते हैं, या इन स्कीम के ग्राप्त कर्नचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति में यम हो जाते हैं, तो यह छूट रह की जा सकती है।
- 10. यदि किसी भारणवण, नियोजक उन निया सारीख के भीक्षर, जो भाग्सीय जीवन बीमा निगम निया करे, प्रीमियम का संदाय करने मे असफल ग्रहना है, और पासिसी को व्यागन हो जाने दिया जाना है तो, छूट रह की जा सकती है।
- 11. सियोजक द्वारा प्रीमियन के संदाय में किए गए किसी व्यक्तिकम की देणा में उन मृत तदस्यां के नामनिर्देशितियों या विधिक बारिमो की जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उका रक्तम के घरनगैत होते, बीमा खायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होता।
- 12. उन्हा स्थापन के संबंध में नियोजक, इन स्क्रीक के प्रधीन प्राने नाले किसी सबस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्दीणिनियाँ/विधिक वारिसो की बीमाकृत रक्षम का संदाय तरपरना में प्रोर प्रत्येक देश। में भारतीय जीवन बीमा निगय से बीमाकृत रक्षम प्राप्त होने के साज दिस के भीतर मुनिधिकत करेगा।

[मंख्या एस - 35014/248/82 पीरुगफ-H]

S.O. 4075.—Whereas Messrs Ambar Corporation, Laxminiwas, Jayendraganj, Gwalior-474009 (MP[2261) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act); 1001 GI/82—8

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance Which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 thereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month,
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employees, who is already a member of the Employees' Provident Fund of the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is camployed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees then the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employer been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominte of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium within the due date, as liked by the Life Insurance Corporation of India etc. and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of

deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nomince legal helrs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014 (248)|82-PF.II]

का॰ आ॰ 4076 → नैसर्स दूरवाणी केवल्स प्राइवेट लिमिटेड, "मारुधी मैनजान" दीसरी मंजिल, 19/7, किल्पम रोड, बंगलीर-560052 (किएन/4661) (जिसे इसमें इसके पश्चात उकत स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी मिन्य निधि और प्रकीर्ण उपशब्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात एकत प्रधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के प्रधीन छूट दिए जाने के जिए अविन किया है;

भीर केन्द्रीय संस्कार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक ग्रामियाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के ग्राधीन जीवन बीमा के इस्स में फायबे उठा रहे हैं भीर ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायबे उन फायबों से ग्रामिक भनुकूल हैं जो कर्मचारी निकाप सहब्द्रश्च बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चास उक्स स्कीम कहा गया है) के ग्रामीन पन्हें भनुकोय हैं;

मतः , केन्द्रीय सरकार, उक्त समिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रवत्त मक्तियों का प्रगीग करते द्वुए और इससे उपाबद्ध भनुसूची में चिनिविंद्ध क्षतों के समीन रहते प्रुए, उक्त स्थापन की तीन वर्ष की सर्वधि के लिए स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

- 1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रावेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त कर्नाटक को ऐसी विवरणियां सेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रवान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर भिविष्ट करे ।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाधित के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्धिट करे।
- 3. सामृहिक बीम। स्कीम के प्रशासन में, जिसके प्रन्तर्गत लेखाओं कः रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा प्रीमियम का संवाय लेखाओं का धन्तरण , निरोक्षण प्रभारों का सदाय धावि भी है, होने वाले सभी क्यों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकारु द्वार, यथा भनुमीदित सःमृहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, घोर जब कथी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसको मुख्य बातों का प्रमुखाद, स्थापन के सुचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त प्रधिनियम के प्रधीन छूट प्राप्त किसी स्वापन की भविष्य निधि का पहले ही सवस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजिक सामूहिक बीमा स्कीम के सवस्य के रूप में उसका नाम तुरक्त वर्ण करेगा घौर उसकी बाबत भावस्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीम। निगम की संबन्त करेगा।
- 6. यवि उक्त स्थीम के अधील कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे कहाए जाते हैं तो, नियोजक सामृहिक बीमा स्थीम के अधीन कर्मचारियों

- को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि को जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मजारियों के लिए सामृहिक बीमा स्कीन के अधीन उपलब्ध फायदे उन कायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुक्रेय हैं।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कार्य-चारी की मृत्यु पर इस स्कीम के प्रधीत सर्वेय रक्षम उस रक्षम से क्षम है, जो कर्मचारी की उस बणा में संवेय होती, जब वह उक्त स्कीम के प्रधीत होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक बारिय/नामनिर्वेषिती को प्रतिकर के इप में दोनों रक्षमों के प्रशार के बर्बर रक्षम के संवाय करेगा।
- 8. सामृहिक बीमा स्कीम के उपवक्तों में कीई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटक के पूर्व प्रनुमोदन के बिना नहीं किया जाएमा प्रीप जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हिन पर प्रतिकृत प्रभाय महने की संभावना हो, बहां प्रावेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना वृष्टिकोण स्पष्ट करने का पुक्तियुक्त भवसर देगा ।
- 9. यदि किसी कारणतथा, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले धवना चुका है प्रधीन नहीं रहि जाते हैं, या इस स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों की प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रह की जा सकती है।
- 10. यदि किसी काश्यवण, नियोजक उस नियम गारीख के भीनर जो भारतीय जीवन बीमा नियम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में स्रसकत रहता है, स्रोर पालिसी की व्यपगत हो जाने विया जाना है तो छूट रह की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाध में किए गए किसी क्यांतिकम की वशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितीयों या विश्विक पारिसों की जो यदि यह छूट न दो एई होती तो उत्तर स्कीम के सम्मानित होते, जीमा फायबों के संशय के उत्तरदाशित्र िशंका पर होता ।
- 12 उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीत के श्रधीर शामि वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हंकवार नाम निर्देशिनीयों विभिन्न वारिसी की बीमाइत रकम का संदाय तत्परना से भीर प्रत्येक वशा में भारतीय जीवन बीमा नियम से बानाइत रकन प्राप्त हाने के साल विभ के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं॰ एस-35014/244/82-गे॰ एक-II]

S.O. 4076.—Whereas Messrs Doorvanl Cables Private Ltd., Maruthi Mansion, 3rd Floor, 19/7 Canningham Road, Bangalore-560052 (KN-4661) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under subsection (2A) of section 17 of the Employees' Prov dent Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 cf 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life Insurance which are more favourable to such employees the the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of Insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employers.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Emplioyees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Oroup Insurance scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium etc. the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

काल्भाल 4077—मैसमें मेटल बाक्स इंडिया सिमिटेड, 19, इलाइक मृदाली स्ट्रीट, तोविरपेट, मद्रास (टी एन/196) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उपत स्थापन कहा गया है) ने कर्भचारी भविष्य निधि मौर प्रकोण उपबन्ध मधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया है) की झारा 17 की उपसारा (2क) के भ्रमीन छूट विए जाने के लिए माबेदन किया गया है;

धीर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उनत स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक प्रांक्षवाय या प्रीमियम का संवाय किए बिना हैं, भारतीय जीवन पीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं भीर ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से प्रधिन प्रनुकूल हैं जो कर्मचारी निजेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उनत स्कीम कहा गया है) के प्रधीन उन्हें अनुनेव हैं;

श्रतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधितियम की धारा 17 की उपधारा (2क) क्षारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिद्दिष्ट शर्तों के धवीन रहते हुए, उक्त स्थापन की सीन वर्ष की प्रवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबग्धों के प्रवर्तन से छूट बेती है।

अनुसूची

- उन्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रावेशिक मिष्ठण निधि प्रायुक्त तमिलनाडु की ऐसी विवरणियां भेजेगा प्रौर ऐसे निका रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रवान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निविध्ट करें।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रस्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त मिनियम की घारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के भिन्नोन समय-समय पर निर्विष्ट करें।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रकासन में, जिसके धंक्षर्यत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीम। प्रीमियम का संवाय, लेखाओं का प्रस्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संवाय प्रावि भी है, होने वाले सभी क्यों का बहुन नियोजक द्वारा किया आयेगा।
- 4. नियोजक, केन्दीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, भीर जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसँख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातो का प्रनुवाद स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मवारी, जो कर्मवारी भविष्य निश्चि का या उक्त प्रधिनियम के भ्रधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निश्चि का पहले ही सवस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है हो, नियोजिक सामृहिक बीमा स्कीम के सवस्य के रूप में उसका नाम तुरक्त दर्ज करेगा भीर उसकी बाबन भ्रावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सबत्त करेगा।
- 6. यदि अन्त स्कीम के अक्षीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामृद्दिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समृदिन रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामृद्दिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकृत हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अप्रोत अनुकृत हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुकृत हों।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए बी, यदि किसी कर्मजारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मजारी को उस दया में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मजारी के विधिक बारिस/नामनिर्देशिती को

प्रतिकर केरूप में दोनों रक्षमों के घन्तर के बराबर रकम का सवाय करेगा।

- 8. सामृहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी रांगोधन, प्रावेणिक भविष्य निधि अप्वम्म भिन्ततां के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना प्रमुमोदन देने से पूर्व वर्मचारियों को प्रपना दृष्टिकीण स्पष्ट करने का युक्तियुवन अवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणत्रश, स्थापन के कर्मवारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक कीमा स्कीम के, जिमें स्थापन पहले अपना चुका है अर्धान नहीं रह जाने हैं, या इस स्कीम के अर्धान कर्मचारियों को प्राप्त होने बाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट ग्रह की जा सकसी है।
- 10. यदि किसी कारणवया, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीयन बीमा नियम नियत करे, प्रीमियम कासंदाय करने में भसपाल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है ती, कृट रह की जासकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किए गए किसी व्यक्तिक की दशा में उन मृत सवस्यों के नामितर्वेणितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होंती तो उकते स्काम के प्रत्येत होंते, बीमा फायबों के संवाय का उक्तरवायिक नियोजक पर होगा।
- 12. उक्त स्थापन के सबंध में नियोजना, इस स्कीम के धर्मीन माने बाले किसी सबस्य की मृत्यु होने पर उसके हजदार नाम निर्देशनियी/ विधिक वारिसो की दीमाइन रकम का सवाम तरपरता से मीर प्रत्येक बना में भारतीय जीवन बाग। निगम से बीमाइन एकम प्राप्त होने के साल बिन के भीतर सुनिश्चिल करेगा।

[संख्या एस॰ 35014/241/82-पी॰एफ॰ II]

8.0. 4077.—Whereas Messrs Metal Box India, Ltd., 19, Elaiya Mudali Street, Tondiarpet, Madras (TN/196) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Finds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of furce years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc shall be borne by the employers.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6 The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where app amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the empoyer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(241)/82-PF.II]

कां कार 4078 - मैससं इथिको हुग्स एण्ड कैमिकस्स मैस्यूपैक्चरित कं 37, ए-इण्डस्ट्रियल एस्टेट पोली पाउण्ड, इन्योर--- 452002 (कोड स०प्र० 2470) (जिले इसमें इसके पश्चात उक्त स्रण्यत एए स्ता है) ने कर्मचारी स्रविच्य निविधीर प्रकाणं उपबन्ध मिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्रविनियम कहा गया है) की बार 17 की उपवारा (2क) के स्रवीन सूट दिए जाने के लिए सानेवन किया है;

भीर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उन्नत स्थापन के कर्मचारी, तिसी पृथक प्रभिदाय या प्रीसियम का सदाम किए दिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की मामूहिक बीमा स्कीम के भ्रधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहें हैं भीर ऐसे कर्मचारियों को लिए ये फायदे उन फायदों से श्रधिक अनुकूलन हैं भो कमंचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उन्नत स्कीम कहा गया है) के भ्रधीन उन्हें भ्रमुकेय है,

मतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त मधिनियम की घारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रवत्त मक्तियों का प्रयोग करते हुए मीर इससे उपावद मनु-सूची में विनिदिन्द शर्ती के प्रधान गहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की मबधि के लिए जा। स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अमृसूची

- 1 उपत स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रावेशिक श्रविष्य निधि प्रायुक्त सध्य प्रदेश को ऐसी विवरणिया भेजेगा घीर ऐसे लेखा रखेगा तथा निर्देशिक के लिए ऐसी मुविधाएं प्रवान करेगा का केर्ब्राय सरकार, समय-समय पर निविध्द करे।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभार का प्रस्येक मास की समाप्ति के 15 विन के भीतर मनाय करेगा जो केन्द्रिय गरकार, उदन प्रधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के प्रधीन समय-समय पर निविष्ट करें!
- 3. सामूहिक भीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके प्रकारित लेखान्नों का एखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखान्नों का भन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय प्रांदि भी है, होने वाले सभी ब्ययों वा वस्तुत नियोजक क्षारा किया जायेगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुसंदित सामृहिक बीमा स्कीस के नियमों का एक प्रति, और जब ककी उनमें संगाधन किया जाए, तब उस समोधन की प्रति क्षया कर्मचारियों की सहुसक्या की भाषा में उसकी मुख्यबातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदिशित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मकारी, जो कर्मकारी मिवय्य निधि का या उक्त प्रक्षितियम के प्रधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सबस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजिक सामृद्धिक कीमा स्कीम के सबस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा भीर उसकी बाबत भावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन कीमा निगम को संबक्त करेगा।
- 6. यदि उनते स्कीम के भ्रधीन कर्मधारियों को उपलब्ध कायदे बढ़ाएं जाते हैं, तो, नियोजक सामूजिबीमा स्कीम के भ्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामृहित बीभा स्कीम के भ्रधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से भृथिक प्रतृष्ट्रग हीं भी उनन स्कीम के भ्रधीन यनुक्रेय हीं।
- 7. सामृहिक बीचा रुकीम में किसी बात के हों। हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्वीम के श्रवीन सस्वेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दणा में संदेय हाती, जब बहु उक्त स्कीम के श्रवीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के बिधिक वरिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप भें दोना रकमों के झन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।
- 8. सामूहिक बीम। स्कीम के उपबन्धां में कोई भी संबोधन प्रावेशिक भिवण्य निधि आयुक्त मध्य प्रवेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएका भीर जहां किया संशोधन के गर्मकारियों के हिन पर प्रसिक्त अभाव पड़ने की संझावना हा, वहां पारेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अनमा अनुभोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दुष्टिकीण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त भवसर देगा ।

- 9. यदि किसी कारणवाग, स्थापन के कर्मणारी, भारतीय कीवन बीमा निगम की उस सामृहिक बीमा स्कीम के, जिस स्थापन गहले अपना मुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम को अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने बाल फायदे किसी रीति से कम हो जाने हैं तो यह छूट रह की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवया, नियोजक उस नियन आरीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियस करें। श्रीमियम का संवाय करने में असफल रहना है, भीर पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रह की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा भीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यक्तिकम की दशा में उन मृथ सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक बारिसों की जो यदि यह छूट न घी गई होती तो उक्त स्कीय के प्रत्येत होते, बीमा फायदों के सदाय का उत्तरवायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम प्रधीन प्राणे वाले किसी सदस्य की मृत्यु होते पर उसके हकदार नाम निदेशितिया/ विश्विक वारिसो की बीमाइत रकम का संदाय तत्परता से मौर प्रत्येक स्था में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाइत रकम प्राप्त होने के साल दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संहया एस-35014/239/82-पी०एफ० II]

S.O. 4078.—Whereas Messrs Ethico Drugs & Chemicals Mfg. Co., 37-A, Industrial Estate, Pologround, Indore-452003, (MP/2470) (hereinafter refrered to as the said establishment have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India, is the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the condition, specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts, the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Madhya Pradesh, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses invoved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees,
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employer in

his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance surance Scheme, if on the death of an employee the amount ployees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approard of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the empoyer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of defaut, if any made by the employer in payment of premium the repsonsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India

INo. S-35014(239)/82-PF.III

कार्लमा • 4079. — मैससं लीबर्स इंजीनियरिंग वर्क्स, इण्डस्ट्रियल टाउन जालकार-144004 (पी/एन)160) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी मिवव्य निधि भीर प्रशीं उपजस्य मिविनयम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चान उक्त मिविनयम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के मधीन छूट विए जाने के लिए मावेवन किया है;

श्रीर केण्ड्रीय सरवा? का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कमचारी, किसी पृषक प्रभिवाय या प्रीमियम का संवाय िए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामृहिक बीमा स्कीम के प्रधीन जीवन बीमा के रूप में कायदे उठा रहे हैं श्रीर ऐसे कर्मवारियों के लिए ये फायदे उन कायवों से प्रधिक श्रनुकूल जो कर्मवारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के प्रधीन उन्हें श्रनुहोय है;

मतः केण्डीय सरकार, उक्न प्रधितियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्रीर इससे उपायक मनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्ते के मधीन रहते हुए, उक्त स्वापन की तीन वर्ष की मनिधि के लिए उक्त स्वीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

वनुत्र्धी

- उक्त स्वापन के सम्बाध में नियोजक प्रादेशिक विवय निधि मायुक्त पंजाब को ऐसी विवरणियां मेजेसा धीर ऐसे लेखा तथा निरोक्षण के निए ऐसी सुविधाएं प्रवान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट वरें।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रधारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 विश्व के भीतर संवाय करेगा को केन्द्रीय सरकार, उनत प्रधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के प्रधीन समय-समय पर निर्विष्ट करे।
- 3. सामृहिक सीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके प्रन्तगैत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संवाय, लेखाओं का घन्तरण, निरीकण प्रभारों का संवाय घावि भी है, होने वाले सभी व्ययों का बहुत नियोजक द्वारा किया जाएगा।
- 4. नियोजक, केश्मीय सरकार द्वारा यथा अनुवादित सामृहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, भीर जब कभी उनमें संबोधन किया जाए, तब उस संबोधन की प्रति तथा कर्में चारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का प्रनुवाद, स्थापन के सुचना-पट्ट पर प्रविधित करेगा।
- 5. मदि कोई ऐसा कर्मबारी, जो कर्मबारी भविष्य निधि का या उक्त भिवित्यम के प्रधीन कूट प्राप्त किसी स्वापन की मविष्य निधि का यह यह है। सबस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सबस्य के रूप में उसका नाम सुरूम वर्ज करेगा और उसकी बाबत भावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम की संदल करेगा।
- 6. यदि उक्त स्कीम के प्रधीन कं मक्ति की उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामृहिक बीमा स्कीम के प्रधीन कर्मवारियों को उपलब्ध फायदों में समृश्वित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मवारियों के लिए सामृहिक बीमा स्कीम के प्रधीन उपलब्ध फायदे उन कायदों से प्रधिक प्रमुक्त हों, जो उक्त स्कीम के प्रधीन प्रकृतिय हैं।
- 7. सामृहिक बीमा स्तीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मवारी की मरयु पर इस स्तीम के मधीन सन्वेम रकम उस रकम से कम है, जो कर्मवारी की उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के मधीन होता तो, नियोजक कमवारी के अधिक वारिस/नामनिवेंकित को प्रतिकर के रूप में बोनों रकमों के भन्तर के बराबर रक्त सा संवाय करेगा।
- 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपनकों में काई भी संशोधन, प्रावेषिक मिल्य निधि प्र.युक्त पंजाब के पूर्व प्रनुमोधन के बिना नहीं किया जाएगा भीर जहां किसी संशोधन से कमचारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की संवावना हो, वहां प्रावेशिक मिल्या निधि भायुक्त, अपना भनुमोधन देने से पूर्व कर्मचारियों को भ्रयमा बृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त प्रवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवग, स्थापन के फर्नेवारी, भारतीय जीवन थीमा निगम की उस सामूहिक भीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले प्रपान चुका है प्रधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीक के प्रधीन कर्मवारियों को प्राप्त होंने वाले फायदे किसी रीति से कम ही जाते हैं, तो यह खूट रह की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवंश, नियोजक उस नियत तारील के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निवम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में मसक्तम रहता है, मीर पाणिसी को न्ययगत हो जाने दिया जात है तो छुट रह की जा सकती है।

- 11. नियोजक द्वारा त्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यक्तिका की दशा में उन भूत सदस्यों के नाम नियमित्रतयों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न की गई होती तो उक्त स्कीम के संगाँत होते, बीमा फायदों के संदाय का अत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. उक्त स्वापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के धर्मान धाने बाले किसी संदेश्य की मृत्यु होने पर उसके हुकबार नाम निवेशितियाँ/ विधिक बारिसों की बीमाइत रकम का संवाय सत्परतः से धौर प्रत्वेक वज्ञा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाइत रक्षम प्राप्त होने के सात विभ के भीतर सुनिश्चित भरेगा।

[संख्या एस-35014/338/82-पी०एक०-II]

8.0. 4079.—Whereas Messrs Leader Engineering Works, Industrial Town, Juliundur-144004 (PN/160) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Empioyees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be icss than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the empoyee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shail be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner. Punjab and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to expiain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life InsuranceCorporation of India as aiready adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the empoyer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the poicy is allowed to iapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the repsonsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominees/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(238)/82-PF.II]

का०आ० 4080-- मैसैस हिन्दुस्तान बाउन बोवरी लिमिटेड, पो०बाक्स नं 16 प्राई०ए० फरीवाबाव (पी०एन०375) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कमैंबारी भविष्य निधि धौर प्रकींण उपबन्ध भवित्यस, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चान उक्त प्रक्रितियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के भवित छूट दिए जाने के लिए भविदन किया है;

मौर केन्द्रीय सरकर का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मे कारी, किसी पृषक मिना हो, मारतीय का संवाय किए बिना हो, मारतीय जीवन बीमा निगम की सामृहिक बीमा स्कीन के मधीन जीवन बीमा के किए में कायवें उठा रहे हैं भौर ऐसे वर्मे वारियों के लिए में कायवें उन कायवें से मधिक अनुकूल हैं जो कर्मे बारी निवाप महबद्ध बीमा स्कीम 1976 (बिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के भर्मान उन्हें भन्नेय है;

मत., केन्द्रीय सरकार, उक्त मिलिन्यम की धारा 17 की जिपमारा (2क) द्वारा प्रवत्त गक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध मनुसूची मे विनिधिष्ट गर्तों के मधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की मथिध के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवतन से छूट वेती है।

अनुसूची

 उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रावेशिक मिष्य निधि मायुक्त, पंजाब को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा सथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रवाद करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निविष्ट करें।

- 2. तियोजक, ऐसे तिरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाध्य के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जा केन्द्रीय सरकार, उक्त मधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के मधीन समय-समय पर तिर्दिष्ट करें।
- 3 मामूहिक भीषा स्थीम के प्रशासन में, जिसके घल्नैगत सेखाओं का रखा जाना, विश्वरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संवाय, लेखाओं का प्रमन्त्रण, निरीक्षण प्रभारों का संवाय प्राप्ति भी हैं, होने वाले सभी ज्यायों का बहुन नियोजन हारा किया जायेगा।
- 4. निर्माणक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुसीदित सामूहिक कीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति प्रौर जब कभी उनमें संगोधन किया जाए, तैब उस संगोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का प्रतृवाद, स्थापन के सूबनान्यह पर प्रदेशित क्षेत्रेगा ।
- 5. यदि कांई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्स मिनियम के मधीन छूट प्राप्त किसी स्वापन की भविष्य निधि का पहले ही सबस्य है, उसके स्वापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजिक सामूहिक बीमा स्तीम के सदस्य के रूप मे इसका नाम तुरम्त को करेगा भीर उसकी बावन मावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा नियम को सेवल करेगा।
- 6. यदि जनत स्कीम के भवींन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ायें जाते हैं तो, नियोजक मामूहिक बीमा स्कीम के भवीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में ममुधित रूप से बुद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा ज़िससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के भवीन उपलब्ध फायदे उम फायदों से भविक शानुकृत हो, जो उक्त स्कीम के भवीन सन्नेय हैं।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मकारी की मृत्यू पर इस स्कीम के अधीन सबैय रक्षम उम रक्षम से क्षम है, जो कर्मकारी को उस बया में संदेय होती, जब यह उक्ष्म स्कीम के खडीत होता तो, तिरोमक कर्मकारी के विक्रिक बारिम/नाम निर्वेणिक्षी को प्रतिकर के रूप में दोनो रक्षमों के अन्तर के बराबर रक्षम का संदाय करेगा।
- 8. सामृहिक बीमा स्कीम के उबन्धी में काई मी संशोधन, प्रावेशिक धिविष्य निधि भायुक्त, पंजाब के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगी भीर जहां किसी संशोधन से कर्मजारियों के हिस पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रावेशिक भिन्द्य निधि भायुक्त धपना धनुमोदन देने से पूर्व वासेनारियों की भपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्त हुन भवेसर देगा।
- 9. विदिक्षिणी कारणवण, स्थापत के कर्मजारी, भारतीय जीवन बीमा नियम की उस माम्हिक बीणा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अवीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाने कायदे जिसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह छूट रह की जा सकती है।
- 10. यदि किमी कारणवण, नियोजक उस निया कारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा नियम नियम करें, प्रीमियम के संदाय करने से ससकल रहता है, और पालिसी की व्ययगत ही जाने दिया जाता है मा, छूट रह की जा सकती है।
- 11. नियोगफ द्वारा प्रीभिथम के संवाय में किए गए किसी व्यक्तिकम की वक्ता में उन मृत मदस्यों के नाम निर्देशियिया या विधिक बारिमों की को यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के मन्तर्गत होते, बीमा फायदी के संदाय का उत्तरशायित्य नियालक पर होगा।
- 12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में तिपीजक, इस स्कीम के प्रवीत धाने वाले किसी संवस्य की मृत्यु होने पर उसके हक्षवार नाम निर्देणिनियो/

विधि वारिसों की बीमाकृत रकम का सदाय तत्परता से घोर प्रस्येक दक्षा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम पाष्त्र होने के सान बिन के भीसर मूनिश्चित करेगा।

[संख्या एन 35014/237/32-पी॰एफ॰-I1]

S.O. 4080.—Whereas Messis Hindustan Brown Boverl Ltd., Post Box No.16, I.A. Faridabad (PN|375) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellateous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which have more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government herbey exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDUI F

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses invoved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on-the death of an employe the amount nayable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the empoyee as compensation
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of Regional Provident Fund Commissioner, Punjab and

where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the empoyer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of of default, if any made by the employer in payment of premium the repsonsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No.S-35014(237)|82-PF.II]

का॰ आ॰ 4081 .-- मैसर्स श्री गणेश रोलिंग मिस्स, विस्ती रोड, सातरोड खुर्च (हिसार)-125044 (कोड नं॰ पी॰ एन॰/4563) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा थया है) ने कर्मचारी भिष्टिय निधि और प्रकीण उपबंध प्रधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा थया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के प्रधीन छूट दिए जामें के लिए श्रायेदन किया है;

भीर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मेचारी, किसी पृथक अभिवाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम को सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं भीर ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके परचात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुक्षेय हैं;

भतः, केन्द्रीय सरकार, जक्त भाधित्वयम की धारा 17की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए भीर इससे जपाबद्ध भनुसूची में विनिर्विष्ट शर्तों के भ्रधीन रहते हुए, जक्त स्थापन को तीन वर्ष की भ्रषधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट बेती है।

अनुस्ची

- उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रावेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त पंजाब को ऐसी विवरणियां भेजेश भीर ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीकण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निविष्ट करे।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 विन से भीतर संवाम करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की सारा 17 के उपघारा (3क) के खंड (क) के प्रधीन समय-समय पर निविद्ध करे।
- 3. सम्हिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके घन्तर्गत सेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का प्रन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय घावि भी है, होने वाले सभी ध्ययों का बहुन नियोजक द्वारा किया आयेगा।

- 4. नियोजक, केलीय सरकार द्वारा यथा घनुमोदित सामृहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रांत, भौर जब कभी उनमें संबोधन किया जाए, तब उस संबोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का घनुबाद स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदिशित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भिष्ठिय निधि का या उक्स भिधिनियम के भिष्ठीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भिष्ठिय निधि का पहले हो सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजिक सामृहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम सुरन्त वर्ज करेगा और उसकी बाबत श्रावश्यक श्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।
- 6. यदि उक्त स्कीम के ध्रधीन कर्मशारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामृहिक बीमा स्कीम के घ्रधीन कर्मचारियों को उप-लब्ध फायदों में समृचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामृहिक बीमा स्कीम के घ्रधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से घ्रधिक घनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के घ्रधीन ध्रनुत्रेय हैं।
- 7. सामृहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कमंचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के मधीन सन्देय रकम उस रकन से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के मधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामिवेंशिती को प्रतिकर के रूप में वोनों रकमों के भ्रष्टर के बराबर रकम का संबाय करेगा।
- 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कीई भी संगोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि मायुक्त पंजाब के पूर्व मनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा मौर जहां किसी संगोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त, प्रपना मनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को भपना वृष्टिकीण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त प्रवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय खीवन बीमा िमगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले घ्रपना चुका है प्रधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्वीम के प्रधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने बाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह छूट रह की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीका के भीतर, वो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में श्रसफल रहता है, और पालिसी को व्यपशत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रह की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किए गए किसी व्यक्तिकम की दक्षा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के मंतर्गत होते, बीमा कायदों के संवाय का उत्तरवायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के घ्रधीन घाने बाले किसी सबस्य की मत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्दोणितयों/ विधिक बारिसों की बीमाक्षत रकम का संबाय तत्परता से भौर प्रत्येक दशा में मारतीय जीवन बीमा नियम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सास दिन के भीतर मुनिध्वित करेगा।

[संख्या एस-38014/236/82-पी० एफ-II]

5.0. 4081.—Whereas Messrs Shree Gantsh Rolling Mills, Delhi Road, Satrod Khurd (Hissar)-125044 (Code No. PN 4563) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976, (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Λ ct and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHFDUI F

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner. Punjab, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc shall be borne by the employers.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premimum in tespect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be hable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life

Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled

- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heir, of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominec|legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(236)/82-PF, II]

कार आर 4082 .--मैनमें नेमनल को-प्रापरेटिज कंज्यूमर्स फैडरेमल धाँक धीड्या लिमिटेड, मुख्यालय दीपाली, (5वां फ्लोर) 92-नेहरू प्लेस, नई विल्ली-110019) कोड-नं धीएल 2333, (जिसे इसमें इसके प्रचात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी अविषय निधि घौर प्रकीण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952का 19) जिसे इसके प्रचात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है कि धारा 17 की उपधारा २७ के अधीन छुट विए जाने के लिए धायेदन किया है;

त्रीर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिवाय या प्रीमियम का संदाय निए जिला ही, भारतीय जीवन बीमा निशम की सामृष्टिक बीमा स्कीम के अर्थान जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए से फायदे उन फायदें से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चान् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुशेय है;

श्रतः, केन्द्रीय सरकारः, उक्त श्रिष्ठिनियमं की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रवत्न गक्तियों का प्रयोग करने हुए श्रीर श्रममे उपाबद्ध श्रन्-सूत्री से विनिर्दिष्ट गर्नों के श्रधीन रहने हुए, उक्त स्थापन का तीन वर्ष की श्रवधि के निए उक्त स्कीम के सभी उपवधी के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूचिर

- उक्त स्थापन के संबंध मे नियोजक प्रादेशिक अधिष्य निधि प्रायुक्त विल्ली को ऐसी विवरणिया गेजेगा घीर ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रवात करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निविध्द करे।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समास्त्रि के 15 दिन के भीतर गंदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रक्षिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खड़ (क) के प्रधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।
- असामृहिक बीमा रूकीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गंस लेखाओं का पन्ना जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संवाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संवाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन निर्योजिक हारा किया आयेगा।
- श्रीतियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा प्रनुमोदित सामृहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, ग्रीर जब कभी उनमें सणोधन किया जाए, तब उस संगोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का धनुबाद स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उनते अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, तियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम सुरन्त दर्ज करेगा भीर उसकी बाबल श्रावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम की संवत्त करेगा।

- 6 यदि उक्त स्कीम के श्रधीन कर्मचारियों की उपलब्ध फायबे बढाए जाते हैं ता, तिसाजक सामृष्टिक बीमा स्कीम के श्रधीन कर्मचारियों की उप-अच्छा फायदी में समृज्यित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामृद्धिक बीमा स्कीम के ग्रधीन उपलब्ध फायदें उन फायदों से स्थिक श्रनुकृत हो, जा उक्त स्वीम के ग्रधीन श्रमुकी है।
- 7 सामृहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मन्यू पर इस स्कीम के अधीन सदेय रक्तम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी की उस दणा में सदेय हाती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन हाता नी, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देणिकी की प्रतिकार के रूप में दोनों रकमों के अतर के बराबर रक्षम का सदाय करेगा।
- 8 सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में काई भी सणोधन, प्राद्धीणक्ष भविष्य (त्रीय ग्रायुक्त दिल्ली के पूर्व ग्रनुमोदन के बिना नहीं किया जायेजा ग्रीर जहां किया सणाधन से कर्मचारियों के दिल पर प्रतिकूल प्रभाव पहने की संभावना हो बही, प्रादेणिक अधिष्य निधि ग्रायुक्त, ग्रपना ग्रनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को ग्रपना दृष्टिकीण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त श्रवसर देना।
- 9. यदि किसी कारणवण, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन यीमा निराम की उस मामृहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अर्थान नहीं रह जाते है, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों का प्राप्त होने बाने फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह छूट रह की जा सकती है।
- 10 यदि शिक्षी कासणवण, नियंजिक उसं नियम तारीख के भी सर जो भारतीय जीवन बीमा निर्मा नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपनन हो जान दिया जाना है ती. छूट • इ की जा सकती है।
- 11. निर्याजन तारा प्रीमियम के सदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशों में उन मून सदस्यों के नामनिर्दाणिनियों या विधिक वारियों को जो यदि यह, छुट न दीं गई हानी नो उक्त स्कीम के अनुगंत हाले, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियाजक पर होगा।
- 12 उनम स्थानन के सबंध में नियाजक, इस स्कीम के ग्रधीन आने वाले किसी सदस्य की मन्यु होने पर उसके अकदार नाम निर्देणितियो/ विधिक वारिसो की बीमाकुन रकम का संवाय नथरना से श्रीर प्रस्येक बवा में भारतीय जीवन बीमा निर्मा से बीमाकुन रकम प्राप्त होने के नान दिन के भीनर मुनिण्यित करेगा।

[संख्या एस-३5014/231/82-पी० एफ-2]

S.O. 4082.—Whereas Messrs National Cooperative Consumer's Federation of India Ltd., H. O.: Deepali (5th Floor), 92, Nehru Place, New Delhi-110019 (Code No. DL|2333) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme):

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto,

the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employers.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall airrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner. Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said establishment

shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee|legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

(No. S-35014(234)/82-P.F. III

सर्वे दिल्ली, 13नवम्बर, 1982

कार आर 4083 .—मैं समं बीर सीर एमर इंजीनियरिंग प्रॉबक्ट्स, ग्रसरोन, रोपड़ (पी एन। 5959) (जिसे इसमें इमके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी मिलव्य निधि और प्रकीण उपक्षेत्र प्रधिनियम, (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है की धारा 17 की उपधारा (2क) के प्रधीन छूट दिए जाने के लिए प्रावेदन किया है;

भौर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अधिदाय या प्रीक्षियम का संवाय किए बिना ही। भारतीय जीवन बीमा निगम की सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं भौर ऐसे कर्मचारियों के लिए में फायदे उन फायदों से प्रधिक मनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप मनुबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पक्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के प्रधीन उन्हें अनुबंध है;

मतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त भिक्षितियम की धारा 17 की उपबारा (2क) द्वारा प्रदक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भीर इससे उपाबद मत्-सूची में विनिर्विष्ट शर्तों के भिद्यान रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की धयिष्ठ के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्नों के प्रवर्तन से सूठ वेली है।

अनुसूची

- उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त पंजाब को ऐसी विवरणियां मेजेगा घौर ऐसे लेखा रखेगा तथा निरोक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रवान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।
- 2. नियोजभ, ऐसे निरीक्षण प्रचारों का प्रश्येक सास की सनाध्ति के 15 विष के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपघारा (3क) के खंड (क) के प्रधीन समय-समय पर मिविष्ट करें।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके शंतर्गत लेखाओं का रखा जाना जिल्पणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीतिमयम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय शादि भी है, होने वाले सभी क्यों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, भीर जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मेचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद; स्थापन के श्रुचन प्टिट पर प्रविश्ति करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मकारी, जो कर्मकारी भविष्य निधि का या उक्त श्रीधनियम के श्रीम छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सबस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजिक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त वर्ग करेगा और उनकी बाबल श्रीकथक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।
- 6. यदि उक्त स्कीम के म्रद्रील कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते, हैं तो, नियोजक सामृहिक बीमा स्कीम के म्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समृचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था फरेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामृहिक बीमा स्कीम के म्रधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से म्रिक्ड मनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के म्रधीन मनुक्षेय हैं ।

- 7. सामृद्धिक बीमा स्कृिम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी मार्मभारी की मृत्यु पर इस स्कीम के प्रधीन संवेय रक्तम उस रक्तम से कम है, जो कमैं नारी को उस वसा में संवेय होती, जब वह उक्त स्कीम के प्रधीन होता, तो नियोजक अमें नारी के विधिक वारिमानामिक शिलो को प्रतिकर के रूप में वोनों रक्तमों के अंतर के वरावर रक्तम का संवाय करेगा।
- 8. सामृहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रावेशिक भिविष्य निधि भायुक्त पंजाब के पूर्व भनुमोदन के बिना नहीं किए जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मनारियों के हिन पर प्रतिकृत प्रजाब पढ़ने की संभावना हो वहां प्रावेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त, प्रथमा प्रमुभोदन देने से पूर्व कर्मवारियों को प्रथमा प्रृष्टिकोण स्थब्द करने का युक्तियुक्त प्रवसर देगा।
- 9. यदि भिसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामृहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले प्रमता चुका है प्रधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह छूद रद की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवश नियोजन उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा नियत नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में घसफल रहता है, भीर पालिसी को व्यवगत हो जाने दिया जाता है, तो, छूट रह की जा सकती है।
- 11. नियोगक द्वारा प्रीभियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिकम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह ,छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के प्रतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के प्रधीन माने पाले किसी सदस्य की मृत्यू होने पर उसके हकदार नाम निर्वेशितियों विधिक वारिसों की वीभाइन रकम का संवाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाइन रकम प्राप्त होने के सान दिन के भीतर मुनिश्चित करेगा।

[संख्या एम-35014/245/81-पी०एफ० 2]

New Delhi, the 13th November, 1982

S.O. 4083.—Whereas Messrs DCM Engineering Products Works, Asron, Ropar (PN/5959) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance permia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employers.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund, of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be concelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premimum etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of decessed members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(245)/82-PF.II]

का० आ० 4084.—मैंसर्स तिमलनांडु शूगर केन फार्म कारपोरेशन जिमिटेड वाधापाधियानगलम थंजाबर (टीन एन/7930) (जिसे इसमें इसके पश्चात् जकत स्थापन कहा गया है) ने कर्मवारी भिषय निधि भौर प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके

परकात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपकारा (2क) के अधीन छट दिए जाने के लिए प्रावेदन किया है;

श्रीर केन्द्रीय सरकार का समाझान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक श्रीकवाय या श्रीमियम का संवाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामृहिक बीमा स्कीम के श्रधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं श्रीर ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से प्रधिक श्रनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप महुबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम यहा गया है) के श्रधीन उक्षें श्रनुकेय है;

धतः केन्द्रीय सरकार, उन्त प्रविनियम की घारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रवल गिक्नयों का प्रयोग करने हुए और इससे उपायद धनु सूची में विभिद्धिय गतौं के प्रवीन रहते हुए, उन्त स्थापम को तीन वर्ष की प्रविध के लिए उन्त स्कीम के मभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

- उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्राविशिक भनिष्य निश्च प्रायुक्त समिलनाइ को ऐसी निवरणियां भेजेगा श्रीर ऐसे लेखा रखेगा तथा निरोक्षण के लिए ऐसी मुविधाएं प्रवान करेगा जो केन्द्रीय सरकार ममय-समय पर निविष्ट करे।
- 2. नियोजन, ऐसे निरोक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की आरा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के घंडीन समय-मनय पर निर्दिष्ट करे।
- 3 सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, िक्स अंत्रीन लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुन किया जाना, बीमा प्रीमियम का संवाय, निखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संवाय श्रादि भी है, होने वाले सभी क्यों का बहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।
- 4 नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदिन सामृहिक वीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति भौर जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुमंख्या की भाषा में उसकी, मध्य बातों का अनुवाद, स्थान के सुचना-पट्ट पर प्रथशित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उन्त श्रीधनियम के श्रिश्चेन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही मदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोगक सामू-हिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम सुरस्त दर्ज करेगा श्रोर उसकी बाबत श्रावश्यक प्रोमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संवत्त करेगा।
- 6. यदि उक्त स्कीम के प्रधीन कर्मनारियों को उर्जन्छ फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के प्रजीन कर्मनारियों को उपलब्ध फायदों में मनुष्यत रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मनारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से प्रधिक धनुकूष हो, जो उक्त स्कीम के प्रधीन प्रनुक्षेय हैं।
- 7. सामृहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भो, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीत सदेय रुक्त उन रक्तम में क्षत्र है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उन्त स्कीम के अधीत होता सो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिक्तर के रूप में दोनों रक्तमों के असर के बराबर रक्षम का संवाय करेगा।
- 8. सामृहिक बीमा स्कीम के उपनंत्रों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त नीमलनाहु के पूर्व प्रनुमोदन के बिना नहीं किया प्राएम। घोर जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त, अपना मनुमोदन

देने से पूर्व कर्मकारियों को प्रयमा दुष्टिकोण रूपण्ट करने का युक्तिपुक्त अनुसर देना ।

- 9. यदि (कसी कारणवाम, स्थापत के कर्नचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उन मामृहिक बीमा स्कीम के जिने स्थापत पहले प्रयन्त मुहा है प्रदीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्रापत होने बाले फायदे किसी रीनि से कम हा जाते हैं, तो यह छूट रह की जी सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवन, नियोज्य उस नियत मारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा नियम नियत करे प्रीधेगात का महत्य करते में प्रमक्त रहत, है और पालिसाकी अवनतत्र हो जाने दिया जाना है ती, छूट रह कि जा सकती है।
- 11. नियाजक द्वारा प्रेशिमभम के मदाय में किए गए किसी व्यक्तिकम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामानदींशितिया या निधिक नारिमों की जो यदि यह छूट न की गई हाती का उक्त म्हाम के श्रांति शीर, यात्र फायदी के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. उदय स्थापन के सबस में नियाजन इम स्कीत के अग्रीत प्राप्ति वालि किसी सदस्य की मृत्यु होने पर जाते हरदार नाम निर्देशातया। विशिक्ष वारिनो की बीमाका रजा का मदाय नदरता से और प्रस्थेक दण। में भारतीय जावन बामा नियम में बीपाकन रजन प्राप्त होने के नाम दिन /के मीतर मृति। स्थान करेगा।

[संख्या एम-35014/252/82-पी०एफ०-11]

S.O. 4084.—Whereas Messis Tamil Nadu Sugar Cane Farm Corporation Limited, Vudapathimangalam, Thanjavur. (TN/7930) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act):

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinalter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be boine by the employers.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the sailent features threof, in the language of the majority of the employees.

- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premimum in respect of him to the Life Insurance Corporation of India
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employes, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10 Where, for any reason, the employer fails to pay the premimum etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Coporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nomince flegal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

INo. S-35014(252)/82-PF.II]

का० आ०४।085 --- मैसर्स डेल्टन केवल्स लिसिटेड, 24, दिन्य।गंज मई दिल्ली (डीएल/179) (जिसे इसमें इसके पण्जात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी श्रीवच्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध प्रक्षिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पण्जात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के प्रक्षीन छूट दिए जाने के लिए प्रावेदन किया है,

भीर केन्द्रीम सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सदाय किए जिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की सामुहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा कि म्प में फायदे उटा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों में अधिक अनुकृत है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुजय है;

श्रात. केन्द्रोय सरकार, उक्त श्राधिनियम की धारा 17 की उपधार (2क) द्वारा प्रदक्ष्य शक्तियों का प्रयोग करने हुए और इसमें उपाबंध श्रानुसूची में विनिदिष्ट शर्यों के श्राधीन रहते हुए, उक्त रणायन को तीन वर्ष की सर्वाध के लिए उक्त स्कीम के सभी उपवन्धों के प्रश्तन में छट देती हैं।

अनुसूची

- । उक्त स्थापन के सबन्ध में नियोजक प्रादेणिक भिवास निधि धायुक्त विल्ली को ऐसी विवरणियां भेजेगा धौर ऐसे लेखा रखेगा नधा निरिक्षण के लिए ऐसी मुचिधाए प्रदान करेगा जो केटीय सरकार, समय-समय पर निविष्ट करे।
- 2 नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा 17 की उपधार। (3क) के खण्ड (क) के अर्धन एमय-समय पर निरिष्ट करे।
- 3 सामृतिक कीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके घरतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विघरणिया का प्रस्तृत किया जाना, वीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय प्रादि भी है, होने वाले सभी व्ययों का बहुत नियोजक द्वारा किया जायेगा।
- 4 नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा भनुमोदित मामृहिक बीमा स्कीम के नियमों ना एक प्रति, और जब कभी उनमें संगोधन किया आए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मकारियों की बहुगंख्या की भाषा में उसकी भुक्य बातों का भनुवाब, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या जनन मधिनियम के प्रधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सबस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजिक सामूहिक बीमा स्त्रीम के सबस्य के रूप में उसका नाम तरन्त क्रजे करेगा श्रीर उसकी बाबन भ्रावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदहन करेगा।
- 6 यदि उक्त स्कीम के मधीन नर्मनारियों को उपलब्ध फायदे बहुए जाते हैं तो, नियोजक सामृहिक बीमा स्कीम के मधीन कर्मनारियों को उपलब्ध फायदों में ममुनित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मनारियों के लिए सामृहिक बीमा स्कीम के प्रधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों में मधिक अनुकृष्ण हो, जो उक्त स्कीम के ग्रधीन अनुनेय है।
- 7. समृत्तिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीत गल्देय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में सदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीत होती, तो, तियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनो रकमों के अन्तर के बराबर रक्षम का सवाय करेगा।
- 8. सामूहिक बीमा स्त्रीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भिविष्य निश्चि प्रायुक्त दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया आएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मकारियों के हित पर प्रतिकृष प्रभाव पक्ष्ते को स्तावना हो, वहां प्रादेशिक भिविष्य निधि अध्युक्त, प्रपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मवारियों को अपना वृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देना।
- 9. यदि किसी कारणवण, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा विगम की उस मासूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले घ्रपना खुका है प्रधीन मही रह जीते है, या इस स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हा जाते हैं, तो यह छूट उद्द की जा सकती है।
- 10 यदि किसी कारणवण, नियोजक उस नियम तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा नियम नियत करें, प्रीमिथम का सदाय करने में प्रसंपत्त

- रहता है, स्रीर पालिसी को व्यपगत हो जाने विया जाता है तो, छूट रहद की जा सकती है।
- 1! नियाजक हारा प्रं मियम थे सदाय मे किए गए किसी व्यक्तिकम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जायदि यह छूट नर्दा गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय ना उत्परदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. उनन स्थापन के संबंध में नियोजक, इस सिक्स के श्रशीन श्राने वालि किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियो/विधिक वारिसो की बीमाक्कत रकम का सदाय तत्परता से श्रीर प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बामा निगम से बीमाक्कत रकम श्राप्त होने के सात दिस के भीतर स्तिश्चित करेगा।

[सं० एम०-35014/254/82-पी० एफ-H]

-= _ - - _ . . . _=

S.O. 4085.—Whereas Messrs Delton Cables Limited, 24, Daryagani, New Delhi (DL/179) (heremafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellancous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the emyloyers.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6 The employe; shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the fegal heir/nomines of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employers.
- 12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(254)/82-PF.1]]

का॰ आ॰ 4086:----मैससै जैनेलेक लिमिटेब, जोगेश्वरी इंस्ट, बस्बई (एम॰ एच॰/609) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मेचारी भविष्य विधि धौर प्रकीण उपबन्ध मधिनियम 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चत् छक्त प्रधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के मधीन छूट दिए जाने के लिए भावेदन किया है;

भौर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त त्यापन के कर्मभारी, किसी पृथक प्रभिवाय या प्रीमियम का संवाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रुप में कायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मभारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से प्रक्षिक प्रनुकृत हैं जो कर्मजारी निक्षेप सहवद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पण्यात् उक्त स्कीम कहा गया है) के प्रधीन उन्हें अमुनेय हैं;

श्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त श्रधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रवस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपा-बद्ध प्रनुसूची में विनिधिष्ट शर्तों के के प्रधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की श्रवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट वेती है।

अनुसूची

- उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रावेशिक शिवष्य निधि प्रायुक्त महाराष्ट्र को ऐसी विधरणियां भेजेगा प्रौर ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निविष्ट करे।
- 2 नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येवां मास की समाप्ति के 15 किन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अञ्चनियम की घारा 17 की उपधारा (3क) के आपक (क) के अधीन समय-समय पर निर्विष्ट करें।

- 3 सामृहिक बोमा स्कीम के प्रणासन में, जिसके ग्रन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना- विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, कीमा प्रीमियम का संवाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संवाय आवि भी है, होने वाले सभी व्ययों का बहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोवित नामूहिक बीमा स्कीम के नियमों का एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तया कर्मजारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सुचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।
- 5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भिष्ठष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामृहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरस्त वर्ज करेगा भीर उसकी बाबन आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सदत्त करेगा।
- 6. यदि उनत स्कीम के प्रधीन कर्मधारियों को उपलब्ध कायदे बढाए जाते हैं सो, नियोजक सामृहिक बीमा स्कीम के ब्राग्नीम कर चारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित दय से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मखारियों के लिए सामृहिक बीमा स्कीम के ब्राग्नीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से प्रधिक ब्रनुकूल हो, जो उपत स्कीम के ब्राग्नीन ग्रनुक्रीय हैं।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृथ्यु पर इस स्कीम के प्रधीन सन्देय रक्षम उस रक्षम से कम है, जो कर्मचारी को उस दक्षा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के प्रधीन हीना सो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतीकर के खप में दोनों रकमों के प्रन्तर के बराधर रक्षम का संदाय करेगा।
- 8. सामूहिक कीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई मी संशोधन, प्रावेशिक भविष्य निधि म्रायुक्त महाराष्ट्र के पूर्व मनुमोवन के बिना नहीं किया जायेगा भीर जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृष प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रावेशिक भविष्य निधि म्रायुक्त, म्रपना मनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को म्रपना वृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।
- 9 यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहुले प्रपना चुका है प्रधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के ,ध्रधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं सो वह छूट रवृद की जा सकसी है।
- 10. यदि किसी कारणवंश, नियोजक उस नियन तारीख के भीतर,जी भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संवाय करेंने में प्रसक्त रहता है, धीर पालिसी को व्यपगत ही जाने विया जासा हैं तो, छूट रह्म की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किये गए किसी ध्यक्तिकम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियो या विधिक बारिमों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फाययों के संवाय का उत्तरवायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. उकन स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन झाने बाले किसी सबस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्नेशातियो/विधिक वारिसो की बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से भीर प्रत्येक वशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सक्या एस०-35014/256/82-पी० एफ०-2]

S.O. 4086 — Whereas Messis Genelee Ltd., Jogeshwaii East Bombay (MH/609) thereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellancous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) thereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insulance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Imployees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Covernment hereby exempts the sail establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The emplyer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Lund Commissioner, Maharashta mantain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the sid Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc shall be borne by the employers.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an ostablishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately entol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme apporpriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra und where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give u reasonable opportunity to the employees to explain their points of view
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 1001 GI/82—10

- as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premimum within the due date, as fixed by the Lafe Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members, who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal hens entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. \$-35014(256)/82-PF.[I]

का० आ० 4087 - - मैससं सूजाता टैक्सटाईलस मिल्स डाक्घर नात-जंगड (के एन०/89) (जिसे इससे इसके पण्चात उक्त रक्षापन कहा गया है) ने कर्मचारी भिवाय निधि और प्रकीर्ण उपयन्ध श्रीधिनयम 1952 (1952 का 19) जिसे इससे इसके पण्चास् उक्त श्रीधिनयम नहा गया है की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट विए जाने के लिए श्रीस्टन किया है;

श्रीर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक श्रामिदाय या प्रीमियम का गंदाय किए विना ही भारतीय जीवन श्रीमा निगम की सामृहिक बीमा स्त्रीम के श्रुशीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उटा रहे हैं और ऐसे कर्मचारिया के लिए ये पायदे उन फायदों से श्रीधक श्रुन्तूल है भी कर्मचारी निक्षेप सहबाद बीमा स्व्रीम, 1976 (जिसे इससे उसके पृष्चात् अक्त स्वीम कहा गया है) के अधीन उन्हें श्रुन्त्येय है,

श्रम, सेन्द्रीय सरकार, उबन श्रधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क्) क्षारा प्रदन्त शक्तियों का प्रयाग करने हुए और इससे उपभार अनुसूखी में विनिविष्ट गर्तों के श्रधीन रहने हुए, उदेश स्थापन को नोन वर्ष की श्रवधि के लिए उतन स्कीम के सभी उपवर्धों के प्रवर्तन से छुट दती है।

अमृसुखो

- 1 उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रावेशिक शिवण्य निधि प्राय्यन कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा ध्रीर ऐसे लेखा रखेगा तथा निर्माक्षण के लिए ऐसी सुविधाए प्रदान करगा में केर्न्डाय सरकार, समय-समय पर निर्दिग्ट करे।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक माम की समास्त्रि के 15 दिन के भीतर मंदाय करें जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के प्रधीन समय-समय पर निद्दिष्ट करें।
- 3. सामृहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके श्रन्तर्भन लेखाओं का उच्छा जाना विवरणियों का प्रस्तुन किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का श्रन्तरण, निरीक्षण प्रभागें का मंदाय श्रादि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वाग किया जायेगा।
- 4 नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा धन्मीदिन सामूहिक नीमा स्कीस के नियमों की एक प्रति, सीर जब कभी उन्नमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुमेंच्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का सनुवाद, स्थापन के सूचना-पटट पर प्रदर्शित करेगा।

- 5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जा कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के मधीन छूट प्राप्त कियी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियाजित किया जाता है ती, नियाजिक मामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम सुरुन वर्ज करेगा श्रीर उसकी बाबन मावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम की संदश्य करेगा।
- मर्याद उतन स्कीम के प्रश्लीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बहाए जाने हैं तो नियोजक सामृहिक बीमा स्कीम के प्रश्लीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे में समृजित रप से युद्ध की जाने की व्यवस्था करेगा जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामृहिक बीमा स्कीम के प्रश्लीन उपलब्ध फायदे उस फायदों से प्रश्लिक प्रमुक्त हों, जो उत्तर स्कीम के प्रश्लीन प्रमुक्तिय है।
- ्र मामृहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किसी कर्मक्रियों की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन मन्द्रेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मक्रियों को उस दणा में सदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मकारों के विधिक बारिस/मामनिर्दीशित को प्रतिकर के स्थान रकम का संदाय करेगा।
- श्रामाहिक बीमा स्कीम के उपबन्धी में कोई भी संशोधन, प्रावेणिक भियाप निधि प्रायुक्त कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा थोंग जहां किसी अशोधन में कर्मचारियों के हित पर प्रिक्ति प्रभाव पटन की सप्तावना हो, बलो प्रादेणिक भविष्य निधि प्रायुक्त, प्रपत्ना अनुमीदन देने में पूर्व कर्मचारियों का प्राप्ता दृष्टिकोण स्पाट करने का युक्तियन अवसर देगा।
- ् यदि किसी कारणवण, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन शीमा निगम की उस सामृहिक वीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों की प्राप्त होने बाल कायदे किसी पीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रव्द की जा सकती है।.
- 10 थदि किसी क.रणवण, नियात्रक उस नियम ताराख के भीतर, जो भारतीय जीवन बामा निगम नियम करे, प्रांमियम का सदाय करने में प्रमफल रहता है, थ्रीर पालिसी की ज्यागत हो जाने दिया जाता है थी. छूट रद्द की जा सकर्ता है।
- 1: नियोजक जारा प्रेमियम के सदाय में किए गए किसी व्यक्तियम की द्या में उन मन सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिमों को जी प्रदि यह खूट न दः गई होती तो उक्त स्त्रीम के अन्तर्शत होते, बीमा कायटों के सदाय का उन्तर्रहायित्व नियोजक पर होगा।
- 1.2. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के प्रधीन प्राने बाल किसी सबस्य की मृत्य होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितयों/ विधिक बारिसो की बीमाकृत रकम का सदीय तत्यरता से ग्रीर प्रत्येक वंशी में भारतीय जीवन कीमा निगम से कीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के सीवर मृतिश्वत करेगा।

[सरमा एस०-35014/259/82-पाँ एफ०-II]

S.O. 4087.—Whereas Messis Sujatha Textile Mills, P.O. Nanjangud, Karnatakai (KN/89) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under subsection (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment, are without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE -

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Kainataka, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2 The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employers.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him- as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said' Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premimum within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium etc the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/

legal fers entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum—assured from the Lite Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(259)]82-PF. II]

कार आरं 4088 — मैसर्ज श्री रामालिया मिल्स प्राह्मेट लिमिटेड, 212, रामासामी, तगर, अरुपुकोद्रार्ड-626101 (सिमिल नाडू स्टेट), (टीरु एनं ०/5252) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने समेच्यर अविच्य निश्चि और प्रकीर उपन्त प्रशित्यम, 1952 (1952 का 19 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धार्य 17 की उपधारा (2क्त) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है:

र्जीय केन्द्रीय सरकार का समाधान हा गया है कि उक्त स्थापन ने कर्मकारी, किसी पुश्रक अभिदाय या प्रामियम का सदाय किए जिना ही, अपनीय जीवन बीमा निर्मम की सामृहिक दीमा स्कीम के अधीन जीवन दोमा के रूप में कायदे उठा रहे हैं भीर ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन कायदों से अधिक अनुकृष है जो कर्मकारी निक्षप सहबद्ध दीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुक्षय है;

अर्ष: केन्द्रीय, मरकार उनन मिधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त प्रसित्त का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध मनुसूची मे विनिर्विष्ट गर्ती के भधीन रहते हुए, उनत स्थापन को तीन वर्ष की समिधि के लिए उनन स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से खूट देती है।

अनुसूची

- 1. उत्तत स्थापन के संबंध में नियां जक प्रादेशिक भविष्य निश्चि घायुक्त, निमलनाटु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी मुनिधाएं प्रवान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करें ।
- 2 नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारो को प्रत्येक माम की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सदाय करेगा जा केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की घारा 17 की उपघारा (3क) के खण्ड (क) के प्रधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 3. सामृहिक बीमा स्कीम के प्रमासन में, जिसके प्रस्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवर्णणयों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियन का मवाय, लेखाओं का श्रंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय भौदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का बहुन नियोजक द्वारा किया जाएगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामृहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किए आए, तब उम संशोधन की प्रति तथा कर्मक। रिया की बहुमच्या की भाषा में उसकी मुख्य बाको का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।
- 5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी जी कर्मचारी अधिक्य निधि का या उक्त अधि-नियम के प्रधीन ष्ट्रंट प्राप्त किसी स्थापन की अधिक्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन से नियाजित किया जाता है तो, नियाजक सामृहिक यीमा स्वीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेशा और उसकी बाबत जायण्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा नियम की सदस करेगा।
- 6 यदि उसन स्कीम के अधीन कर्मवारियों को उपलब्ध कायदे बहाए जाने है तो, नियोजक सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मवारियों को उपलब्ध फायदा में समुचिन रूप से बृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मवारियों के लिए सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुक्ल हो, जो उक्त स्कीम के अधीन अनु-जेय है ।
- 7 सामृतिक बीसा स्कीस के किसी बात के होने हुए भी, यदि किसी कमेचारी की मृत्यु पर इस स्कीस के प्रधीन संदेय रक्तम उस रक्षम से कम है

जा कर्मचारी को उस दक्षा में सर्देय होंती जब वह उक्त स्कीम के प्रधीत होता तो, तियोजक कर्मचारी विधिक वारिस/नाम निर्देणिसी को प्रथिकर के रूप में दानों रकमों के श्रतर के बराबर रकम का संदाय करेंगा ।

- ४ सामृहिक जीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई मी संगोधन, प्रादे-गिक भविष्य निधि प्रायुक्त, तिमलनाइ के पूर्व धन्मोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संगोधन से कर्मपानियों के हित पर प्रति-कृल प्रनाव पड़ने की सनावना हो वहां, प्रादेशिक सविष्य निधि प्रायुक्त प्रपत्ता धन्मोदन देने से पूर्व कर्मणारियों को प्रपत्ता दृष्टिकीण स्पष्ट करने का यक्तियक्त प्रवसर देशा ।
- 9 यदि किसी कारणवंश, स्थापन के कर्मवारों, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामृद्धिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या उस स्कीम के अबीन कर्मवाशियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रोति से कम हो जाते हैं, तो यह रह की जा सकती है ।
- 10 यद्भिकिमी कारणवश . नियंशिक उस नियंत तारीख़ के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा नियम नियम करे, प्रोमियय का संदाय करते में ग्रमफल रहता है, ग्रार पालिसी को व्यवगत हो जाने दिए जाता है तो, छूट रह की जा सकती है ।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाध में किए गए किसी व्यतिकम की दणा में, उन मृत मदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों की जो, यदि छूट न दी गई होती तो उनत स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदी के संवाय का उत्तरवायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. उन्तर स्थापन के सबध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी मदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/ विधिक बारिसी की बीमाकृत रकम का सदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के मात दिन के भीतर मुनिष्चित करेगा ।

[सं॰ एस-3501 1/437/82-पी॰ एफ॰-LI]

S.O. 4088.—Whereas Messrs Shri Ramalinga Mills Private Limited, 212, Ramasamy Nagar, Aruppukottal-626101 (Tamil Nadu State) (TN|5252) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contributions or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereipafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said. Act, within 15 days from the close of every month.

- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir nominee of the employee as compensation,
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(437)[82-PF. II]

कार आहे. 4089:— मैससे माडमें बेकरीज (बाई) लिमिटेड प्रदीयार महास-(टी० एत/10387), (जिसे इसमें इसके पश्चात एकर स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि भीर प्रकीर्ण उपबन्ध मधिनियम, 1952(1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उकर मधिनियम कहा गया है) की धारा 17 भी उपधारा (2क) के बाबीन छट दिए जाने के लिए भावेदन किया है;

भीर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्ने-चारी, किसी पृथक ऋभिदाय या प्रीमियन का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा की सामृहिक सीमा स्कीम के ख़बीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है ग्रीर ऐसे कमैत्रारियों के लिए ये फायदे उर फायदों से प्रधिक श्रमुकूल है जो कमैत्रारी निक्षेप सहबद्ध दीमा स्नीम १५०० जिसे इससे इसके पण्नान उपन स्कीम कहा गया है) के श्रधीन उन्हें श्रमुक्त रहें,

मित केन्द्रीय सरकार, उनन प्रधिनियम की धारा 12 को उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त णिक्तयों का प्रयोग करने हुए और इसमें उनाबद्ध भनुसूर्वा में विनिर्दिष्ट गर्नों के प्रधीन रहते हुए उक्त स्थापन का तान वर्ष की प्रवर्ध के लिए उक्त स्थीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन में छूट देती है।

अनुसूची

- 1 उक्त स्थापन के सबंध में नियोजक भविष्य प्रोदणिक निश्च प्रायुक्त, मद्रास को ऐसी विवरणिया भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा तिराशण के लिए ऐसी सुविधाए प्रवान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-गण्य पर निविष्ट करे।
- 2. नियाजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाधित के 15 दिन के भीतर संदाय करना जो केन्द्रीय सरकार, उक्त भीजीतपम की धारा 17 की उपधारा (अक) के खण्ड (क) के प्रधीन समय-पसय पर निरिष्ट करें ।
- 3 सामृहिक बीमा स्कीम के प्रणासन में, जिसके प्रन्तर्गत लेखाणे का रखा जाना, विवरणियो का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियस का नंदाय, लेखामो का मतरण, निरीक्षण प्रभारा का सवाय आदि भी है, होने कर ने सभी क्यायों का वहन नियोक्षण द्वारा किया जाएगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय मरकार द्वारा धनुमोदित सामृहिक बीमा स्काम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, जब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुमख्या की साथा में उसके मुख्य बातों का धनुवाद, स्थापम के मुचना पट्ट पर प्रवीगत करेगा।
- 5. यदि काई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निश्चिका पर उतन प्राधिनियम के प्रधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निश्चिका एक प्रश्नि स्थापन के सविष्य निश्चिका है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, रियोजिक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप मे उसका नाम तुरन्त दज करेगा धौर उसकी दावत धावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगंध का संदत्त करेगा।
- 6 यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मकारियों को उपलब्ध फायदे बढाए जाने हैं तो, नियोजक माम्हिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उप-लब्ध फायदों में समुखिल रूप में बृद्धि की जाने की ब्यवस्था करिया जिससे कि कर्मचारियों के लिए मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों ने अधिक अनुकूल हो, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुहोय है।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के झदीन सदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेश होती जब वह उकर स्कीम के झदीन होता तो, नियाजक कर्मकारी के विशिक्ष वारिम/नाम निर्देशिकों को प्रिमिक्त के कप में वानों रकमों के अन्त्र के बराबर रकम के सदाय करेगा ।
- 8. सामृहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में काई भी संगोधन , प्रादेशिक भिविष्य निधि प्रायुक्त, महाम के पूर्व प्रतृभादन के बिना नहीं किया नाएगा और जहां किसी संगोधन में कर्मवारियों के हिन पर प्रतिकृत प्रभाव उड़ने की संभावना हो वहां , प्रादेशिक भिविष्य निधि प्रायुक्त, प्रपत्ता मनुमोदन देने में पूर्व कर्मचारियों को प्रपत्ता कृष्टिकीण स्थष्ट करने का युक्तियुक्त प्रवस्त देगा ।
- 9 यदि किसी कारणवा, स्थापना ने कसंवारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामृहिक बीमा स्कीम के, जिससे स्थापन पहले श्रपना जुका है धन्नीन नहीं रह जाने हैं, या इस स्कीम के प्रवीन कर्मवारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाने हैं, तो बह रह की जा सकती है ।

10: यदि:, क्रिक्स कारपावण, नियोजक उस नियत नारी ख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, घ्रीमियम का संदाय करने में प्रमुक्त है, घोट पालिमी का व्यवसाद द्वां जाने दिया जाता है ती, खुष्ट रहे की जा सकती है।

_== _- -- -- -- ----

- 1. नियाजक द्वारा प्रीमियम के सदाय में फिए गए किसी व्यक्तित्रम की द्वारा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विश्विक वारिसों का जा, यदि यह छूट न दो गई होनी तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, अस्ति फायदों के सदाय का उत्तरदायित्व नियाजक पर होगा।
- 12 उन्त स्थापन के संबक्ष में नियंजिक, इस स्कीम के श्रक्षीत श्रान किसी किसी सवस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक बारिसों को श्रीमाकृत रकम का सवाय तत्तरता से श्रीर प्रत्येक वंशा में भारतीय अधिन श्रीमा निगम में नीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीनगर सुनिश्चित करेगा ।

मिक एम०+35014/438/82-पीकएफक::}

S.O. 4089.—Whereas Messrs Modern Bakeries (I) Limited, Adyar, Madras-20 (TN/10387) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act. 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act):

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contributions or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Link Insurance Solieme, 1976 (hereinatter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner. Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc shall be borne by the employers.
- 4. The employer display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Solome as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund of the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary prominum in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available 1001GI/82—11

under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme

للمن الأراب المنظم الأرافيات المنظمين ال<mark>قيار الش</mark>ماليين الإي

- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insutance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employee shall pay the difference to the legal heirmominee of the employee as compensation.
- 8 No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life-Insurance Corporation of India as already adopted by the sail establishment, on the benefits to the employers under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premimum within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(438)[82-PF. II]

कार आर 40.90.— मैसर्न केर एसर श्रीर पस्पम लिसिटंड, बोम्बे-पूर्ता रोडे, प्ना-411018 (एस ए/6471), (जिसे एसमें इसके पर्ण्यात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मकारी अविषय निधि और प्रकीण उपबन्ध श्रीधिनियम, 1952 (1952 का 10) (जिसे इसमें इसके पर्ण्यात् उक्त श्रीधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए धायेदन किया है;

शौर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, शारतीय जीवन बीमा निगम की सामृहिक कीमा स्वीम के अर्धन जीवन बीमा के रूप में फायदे उटा रहे है शौर ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से शांधक अनवृत्त है जो कर्मचारी निलेप सहबज्ज बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पण्चान् उक्त स्कीम कहा गया है) के प्रधीन उन्हें अमृज्ये हैं ,

भ्रत केन्द्रीय सरकार. उक्त प्रधिनियम की धारा 17 की उपक्षारा (2क) द्वारा प्रवल पक्तियों का प्रयोग करते हुए उपावद ध्रम्भूकी में विनिर्दिष्ट गर्कों के अर्धान रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ध की श्रवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उमबस्धों के प्रवतन में छूट देती है।

अनुसूची

- ा उक्त स्थापन के सबंधु में नियोजक प्रावेशिक भाविष्य सिंध भ्रायुक्त, महाराष्ट्र को ऐसी विश्वरणियां भेजेगा भ्रीर ऐसे लेखा रखेश तथा निर्देशण के लिए ऐसी सृविधा प्रदेन करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्देश्ट करें।
- तियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सवाय करेगा जा केन्द्रीय सरकार, उत्तर प्रधिनियम की

भारा 17 की उपभारा (3क) के खण्ड (क) के ग्रधीन समय-समय पर निविष्ट करें।

- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके धन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीनियम का संदाय, क्षेखाओं का धंतरण, निरीक्षण प्रभारोक्षा संवाय धादि भी है, होने वाले सभी क्यां का वहन नियोजक द्वार। किया जाएगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रनुमोदित सामृहिक भीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, घौर जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संगोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का धनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रविधत करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मकारी, जो कर्मकारी भविष्य निधि का या उक्त मधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदक्त करेगा।
- 6. यदि उक्त स्कीम के भ्रश्लीन कर्मवारियों को उपलब्ध कायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मवारियों को उपलब्ध कायदों में समृबित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मवारियों के लिए सामृहिक बीमा सकीम के भ्रधीन उपलब्ध कायदे उन कायदों से अधिक भ्रमृकृत हों, जो उक्त स्कीम के भ्रधीन भ्रमृत्तिय हैं।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के प्रधीन संवैय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दणा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के भ्रधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिविधिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के भ्रंतर के बराबर रकम का संवाय करेगा।
- 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भिवव्य निधि मायुक्त, महाराष्ट्र के पूर्व भनुमीवन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संजोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पढ़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि भायुक्त, भपना मनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को ग्रंपना दृष्टिकीण स्पष्ट करने का प्रकित्युक्त अपना दृष्टिकीण स्पष्ट करने का प्रकित्युक्त अपनर देगा।
- 9 यदि किसी कारणवश, स्थापना के कर्मकारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले भपना कुका है भक्षीन नही रह जाते हैं, या इस स्कीम के भ्रधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने बाले फायरे किसी रिति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती हैं।
- 10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में मसफल रहता है, तो पालिसी को व्यपगंत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रह की जा सकती है।
- 11- नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किए गए किसी व्यक्तिकम, की बशा में, उन मृत सवस्यों के नाम निर्वेशितियों या विश्विक वारिसों को जो, यवि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के धन्नगैत होते. बीमा कायवों के सवाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा 1
- 12. उक्त क्यापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सबस्य की मृत्यु होने पर उसके हकवार नामनिर्देशिनियों | विधिक वारिसों को बीम इत रक्षम क. संवाय तत्परता से और प्रत्येक वशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाइत रक्षम प्राप्त होने के सात विन के भीतर मुनिष्चित करेगा।

[सं॰ एस-35014/439/82-पी एफ-2]

S.O. 4090.—Whereas Messrs K. S. B. Pumps Limited, Bombay, Poona Road, Pimpri, Puna-411018 MH/6471, (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government i₃ satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contributions or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life insurance which are more favourable to such employees than the benefit₃ admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Maharashtra, maintain such accounts and provide for such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including Maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employers.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Where the employee, who is already a member of the Fmployees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said scheme, the employer shall pay the difference to the legal helr/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment, or the benefits to

the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is hable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would, have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(439)/82-PF, II]

कां आर 4091 --- मैसर्स वी कर्नाटका है दी डिविलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड, हसन हेरी, पार्क रोड, बंगलोर (कें मनः | 6736), (जिसे इसमें इसके पश्चात उकत स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविषय निधि भीर प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनयम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट विए जाने के लिए धावेदन किया है;

धौर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उनत स्थापन के कर्मनारी, किसीपृथक धिवाय या प्रीमियम का संवाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के ध्रश्वीन जीवन बीमा के रूप में कायवे उठा रहे हैं धौर ऐसे कर्मनारियों के लिए ये कायवे उन कायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मनारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उचत स्कीम कहा गया है) के प्रधीन उन्हें धनुश्चेय हैं ;

मत: केन्द्रीय सरकार, उनत मधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) धारा प्रवत्त प्रक्तियों का प्रयोग करते हुए भीर इससे उपाव्य मनुसूची में बिनिधिन्ट शतों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उनते स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छट वेती है।

अनुमुखी

- उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रावेशिक भविष्य निधि भायुक्त कर्नाटका को ऐसी विवरणियां घेजेगा भीर ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निरिष्ट करे ।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त घिधिनियम की भ्रारा 17 की उपघारा (3क) के खण्ड (क) के घिधीन ममय-समय पर निर्दिल्ड करें।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रणासन में, जिनके धन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संवाय, लेखाओं का धनरण, निर्दाक्षण प्रभारों संवाय प्रावि भी है, होने वाले सभी क्यया का बहुन नियोजक द्वारा किया जाएगा।
- 4 नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा ग्रमुमोदिन मामूहिक बीमा रकीम के शियमी का एक प्रति, भीर जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मजारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मृज्य वानों का श्रमुखाद, स्थापन के सूचमा-पट्ट पर प्रवर्धित करेगा।

- 5. यदि कोई ऐसा कर्मकारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या जनत अधिनयम के अधीन भूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सवस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजिक मामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरस्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत प्रावण्यक प्रीमियम भारतीय जोवन बीमा निगम को संबक्त करेगा।
- 6. यदि उनत स्वीम के प्रधीन कर्मवारियों को उपलब्ध कायदे बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामृहिक बीमा स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों की उपलब्ध कायदों में समुचित रूप से घृद्धि की जातें की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामृहिक बीमा स्कीम के प्रधीन उपलब्ध कायदे उन फायदों से प्रधिक धनुकूल हों, जो उनत स्कीम के प्रधीन प्रमृ-श्रीय हैं।
- गः सामृहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के मधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी की उन धशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के मधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्वेशिती को प्रतिकर के क्य में दोनों रकमी के मंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।
- 6. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संघोधन, प्रावेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त, कर्गाटका के पूर्व प्रतुमोदन के जिना महीं किया जाएगा भीर जहां किसी संघोधन से जर्मनारियों के हिंत पर प्रतिकृष्ण प्रभाव पढ़ने की संभावना हो बहुा, प्रावेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त, अपना प्रतुमोदन देने से पूर्व कर्मनारियों को प्रपत्त वृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त प्रवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवण, स्थापन के कर्मकारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले भपना चुका है धाधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के भाधीन कर्मेकारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, सो यह रद्द की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवय, नियोजक उस नियत कारीख के भी तर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में भसकत रहता है, भीर पालिसी को व्यवगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रज्ब की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमिथम के संदाय में किए गए किसी व्यतिकार की दशा में, उन मृतसदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो, यदि यह छूट न वी गई होती सी उक्त स्कीम के भन्तगंत होते, बीमा फायदों के संदाय का उस्तरदायिस्व नियोजक पर होगा।
- 12, उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के प्रधीन ग्राने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकवार नामनिवंशितियों/विधिक वारिसों की बीमाकृत रकम का संवाय तत्परता से ग्रीर प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा नियम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर मुनिश्चित करेगा।

[सं॰एस-35014/442/82-पी॰एफ-2] ए॰ के॰ भट्टराई, शवर संचिव

S.O. 4091.—Whereas Messrs The Karnataka Dairy Development Corporation Limited, Hassan Dairy, Park Road, Bangalore (KN/6736), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contributions or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than

the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked insurance Scheme, 1976, (hereinalter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Covernment hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULL

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Bangalore, maintain such accounts and provide for such facilities for inspection, as the Central Covernment may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3.A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Where the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance. Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner. Karnataka and Macie any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employee, of the said establishment do not remain envered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already dopted by the establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the empoyer fail, to pay the premium within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of detailt, it my made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would, have been covered under the said Schome but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal-heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(442)/82-PF.II] A. K. BHATTARAI, Under Scoy. वर्ड दिल्ली, 13 नवम्बर 1982

्काल्काल 4092 ---नेत्रीय सरकार प्रभव खान अन कल्याण निश्चि अधिनयम, 1946 (1946 का 22) की धारा उनी उत्थारा (1) के अनुसरण में 31 मार्फ, 1982 को समाप्त होते वाल वर्ष के दौरान ब्राधक खान अस कल्याण निश्चि में बित्त-पोणित किशाकनामें न्की निम्मिक्षित रिपोर्ट उस वर्ष के लेखा विवरण कथा उन्त निश्चि के वर्ष 1982-83 की प्राप्तियो और स्पर्धों के प्राक्तिन महित अक्शिक-कर्ती है।

श्लीग-।

() सामान्ध

भागक चान श्रम कल्याण निधि का गठन प्रभाव चान श्रम कल्याण निधि प्रविनियम, 1946 (1946 का 22) के प्रयोग अञ्चल खान उद्योग में नियोजिक श्रीमको के कल्याण में मंबीधन क्कीमों के विस्त पोषण के लिए किया गया है।

अधिनिसम में, निर्यात की गई सभी अभ्रक पर मृत्यान्सार सवा छ प्रतिणान की अधिकतम वर पर सीमाणुल्क के उद्यह्म क लिए उपलब्ध किया गया है 2 उपकर की दर, जो कि पहने मृत्यानुसार 2ई प्रतिभत की, 15 जुलाई, 1974 में 31/3 प्रतिणत नक बढ़ा दी गई। संग्रहणों का प्रामटन विभिन्न प्रभंक उत्पादन करने वाल क्षेत्रों में उनके ग्रीसत उत्पादन के प्रतुपान में कल्याणकारी उनायों में समित व्या के लिए किया जाता है।

APT7~ 2

क्यबस्थितः मुविधार्

(क) चिकित्साः

अध्यक खान श्रम कत्याण सगठन द्वारा प्रभन्न श्रमिको ग्रीर उनके साथियों के लिए विधिनन प्रकार की निकित्ता सुविधायों की लिए विधिनन प्रकार की निकित्ता सुविधायों की लिए कुछ क्यवस्था की जाती है उनके अन्तर्भन अस्पतालो, प्रसूति एव शिष्मुक कल्याण केन्द्रों का प्रावधान और अनुप्रकण गृहोपचार सहित क्षयरोग के उपवार की मुविधाए, अध्युवेदिक श्रीष्ट्रालय सहित भौषधालय संवाए श्रीर अन्य सुविधाए शामिल है। रिपोर्ट से सबंधित वर्ष के बीरान अभिक खितको श्रीर उनके भाषित्रों के उपवार के लिए कल्याण सगठनो द्वारा निक्तिलाक्षित केन्द्रीय भया क्षेत्रीय अस्पताल क्षत्राए जाने रहे:----

ऋम सख्या	अस्पताल का नाम	प संगों की स्संख्य ।
1	केन्द्रीय अन्यताल, कमी (बिहार)	100
2	केम्द्रीय अस्पताल, गंगापुर (राजस्थान)	3 0
3	केन्द्रीय घरूपताल, कालीचेडु (द्वास्त्य प्रदेग)	30
-1	भौक्षीय अस्पनाम, सिमरी (बिहार)	30
5	क्षेत्रीय अस्पताल, तालपुर (आम्ध्र प्रवेश)	10
6	केन्द्रीय भस्पताल, कालीबेडु (ब्रान्ध्र प्रदेश)	20
	से सलग्न क्षयरनेंग बार्ड	
7	क्षयरोग भ्रम्यताल, कर्मा, बिहार	50
8	क्षेत्रीय धम्पनाल, मध्वाप्रम	10 (भाहार के
		साथ)

क्रमके अलावा अभ्रक उत्पादन करने वाले तीन राज्यों में निम्नितिश्वित ग्रम्थ प्रकार के चिकित्सा संस्थान भी लगातार कार्य करने रहें :--

विकित्स। मन्यान का नाम	आश्व प्रवेग	विहार	राजस्थान	ক্ৰ
 एसोपेथिक श्रीवद्यालय		5	3	7 ^{3 6}
मा क्षें(द क स्रोप धालय	2	8	4	14
प्रसृति भौर शिशु कल्याण केन्द्र	3		3	G
चलते-फिरतं चिकित्सालय एकक	1	3	. 2	6
होस्योपैधिक एकक	1		-	1
सब् समुदाय येन्ट		5	-1-	5

^{*}भ्रात्म्य प्रवेश में एक एखो**पैश्विक भीवधाल**य को 1-9-80 से केचीय अस्पताल, -कालीचेकुंके याथ मिला विवा गया है।

क्षण्याण मगठन अयरोग से पीडित कानिकों के उक्कार के जिए प्रयाणि मुक्काओं की व्यवस्था करने के प्रयास करने। रहा। अयरोग अस्पनानी भीर क्षिणिकों की स्थापना के प्रयास करने। रहा। अयरोग अस्पनानी भीर क्षिणिकों की स्थापना के प्रयास करने के लिए अयरोग सैनेटीरियम, मदार (अजकेर) में चार पर्लग आरक्षित किए गए। इसके भितिरकत, इस प्रयासन के लिए केन्द्रीय अस्पतान गतापुर में 10 पर्लगों के अस्प बार्ड हैं। कल्याण निध अयरोग और छाती के रोगों के सरकारी अस्पतान, नैन्धीर में चार पर्लगों का वेवल अभक चिनकों भीर उनके परिवारों के प्रयोगके लिए आरक्षण जारी। रहा।

क्षत्ररोग के ऐसे रोगी को 9 माम की प्रविधित्तक के लिए 50 स्पये प्रितिमाम का निर्वाह भक्ता दिया जाता है, यदि बहु परिवार के लिए स्वयं निर्माने बाला सदस्य हो। प्रालोच्य क्योर्ट की प्रविधि के वौरान बिहार, में 32 मरीजों, राजस्थान में एक मरीज को निर्वाह भन्ता मजूर किया गया। बिबिध विकिस्सा सुविधाए:

षातक हुर्बेटना लाभ योजना के क्षत्तर्यत, निधि ने व्यक्ति की परली को 250 क्ष्में की अब 500 रुपये नक संजीधित एक मृश्त भवायनी और पांच वर्ष की अवधि के लिए देय 25 रुपये प्रतिमास के भती की अदायनी भीर प्रत्येच क्ष्में क्ष्में के लिए उसके 15 वर्ष के क्षीने कक्ष्म या विवाह करने तक, जो भी पहने हो, 15 रुपये की मासिक छान्नवृत्ति की अवधिनी के रूप में विक्तिय सहायना देना जारी रखा।

श्रालोभ्य रिपोर्ट की श्रवधि के दौरान इस योजना के श्रन्तर्गत भीलवाड़ा राजस्थान में दो मामलो में 600 ध्यमें और कर्मा (बिहार) में मृतको के दो श्राश्यिनों को 700 ध्यमें की रिशा का खुगतान किया गया।

तेहुलमारी कोव प्रस्पताल में कोव से पीड़ित बिहार के अश्वक खिनकों के उपकार के लिए क्यवस्था जारी रहीं। कैंसर में पीडित प्रश्नक खिनकों के उपकार के लिए केन्द्रीय प्रस्पताल कन्न्ना (प्रास्तत्वोल) ग्रीर राजी में काके में मानस्था रोगों के प्रस्पताल में भाग्तिक रोगों से पीडित खिनकों की उपकार क्यवस्था जारी रहीं। कैंसर से पीड़ित ग्रंभक खिनकों के उपकार की प्रजान के प्रकार करानाल में पत्रंगों के भारकाणों की धतुमित जी गई है, जिसमें सामान्यत 9 माम से प्रवाधिक ग्रंबधि के लिये मुक्त उपवार की व्यवस्था की गई बीर कुछ थायवार वाले मामलों में यह प्रविधि भाम से पिछका हो। सकती है, यदि उपवार कर रहे जिनस्सा प्राधिकारी ऐसा व्यवस्था की गई बीर कुछ थायवार कर रहे जिनस्सा प्राधिकारी ऐसा व्यवहार है।

ऐसे रोगी, जिन्हें हुए प्रावन नहीं है, क्षणक श्वान श्वम करवाण संगठन हारा चलाए जा रहे प्रसानानों में उपनार भी प्राप्त करते हैं। उनके उपनार के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निधि सगठनों को महायक भनुदान दिया जाता है। प्रश्नक जान श्वभिकों को 30 दायी प्रति जोड़ा ऐनक श्राधिक नाग (पर के के नागर्ध की जाती है।

(ब) शिक्षा और सनोरंजन सुविधाएं:

सक्षक अभिकों चीर उसके आश्रियों को जिला चीर मनोरण ए विश्वाधों की स्थवस्था करने के लिए, कल्याण संगठमों द्वारा बहुव्येषीय संस्थान जलाए जाते हैं। प्रत्येक मस्थान में एक प्रौद शिक्षा केन्द्र घीर एक रहिना कल्याण केन्द्र जामिल है प्रौद जिला कार्यक गांग का सिस्तान करने हेनु कल्याण संगठन ने सहायक घीर प्रौद जिला केन्द्र भी खोले हैं। मनोरजन के प्रयोजनार्थ प्रश्नक खनन केन्द्रों में रेडियों सेट स्वापन किए गए हे घीर प्रश्नम श्रम कल्याण संगठन के प्रवर्गत मनोरंजन बनव, पुरन्कालय ग्रीम रिविंग कक्ष कार्य रहे हैं। शिक्षा सुविधाधों की व्यवस्था करने हेतु कल्याण संगठनों द्वारा प्राथमिक स्कूल/मिडिल स्कून/हाई स्कूल खलाए ज्या रहे हैं। इन सुविधाधों की व्यवस्था करने वाले संस्थामों की संख्या इस प्रकार है

न म ा व	संस्थाओं का भ्योत	ग्रानध प्रदेश		बिहार	राज- स्वान	कुल
i	2	3		4	5	6
1.	बहुद्देणीय संस्थान (प्री णिक्षा केन्द्र भीर महिलाकल					
	केल्द्र सहित)	· -	-	9	5	1 4
2	प्रीवृ शिक्षा केन्द्र	. ~			7	7
3	प्राइमरी/प्रारम्भिक स्कूल		4	3*		7
4,	मिडिल स्कूल .	, -		(4)*	*	4
5.	हाई स्कूल		2	1		3
6.	सहायक केन्द्र			1		1
7.	खनिकों के बक्को के लिए	ŗ				
	छात्रावास/होस्टल .	•	2	(4)*	1	-,
8.	चलते फिरते सिनेमा एकक		1	3	1	
9.	विभागीय रेबियो सेट		20	16	8	4.
10	मनोरंजन ग लब .		h 4			14
11.	भजन मंबली		- 9	9		1.6
12.	पुस्तकालय ग्रीर वाचनालय			15	10	2 8

^{*1-10-1981} से राण्य सरकारो को हस्तांरित।

चलते फिरते सिनेमा एकक के साध्यम से ग्रीक्षक एवं धार्मिक महुस्व की फिल्में दिखाई जाती हैं।

स्कूली और कालेजों में प्रभंक चानिकों के प्रदे पुत्रों/पुत्रियों के प्रभ्ययन के लिए छात्रवृत्तियां दी जाली है।

अभ्रक चिनिकों के लिए मनीरंजन की व्यवस्था करने के लिए समय-ममय पर चेल-कृद आयोजिल किए जाते हैं और विजेताओं को पुरस्कार दिये जनते हैं।

(ग) पेय कल की मुक्कियाएं

प्रकार अनत असे में पैय जल की असी एक विस्कालिक समस्या है। इस अमस्या को हुन करने के लिए कुएं खोदने की एक योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना के प्रत्यांत प्रमुमानित लागत का 75 प्रतिकृत या वास्तविक लागत का 75 प्रतिकृत जो भी कम हो, मालिकों को कुएं खोदने के लिए दिया जाता है। ग्रान्ध प्रदेश में कालीबेडु गांच में एक स्भायी जल प्रदास योजना चल रही है। प्रभी तक भासा ब्रदेश में 26 कुओं और राजस्थान क्षेत्र में 16 कुओं को खोदा गया है। नुकारवान क्षेत्र में 47 कुओं की सरम्मम की गई है।

^{***}चार में में तीन को पहले ही राज्य सरकार को हस्तातरित किया। गया है।

^{***}एक में समामेलित।

(च) जावास

दो भ्रायास योजनाएं भर्मात् भ्रपना मकान बनामो योजना भीर टाइप-। भ्रायाम योजना (कम लागत भ्रायाम योजना) चल रही है।

श्रपना सकान बनाओं सोजना के श्रन्तर्गेन श्रासेक सकान के लिए 1500 रुपये की बिलीय सहासना का भूगनान किया जाता है (600 रुपये श्राधिक महासता के रूप में और मासिक किस्तों में किना ब्याज के रूप में 900 रुपये, जो नौ नर्प से श्रनिश्चिक भवधि में बसूल किए जाएंगे) इस मोजना के भन्तर्गेश सब तक 718 मकामों को पूरा किया जा मुका है।

टाइप-1 घाणास योजना के झन्तर्गत, साधारण क्षेत्रों में मानक अनु-मानित लागत का 75 प्रतिशत है, जो 6825 देपये हैं और कपास पैदा करने जाजी काली या उभरी हुई भूमि जाजे क्षेत्रों में 7825 रुपये या मकानों के निर्माण की धास्त्रिक लागत का 75 प्रतिशत इनमें जो भी कम है, धार्षिक सहागता दें जाती है। कार्य घादेश जानी होने के साल जान प्रजन्मकों को झार्थिक सहायता का 20 प्रतिशत अगिम रूप में दिया जाता है। इस योजना के झन्तर्गत स्रव तक 72 मकानों का निर्माण किया भा जुका है।

इससे पूर्व विभागीय कालोनी योजना के प्रन्तर्गत 98 मकान प्रीर प्राधिक सहायता प्राप्त धावास योजना के प्रन्तर्गत 12 मकान बनाए गए थे। शावास कार्यक्रमों की भनि को तेज करने के लिए ग्रीर योजनाधों को धाधिक प्राकृषित बनाने के लिए एक धावास उप गर्मित गठित को गई थी, जिसने धपनी रियोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इसकी मंत्रालय में जांच की जा रही है।

सॉग-- 3

वर्ष 1981-82 की ज्ञाप्तियां और व्यय इस प्रकार हैंं '---प्राप्तियां

पहली श्रप्रैल, 1981 को सदशेष	1,92,29,453.88
बर्ष 1981-82 के दौरान प्राप्तिया	1,16,93,000.00
भर्व 1981-82 के दौराम व्य य	84,91,824.00
3 । मार्च, 1982 को भन्त क्षेत्र	2,24,30,629.88

भाग--- 4

सर्वे 1982-83 के लिए अनुमानित प्राप्तियां और व्यय

बजट बनुमान		(मपये	ला कों	में)
प्राप्तियां			100	00
ध्यय े			92	9.5
	ि सररा	अं ड -16016/1/82-एस०-3/	ब्राह्म व	-21

द्वीर श्रीय सरकोक्षा, भवर सचिव

New Delhi, the 13th Nov., 1982

S.O. 4092.—In pursuance of Sub-Section (4) of Section 3 of the Mica Mines Labour Welfare Fund Act, 1946 (XXII of 1946) the Central Government hereby publish the following report of the activities financed from the Mica Mines Labour Welfare Fund during the year ending 31st March, 1982 together with a statement of accounts for that year and an estimate of receipts and expenditure of the said fund for the year 1982-83.

PART-I

General

The Mica Mines Labour Welfare Fund has been constituted under the Mica Mines Labour Welfare Fund Act, 1946, (22 of

1946) for financing schemes relating to the Welfare of labour employed in the mica mining industry.

2. The Act provides for the levy of a duty of customs; on all mica exported, upto a maximum rate of 6-1/4 per cent ad-valorem. The rate of cess, which was 2-1/2 per cent ad-valorem previsouly, has been increased to 3-1/2 per cent with effect from the 15th July, 1974. The collections are allocated for expenditure on welfare measures among the various mica producing areas in proportion to their average production.

PART-II

Facilities provided

A. Medical

Various types of medical facilities for mica workers and their dependents are provided free of cost by the Mica Mines Labour Welfare Organisations. These include provision and maintenance of hospitals, maternity and child welfare centres, facilities for treatment of T.B. including domiciliary treatment dispensary services including Ayurvedic dispensaries and other facilities, etc. The following Central and Regional hospitals continued to be maintained by the Welfare Organisations for the treatment of mica miners and their dependents during the year under report:—

Sl. Name of the Hospitals No.	Bed Strength
1. Central Hospital, Karma (Bihar)	100
2. Central Hospital, Gangapur (Rajasthan)	30
3. Central Hospital, Kalichedu (Andhra Pradesh)	30
4. Regional Hospital, Tisri (Bihar)	30
5. Regional Hospital, Talupur (Andhra Pradesh)	10
 T. B. Ward attached to Central Hospital, Kalichedu (Andhra Pradesh). 	1 20
7. T. B. Hospital, Karma, (Bihar)	50
8. Regional Hospital, Sydapuram	10
	(Dietary)

In addition, the following other medical institutions also continued to function in the three mica producing States.

States :

Medical Institutions	Andhra Pradesh	Bihar	Rajas- than	Total
Allopathic Dispensaries		5	3	* 7
Ayurvedic Dispensaries	2	8	4	14
Maternity and child wel- fare centres.	3		3	6
Mobile Medical Unit	1	3	2	6
Homoeopathic Unit	1		_	1
Small Community Centres		5	— .	5

One Allopathic Dispensary in A. P. region has been merged with Central Hospital, Kalichedu w.e.f. 1-9-1980.

The Welfare Organisations have been endeavouring to provide adequate facilities for treatment of the miners suffering from T.B. Apart from setting up of T. B. Hospitals and clinics, four beds remained reserved at T.B. Sanatorium, Madar (Ajmer), for providing specialized treatment to mica miners suffering from T.B./Sillcosis. Besides, there is a 10 bedded segregated wards in the Central Hospital, Gangapur, for the purpose. Four beds in the Govt. Welfare Fund T.B. & Chest Disease Hospital, Nellore, continued to be reserved for the exclusive use of mica miners and their families.

A subsistence allowance of Rs. 50 per month is granted to a T.B. patient for a period upto 9 months where he happens to be the only earning member of the family. During the period under report 32 patients in Bihar, one patient in Rajasthan were sanctioned Subsistence Allowance.

Miscellaneous Medical Facilities

Under the Fatal Accident Benefit Scheme, the Fund continued to provide financial assistance to the spouse of a miner in the form of a lumpsum payment of Rs. 250/- (since revised to Rs. 500/-) and a monthly allowance of Rs. 25/- payable for a period of five years and a monthly scholarship of Rs. 15/- payable in respect of each school going child till he/she attains the age of 15 or is married, whichever is earlier.

During the period under report, an amount of Rs. 600/to two cases in Bhilwara, Rajasthan and Rs. 700/- to two dependents of the deceased in Karma, Bhiar, was paid under this Scheme.

Arrangements continued for the treatment of mica miners of Bihar suffering from Leprosy at the Tetulmari Leprosy Hospital. For the treatment of mica miners suffering from cancer, arrangements continued at the Central Hospital, Kalla (Assansol), and for mental diseases at the Mental Hospital, Kanke, Ranchi. Under the scheme for the treatment of mica miners suffering from cancer, reservation of beds in a hospital have been allowed which provides free treatment generally for a period not exceeding 9 months and in exceptional cases, this period can be more than 9 months if the treating medical authority so desire.

The non-entitled patients also get treatment from the hospitals run by the Mica Mines Labour Welfare Organisation. For their treatment, Grant-in-aid is paid by the concerned State Govts. to the Fund Organisations. Spectacles are supplied to the Mica Mines Workers at a cost not exceeding Rs. 30/per pair of spectacles.

(B) Educational and Recreational facilities

For providing educational and recreational facilities to mica workers and their dependents, various Multipurpose Institutes, each comprising of an Adult Education Centre and Women's Welfare Centre, are run by the Welfare Organisations. In order to expand the Adult Education activities, Feeder and Adult Education Centres have also been opened by the Welfare Organisations. For recreational purpose, Radio Sets have been installed in mica mining areas and recreation clubs as well as Library and reading rooms have been functioning under the Mica Mines Labour Welfare Organisations. In order to provide educational facilities, Primary Schools/Middle Schools/High Schools are run by the Welfare Organisations. The number of Institutions providing the above facilities are as under;

Sl. Particulars of No. Institutions	A.P.	Bihar	Rajas- than	Total
1 2	3	4		6
Multipurpose Institutes (with an Adult Education Centre and Women's Welfare Centre).		9	5	14
2. Adult Education Con- tre			7	7
3. Primary/Elementary Schools	4	3*		7
4. Middle Schools		4671		4
5. Hlgh Schools	2	1		3

1 2	3	4	5	6
6. Feeder Centre		1		1
 Boarding Houses/Hos- tels for miners' child- ren. 	2	4**	1	7
8. Mobile Cinema Units	1	3	1	5
 Departmental Radio Sets. 	20	16	8	44
10. Recreation Clubs	14			14
 Bhajan Mandalies 	9	9		18
12. Library & Reading Rooms.		15	10	25

- *Since transferred to the state Govt. w.e.f. 1-10-81.
- @Out of four, three have already been transferred to State Govt.
- **Amalgamated into one.

Films of educational and religious value and exhibited through a mobile cinema Unit.

Scholarships are awarded to the sons/daughters of mica miners studying in schools and colleges for their studies.

Games and Sports are organised periodically, to provide recreation to mica miners and prizes are also awarded to the winners.

(C) Drinking Water facilities:

Scarcity of drinking water is a chronic problem in mica mining areas. With a view to resolve this problem, a scheme for sinking of wells has been introduced. Under this scheme, 75% of the estimated cost or 75 per cent of the actual cost, whichever is less, is paid to the mlne owners for slnking wells. In Kalichedu village in Andhra Pradesh, a permanent water supply scheme is in vogue. The two Water Supply Schemes i.e. Talupur and Sudapuram are also under consideration. Twenty six wells in Andhra Pradesh region and 16 in Rajasthan region have been sunk so far. Forty-seven wells in Rajasthan region have also been renovated.

(D) Housing

Two schemes, viz. Build Your Own House Scheme, Low cost Housing Scheme are in vogue.

Under Build Your Own House Scheme, financial assistance to the tune of Rs. 1,500/- per tenement (Rs. 600/- in the form of subsidy and Rs. 900/- in the form of interest free loan recoverable in monthly instalments spread over a period not exceeding 9 years) is paid. 718 houses have so far been completed under this scheme.

Under Type I Housing Scheme, subsidy payable is 75% of standard estimated cost, which is Rs. 6,825/- In ordinary area and Rs. 7825 in black cotton or swelly soil area or 75% of actual cost of construction of houses, whichever is less. 20% of the subsidy is payable in advance to the mine management, with the issue of work order. 72 houses have so far been completed under this scheme.

Earlier, 98 houses were built under the Departmental colony scheme and another 12 houses under subsidized house scheme were constructed. With a view to accelerate the pace of housing programmes and to make the schemes more attractive, a Housing Sub-Committee was constituted, which has since submitted its report. This is being examined in the Ministry.

PART-III

The receipts and expenditure for the year 1980-81 are as follows:—

Receipts
Opening balance as on 1st April, 1981
Receipt during the year 1981-82
Expenditure during the year 1981-82
Closing balance as on 31st March, 1982
PART-IV

1,92,29,453.88
1,16,93,000.00
2,24,30,629.88

Estimated receipts and expenditure for the

year 1982-83

Budget Estimates
Receipts
Rependiture

[F. No. Z-16016/1/82-M. HI/W. II]

T. D. SALHOTRA, Under Secy.